चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी दूर है

पेज 3

माफ़ियाओं के शोषण से मुक्ति कब मिलेगी?

पेज 7

कोइराला के बाद नेपाली कांग्रेस का भविष्य

पेज 11

माला संस्कृति की संस्कृति

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 5 अप्रैल-11 अप्रैल 2010

आईपीएलः इंडियन फिक्सिंग लीग

सब कुछ फिक्स्ड है

[क्रिकेट खिलाड़ियों, नेताओं, मीडिया, अंडरवर्ल्ड, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों और सट्टेबाज़ी का ऐसा घालमेल इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. आरोप लगा कि आईपीएल में सब कुछ फिक्स्ड है, इसलिए पड़ताल ज़रूरी थी. इस संदर्भ में चौथी दुनिया ने कई सट्टेबाज़ों से बातचीत की. उन्होंने टी-20 क्रिकेट के पीछे चल रहे काले कारनामों के बारे में कई सनसनीख़ेज़ जानकारियां दी हैं, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे. अफसोस की बात यह है कि क्रिकेट के कर्णधारों के नेतृत्व में सट्टेबाज़ी के धंधे का औद्योगीकरण हो गया है. इस रिपोर्ट का मक़सद किसी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालना नहीं है, बल्कि क्रिकेट को चाहने वाली भारत की जनता को आगाह करना है कि उसकी भावनाओं के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है.]

आदित्य पूजन

महाभारत युग में द्रौपदी का चीरहरण कोई अतिश्योक्ति नहीं, बल्कि समाज का एक आईना था, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वास्तविक प्रतिबिंब था. यह बात किसी से छुपी नहीं है कि धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर भी जुए के बड़े शौक़ीन थे. जब इंसान की आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश में वह अक्सर ऐसे कामों को भी सही ठहराने की कोशिश करने लगता है, जो नैतिकता के तराज़ू पर खरे नहीं उतरते. खेल की दुनिया अब दूध की धुली नहीं है और भारत इसका अगला ठिकाना है. यदि कौरव और पांडव के बीच पासों का खेल फिक्स हो सकता है, तो क्रिकेट क्यों नहीं. और, क्रिकेट में फिक्सिंग का खेल तो अब कॉरपोरेट का रूप लेता जा रहा है. पहले इस खेल में अंडरवर्ल्ड, सट्टेबाज़ और कुछ पूर्व खिलाड़ी शामिल होते थे, लेकिन अब तो ख़ुद क्रिकेट बोर्ड ही इसका एक हिस्सा बन चुका है. कुछ उदाहरण देखें:

वर्ष 1997, वेस्टइंडीज और भारत के बीच कैरीबियाई देश में खेला गया टेस्ट मैच. जीतने के लिए भारत को मैच की चौथी पारी में केवल 124 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन पूरी भारतीय टीम केवल 98 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. सट्टा बाज़ार में भारत की जीत के लिए हर एक रुपये पर 40 रुपये का दांव लगा था, फिर भी टीम हार गई. टीम में शामिल छह खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये मिले और दो पूर्व खिलाड़ियों को 50-50 लाख. मुक़ाबले को फिक्स करने में अहमदाबाद और दुबई में बैठे सट्टेबाज़ों का बड़ा योगदान था. भारत में ख़ूब हल्ला-हंगामा हुआ. बीसीसीआई में सक्रिय बोर्ड के एक पूर्व अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन बोर्ड के तत्कालीन कर्ताधर्ता चुपचाप बैठे रहे. उनके चुप रहने की वजह क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है.

शारजाह को मैच फिक्सिंग का गढ़ माना जाता है. एक ज़माना था, जब भारतीय खिलाड़ी शारजाह जाकर खेलने के लिए हमेशा आतुर रहते थे. एक सट्टेबाज़ के मुताबिक़, फिक्सिंग की दुनिया में बीसीसीआई के एक पूर्व अध्यक्ष, एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुखिया और श्रीलंका क्रिकेट के एक शीर्ष अधिकारी की तिकड़ी को लोग अभी भी याद करते हैं. एक बार ऐसा हुआ कि शारजाह में हुए एक मुक़ाबले में इस तिकड़ी को 2 मिलियन डॉलर का नुक़सान उठाना पड़ा. वजह, भारतीय टीम मुक़ाबला जीतने में कामयाब रही थी और टीम में नए शामिल हुए दो बल्लेबाज़ों ने यह कारनामा कर दिखाया था. लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई. इस सट्टेबाज़ ने यह भी बताया कि मैच के बाद कोलकाता में इन तीनों ने एक मीटिंग की, जिसमें श्रीलंका टीम के एक पूर्व बल्लेबाज़ भी शामिल थे. इस बैठक में यह तय किया गया कि नुक़सान की भरपाई के लिए भारत और श्रीलंका की टीमों को क्रमशः एक और दो मैच गंवाने होंगे.

मैच फिक्सिंग का खेल सिर्फ़ भारत, पाकिस्तान और शारजाह तक ही सीमित नहीं है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों तक सटोरियों का दबदबा है. मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की दुश्मनी जगज़ाहिर है, लेकिन इनके बीच होने वाले मैचों का हाल भी एशियाई उपमहाद्वीप के मैचों जैसा ही है. मैच फिक्सिंग के कई उदाहरण यहां भी मिलते हैं. वर्ष 1998 में इन दोनों देशों के बीच खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है. ख़बरों पर भरोसा करें तो इस मुक़ाबले से पहले एक विदेशी व्यवसायी हॉर्स रेसिंग और जुए में 15 मिलियन की राशि हार चुका था. उसे अपने नुक़सान की भरपाई करनी थी और इसके लिए उसने क्रिकेट को चुना. खिलाड़ियों ने वही किया, जो उन्हें उस व्यवसायी ने कहा. मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को केवल 176 रन चाहिए थे और डेढ़ दिन का खेल अभी बाक़ी था, लेकिन पूरी टीम केवल 153 रनों पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया. ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए एक रुपये पर 80 रुपये का दांव लगा था. मैच ख़त्म हुआ और उक्त व्यवसायी को 25 मिलियन का मुनाफ़ा हुआ. फिर भी लोग यही कहते हैं कि फिक्सिंग का खेल केवल भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में ही खेला जाता है.

इसके अलावा क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई मैच दर्ज़ हैं, जो सट्टेबाज़ों की वजह से सुर्ख़ियों में रहे हैं. 1999 के विश्वकप में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की हार हो या फिर चैंपियंस ट्राफी, 2000 में भारतीय टीम का फाइनल तक का सफर हो या फिर विश्व कप-2003 में टीम इंडिया का फाइनल में जगह बनाना, क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच इन सभी मुक़ाबलों पर मैच फिक्सिंग का काला साया भी लगातार अपना असर छोड़ता रहा है. पाकिस्तानी टीम की हार के पीछे की कहानी तो यह है कि ख़ुद खिलाड़ी ही अपनी हार के लिए दांव लगाते हैं. आप कप्तान के रूप में सौरव गांगुली की कितनी भी प्रशंसा क्यों न करें, लेकिन इसके पीछे बंगाल लॉबी की छुपी ताक़त का अंदाज़ा शायद ही आपको हो. बीच में तो हालत ऐसी हो गई थी कि सौरव गांगुली को टीम से बाहर करने पर कोलकाता के क्रिकेट प्रेमी बवाल कर देते थे और चयनकर्ताओं को दोबारा सोचना पड़ता था.

पिछले कुछ सालों से टी-20 क्रिकेट की लोकप्रियता ने गेंद और बल्ले के इस खेल को नया आयाम दिया है, लेकिन हैरत की बात है कि सट्टेबाज़ी के रोग से यह भी अछूता नहीं है. सच तो यह है कि टी-20 का ताबड़तोड़ अंदाज़ और उसके पीछे छुपी अनिश्चितता सट्टेबाज़ी के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है. टी-20 की लोकप्रियता ने क्रिकेट में लीग कल्चर को बढ़ावा दिया तो आईपीएल बॉलीवुड और उद्योग जगत को क्रिकेट के साथ जोड़कर कामयाबी की नई इबारतें लिख रहा है. लेकिन इसके साथ ही इसने खेल में सट्टेबाज़ी को भी उद्योग का दर्ज़ा दिला दिया है. यहां राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं नहीं होतीं, खिलाड़ी टीम फ्रेंचाइजी के स्टाफ भर होते हैं और उन्हें वही करना होता है, जो मालिक की इच्छा होती है. आईपीएल में केवल खिलाड़ियों की ही ख़रीद-फरोख्त नहीं होती, बल्कि यहां तो मालिक से लेकर पूरा कुनबा ही बिकने के लिए तैयार है. एक सट्टेबाज़ के मुताबिक़, आईपीएल से जुड़ी बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती और उद्योग जगत की एक मशहूर शख़्सियत मैदान पर तो अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाहर ख़ुद अपनी टीम की हार के लिए दांव लगाने से भी नहीं चूकते. और, उनका साथ देते हैं लीग के ही एक सर्वशक्तिमान अधिकारी और बीसीसीआई में उनके आका.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बेहुरिया से पहले ओएनजीसी के सुबीर राहा और गेल के प्रशांत बनर्जी भी ऐसे हालात में ही सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर हुए थे.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

अंत भला तो सब भला

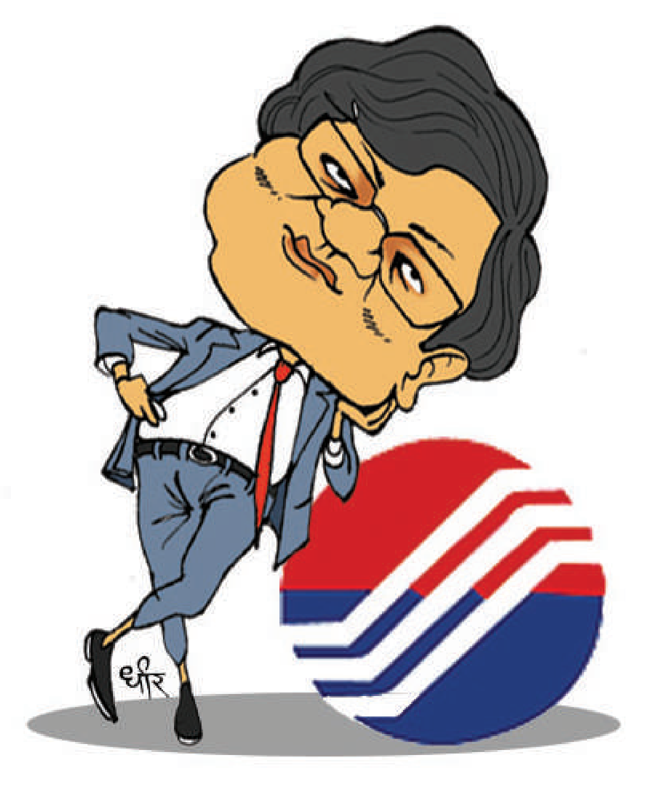

भारतीय तेल निगम (आईओसी) के चेयरमैन पद से पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए सार्थक बेहुरिया ने एक दूसरे संयुक्त उपक्रम पेट्रोनेट एलएनजी के सलाहकार के रूप में अपनी नई पारी शुरू की है. इससे पहले बेहुरिया को सेवा विस्तार देने से इंकार कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें जिस पद पर बिठाया गया है, वह पहले था ही नहीं. स्वाभाविक रूप से लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छुपी कहानी को अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं.

सूत्रों के हवाले से मिली ख़बर पर भरोसा करें तो साल 2006 से अब तक यह तीसरा ऐसा मौका है जब किसी नवरत्न कंपनी के प्रमुख को सेवा विस्तार देने से इंकार किया गया. बेहुरिया से पहले ओएनजीसी के सुबीर राहा और गेल के प्रशांत बनर्जी भी ऐसे हालात में ही सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर हुए थे. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आईओसी में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बेहुरिया को बाहर का रास्ता दिखाया गया. रोचक बात यह भी है कि बेहुरिया के लिए नए पद का सृजन किसी और ने नहीं, बल्कि ख़ुद एस सुंदरेशन ने किया जो पेट्रोनेट के चेयरमैन होने के अलावा पेट्रोलियम सचिव भी हैं. अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बेहुरिया पेट्रोनेट के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन सकते हैं. फ़िलहाल इस पद पर काम कर रहे पी दासगुप्ता इसी साल अगस्त में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसके बाद बेहुरिया को यह ज़िम्मेदारी दी जा सकती है. किसी ने ठीक ही कहा है, अंत भला तो सब भला. कम से कम हम तो यही दुआ करेंगे.

शीर्ष पुलिस अधिकारी मुश्किल में

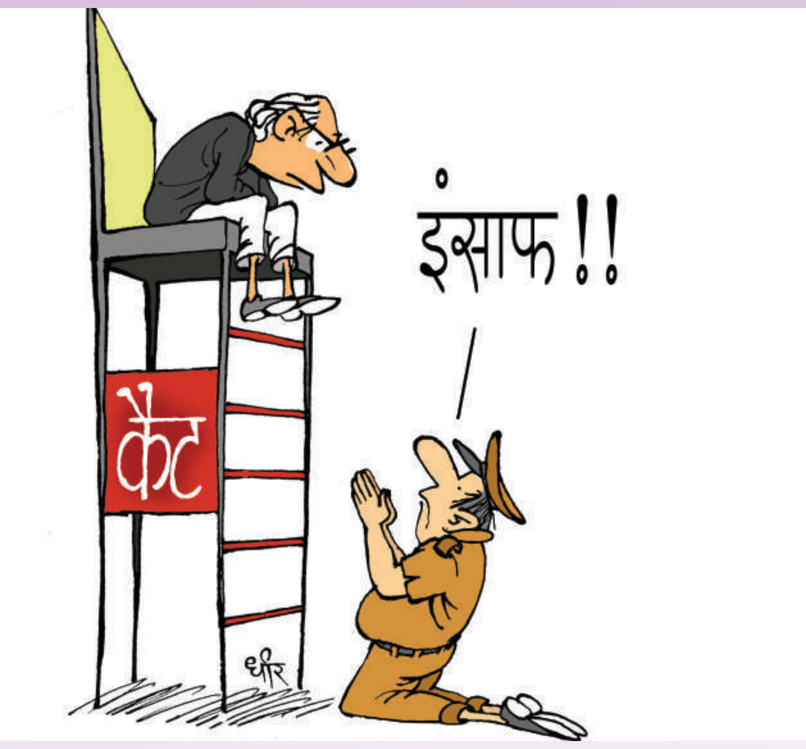

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार फिर टकराव के रास्ते पर हैं. आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री पी चिदंबरम की प्रशंसा करने के बावजूद मोदी के साथ गृह मंत्रालय के तल्ख रिश्तों में कोई कमी नहीं आई है. राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के स्थानांतरण के मुद्दे पर दोनों के बीच हो रही खींचतान तो यही कहानी बयां करती है.

कभी गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख रहे कुलदीप शर्मा के सितारे आजकल गर्दिश में हैं. वजह, उन्होंने मोदी के कहे मुताबिक़ काम करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है. इतना ही नहीं, मोदी प्रशासन अब शर्मा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने संबंधी आदेश को मानने से भी इंकार कर रहा है. हैरान-परेशान शर्मा अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की शरण में गए हैं. उनकी शिक़ायत है कि निष्पक्षता के साथ काम करने के कारण राज्य प्रशासन उन्हें बेवजह निशाने पर ले रहा है.

हालांकि, शर्मा अकेले ऐसे वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं जो मोदी सरकार के रवैये से ख़फ़ा हैं. दरअसल, मोदी राज राज्य में ऐसे नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने से इंकार करने वाले अधिकारियों को अक्सर सरकार का कोपभाजन बनना पड़ता है. और मोदी एवं केंद्र के बीच यह ताजा धींगामुश्ती तो लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का नया अध्याय भर है. बेचारे अधिकारी इसमें लकड़ी के साथ पिसने वाला घुन बनने को मजबूर हैं.

सब कुछ फिक्स्ड है

पृष्ठ एक का शेष

तीन साल पहले जी समूह ने इंडियन क्रिकेट लीग (आईसीएल) की शुरुआत की. जी समूह ने अपनी टीमों में कई देशों के खिलाड़ियों को शामिल किया तो पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव भी उसके साथ हो लिए. यही कारण है कि कपिल देव ने भी ख़ुद को इससे लगभग अलग कर लिया. यह तो भला हो एकाध टीवी न्यूज़ चैनलों का, जिन्होंने कपिल देव को इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए बुलाकर उन्हें थोड़ी-बहुत इज़्ज़त बख्शी है. इसके बावजूद इंडियन क्रिकेट लीग को न तो बीसीसीआई और न ही आईसीसी की मान्यता मिली, क्योंकि बीसीसीआई आईसीएल को तबाह करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तैयारी शुरू कर चुका था.

आठ टीमें, फ़िल्म स्टार्स, चीयरगर्ल्स, पुरज़ोर मार्केटिंग. प्रायोजक राशि इतनी कि लोगों का सिर चकरा जाए. बॉलीवुड के सितारे, मॉडल, राजनीति के खिलाड़ी और बड़ी-बड़ी ब्रांडिंग कंपनियां इस महा आयोजन के लिए एक साथ जमा हुए. हर टीम ने दस साल के लिए 400 से 600 करोड़ रुपये की राशि अदा की. आकलन के मुताबिक़, केवल तीन सालों में टेलीविज़न अधिकार, स्पांसरशिप और गेट फीस से वे इस रकम की भरपाई करने में कामयाब हो जाएंगे. कुछ दिन पहले आईपीएल में दो टीमों की बढ़ोतरी हुई. पुणे और कोच्चि की टीमों की क़ीमत बाक़ी आठ टीमों की कुल क़ीमत से भी ज़्यादा है. अब इन दोनों टीमों को फ़ायदा कैसे होगा, यह सवाल अहम है. ख़बरें आ रही हैं कि पुणे की टीम की फ्रेंजाइजी लेने के बाद सहारा समूह टीम इंडिया की आधिकारिक स्पांसरशिप से हटने पर विचार कर रहा है. अगर क्रिकेट सिर्फ़ ब्रांड बिल्डिंग की बात होती तो सहारा समूह टीम इंडिया का प्रतिष्ठित प्रायोजक बनने के बजाय पुणे की टीम तक सिमट कर क्यों रह जाना चाहता है. इसका जवाब कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट या ब्रांड प्लानर नहीं दे सकता. इसका जवाब हमें कुछ सट्टेबाज़ों ने दिया. उन्होंने बताया कि पैसे का असली स्रोत तो फिक्सिंग है. ब्रांडिंग और टीवी पर आने वाले प्रचार बस दिखावा भर हैं.

इन सट्टेबाज़ों की बातों पर कितना विश्वास किया जाए, यह कहना तो मुश्किल है. उनकी बातें सौ फ़ीसदी सही हों, यह भी नहीं माना जा सकता और न ही हम ऐसा दावा करते हैं कि इन सटोरियों ने जो कुछ बताया है, वह पूरी तरह सही है. लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने जो सवाल उठाए, वे ग़ौर करने लायक़ ज़रूर हैं.

आईपीएल-1

टूर्नामेंट में सबसे कमज़ोर समझी जाने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स अंत में विजेता बनी. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले रॉयल्स की जीत पर एक रुपये पर 25 रुपये का दांव लगा था. हर किसी ने शेनवॉर्न की नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ़ की. रॉयल्स जीत गए. और, इसके साथ ही बीसीसीआई के छह शीर्ष अधिकारी, आईपीएल के एक शीर्ष अधिकारी एवं टीम के मालिक भी जीते. इनमें से हरेक की जेब में 40-80 करोड़ रुपये पहुंच गए. टूर्नामेंट के 35 दिनों के दौरान 50,000 करोड़ से ज़्यादा के सट्टे का खेल खेला गया. लीग की शुरुआत होने से पहले डेक्कन चार्जर्स और रॉयल चैलेंजर्स की टीमों को ख़िताब के सबसे बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अंक तालिका में दोनों टीमें आख़िरी दो स्थानों पर रहीं. क्रिकेट का यह नया स्वरूप अनोखा भले हो, लेकिन यह लगातार चलने वाला है.

आरोप तो यहां तक लगा कि आईपीएल के अनेक शीर्ष अधिकारियों और ख़ासतौर से इसके एक बड़े अधिकारी को ही अकेले 200 करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ. पर इस ख़बर के आने के बाद भी जांच के लिए किसी की भी आवाज़ नहीं उठी. किसी को कानोंकान ख़बर भी नहीं हुई, कोई जांच नहीं, कोई हो-हल्ला नहीं. आख़िर हो भी तो कैसे? जब सटोरियों की टोली में शीर्ष राजनीतिक दलों के नेताओं के भी शामिल होने की बात होने लगे, तो फिर जांच का सवाल ही नहीं उठता. यह भी कहा गया कि इन नेताओं को अपना काला धन भारत में बनाए रखने के लिए एक नया और मनचाहा ज़रिया इसके माध्यम से मिल गया था.

INDIAN PREMIER LEAGUE

आईपीएल-2

सुरक्षा कारणों से इस बार यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया. रॉयल चैलेंजर्स ने नया कप्तान नियुक्त किया. सट्टा बाज़ार के मुताबिक़, बैंगलोर और डेक्कन चार्जर्स की टीमें खिताबी दौड़ में सबसे पीछे थीं. मैच का परिणाम क्या हो, इसका फ़ैसला लीग के अधिकारियों और टीमों के मालिकों ने मिलकर किया. मुक़ाबलों के नतीजों को ऐसे मोड़ा गया कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाया. वैसे भी टूर्नामेंट से जुड़े प्रायोजक, बॉलीवुड के सितारे और एक्सपर्ट कमेंटेटरों की टीम आदि टीआरपी के लिए पर्याप्त थे. कोई अंदर झांक कर नहीं देखता, लेकिन अंदर की दुनिया बड़ी गंदी है. इस बार डेक्कन चार्जर्स की टीम जीती, जबकि रॉयल चैलेंजर्स उप विजेता बनी. एक बार फिर 1500 करोड़ रुपये का बंदरबांट हुआ, जिसमें से 400 करोड़ अकेले लीग अधिकारी की जेब में गए, ऐसा बताया गया. सभी टीमों को प्रायोजकों से बड़ी रकम मिल गई और आईपीएल-3 को और ज़्यादा बड़ा एवं भव्य बनाने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई.

आईपीएल-3

टूर्नामेंट जब शुरू हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीमों को सबसे फिसड्डी माना जा रहा था, लेकिन आगे चलकर अचानक ही दृश्य बदलने लगा. आप मानें या न मानें, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरे सीजन में आईपीएल पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये का सट्टा लग चुका है. पिछले साल एक बड़े फ़िल्मी सितारे की हाई प्रोफाइल टीम मैदान पर अपने प्रदर्शन से ज़्यादा दूसरे कारणों से चर्चा में रही. लेकिन उसकी टीम नैचुरली हार रही थी या उसे हारना ही था, यह बात खिलाड़ियों से ज़्यादा सट्टेबाज़ ही जानते हैं. और, यदि उनकी बातों पर भरोसा करें तो लगातार हो रही हारों के बावजूद टीम का मालिक सौ करोड़ से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने में कामयाब रहा. इसमें उसकी मदद टीम के ही एक वरिष्ठ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य ने की. ज़ाहिर है कि लीग के सर्वशक्तिमान अधिकारी उन्हें जिताने से कैसे इंकार कर सकते हैं. फिर मुंबई इंडियंस और नाइट राइडर्स पर दांव लगाना सबसे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हो सकता है. आप दो करोड़ लगाकर 80 करोड़ तक की कमाई कर सकते हैं.

सब कुछ पहले से ही तय है. मैदान के बाहर बैठे लोग तो केवल दर्शक भर हैं. टूर्नामेंट अभी अपने शुरुआती दौर में है और अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स ख़िताब की सबसे सशक्त दावेदार लगती है. लेकिन, अगले 20 दिनों में तस्वीर का रुख़ पूरी तरह बदल सकता है. बोर्ड के लोग लंदन में बैठकर दांव लगाते हैं तो बॉलीवुड के सितारे का खेल अमेरिका और दुबई से संचालित होता है. हाई प्रोफाइल उद्योगपति के सट्टे का कारोबार हांगकांग और लंदन से चलता है. रॉयल चैलेंजर्स नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतना तो किसी छुपे रुस्तम को ही है. सट्टा बाज़ार का यही नियम है, क्योंकि कमज़ोर टीम की जीत में ही सबका फ़ायदा है. लेकिन इसके पीछे छुपे सवालों का जवाब कौन देगा. क्रिकेट के प्रशंसक तो खेल के उतार-चढ़ावों में ही मगन हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि आईपीएल यानी इंडियन फिक्सिंग लीग चालू है और भारत के आम क्रिकेटप्रेमी सट्टेबाज़ों के जाल में फंस कर वैसे ही जेब से पैसा निकाल कर उनके हवाले कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स के शिकार लोग अपनी जेब का पैसा ड्रग्स व्यापारियों को देते हैं. दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अख़बार
वर्ष 2 अंक 4
दिल्ली, 5 अप्रैल-11 अप्रैल 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ज़मीनी हक़ीक़त देखकर ही प्रणव मुखर्जी ने डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लेने से इंकार कर दिया, पर ममता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है, अर्थव्यवस्था की हालत से कोई मतलब नहीं.

मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी दूर है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

ममता बनर्जी

बिमल राय

रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन की हड़बड़ी के कारण एक रोचक वाकया हो गया. 20 मार्च को महाराजा एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह के लिए अख़बारों को जो विज्ञापन जारी किया गया, उसके नक़्शे में दिल्ली को पाकिस्तान और कोलकाता को बंगाल की खाड़ी में दिखाया गया. जहां हैदराबाद है, वहां खजुराहो लिखा गया था. रेलवे की ज़मीन पर उद्योग लगाने की धकाधक घोषणाओं से ममता अपनी उद्योग विरोध छवि धोना चाहती हैं, पर कोलकाता की सड़कों पर दौड़ती किसी नैनो को देखकर भावुक बंगालियों के मन में कैसी हूक सी उठती है, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है. सिंगुर में बुझे उम्मीदों के दीये और वहां पसरे सन्नाटे की काली छाया से उबरना ममता के लिए आसान नहीं होगा. पूर्व रेलवे ने हालांकि उस विज्ञापन एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया है, पर इसमें रेलवे की लापरवाही भी साफ हो गई.

पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से ममता बनर्जी को वेटिंग रूम में बैठी मुख्यमंत्री के रूप में भले ही मान लिया गया हो, पर 10 महीने का समय बीतने के साथ ही कई नए समीकरण बनने लगे हैं, जो ममता के लिए ख़तरे की घंटी हैं. बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी एक साल का समय बाक़ी है. ज़ाहिर है, अभी चार ऋतुएं आनी हैं और आख़िरी वसंत ऋतु में तृणमूल खिलेगा ही खिलेगा, कहा नहीं जा सकता. हो सकता है, बुद्धदेव धूल झाड़ कर फिर खड़े हो जाएं और एक बार फिर लाल पताकाओं से बंगाल का लालकिला सज जाए. लोकसभा चुनावों की बढ़त बरक़रार रखने के लिए ममता कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. पिछले रेलवे बजट में ममता ने कैबिनेट के सामने 24 बड़ी रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिनमें से 14 पश्चिम बंगाल की थीं. कैबिनेट की बैठक में तब इमोशनल सीन पैदा हो गया, जब अपनी बात मनवाने के लिए ममता फूट-फूट कर रोने लगीं और आंसुओं की बाढ़ में प्रणव दादा बह गए. संभव है कि कुछ परियोजनाओं को केवल सैद्धांतिक स्वीकृति मिली हो, पर ममता ख़ुश हो गईं, इस उम्मीद में कि उनकी जनता भी ख़ुश होगी. बंगाल की ओर झुकाव की आलोचना हुई तो ममता ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी में रेल वैगन कारखाने लगाने के प्रस्तावों को गिनाकर बचाव किया. पर दाई से पेट छिपाने वाली कहावत की तरह कोई भी देख सकता है कि उन्होंने रेल पर सवार होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की है. बाक़ी सब छोड़िए, योजना ख़र्च देखिए. रेलवे का कुल योजना ख़र्च 41426 करोड़ का है, जिसमें से 39000 करोड़ बंगाल की परियोजनाओं पर ख़र्च किया जाना है. इसके अलावा राज्य में 8200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं. सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद के समय से ही रेल किराए नहीं बढ़ रहे हैं, ममता ने भी नहीं बढ़ाया. पर सवाल है कि परियोजनाओं के लिए पैसा आएगा कहां से? क्या ज़्यादातर को योजना आयोग से मंजूरी मिल पाएगी?

ज़मीनी हक़ीक़त देखकर ही प्रणव मुखर्जी ने डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लेने से इंकार कर दिया, पर ममता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है, अर्थव्यवस्था की हालत से कोई मतलब नहीं. तभी तो अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने आंसू बहाने जैसे तिरिया चरित्तर का सहारा लिया. ममता में इतनी राजनीतिक चतुराई नहीं है कि वह बजट में बिहार और राजस्थान का भी थोड़ा ध्यान रखतीं, जहां के लोग बंगाल के हिंदीभाषियों में दो-तिहाई से भी ज़्यादा हैं. ममता लालू की मुखर विरोधी रही हैं और उन्होंने श्वेतपत्र लाकर यह साबित करने की भी कोशिश की कि रेलवे के कायाकल्प के दावे पूरी तरह सच नहीं हैं. पर उन्हें नहीं मालूम, लालू (और साथ में राबड़ी) ने बिहार का भले ही बेड़ा गर्क किया हो, पर रेलमंत्री के तौर पर उनकी लोकप्रियता बरक़रार है. ममता को रवींद्र नाथ टैगोर याद आए, उनके नाम पर ट्रेन चलाने की घोषणा हुई. कोलकाता मेट्रो के सारे स्टेशनों के नाम बंगाल के मनीषियों के नाम पर रख दिए गए हैं. पर उन्हें नहीं लगा कि महाराणा प्रताप, राजेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर या नेपालियों के आदि कवि भानु के नाम पर भी किसी स्टेशन का नामकरण किया जाए. तृणमूल के मां, माटी और मानुष के नारे से भी हिंदीभाषियों को थोड़ा खटका लग रहा है और लोग सोच रहे हैं कि यह महाराष्ट्र के मराठी मानुष की तर्ज वाला कोई नारा तो नहीं है.

वैसे हिंदीभाषियों की उपेक्षा या अपमान राजनीतिक रूप से किस कदर नुक़सानदेह है, इसकी एक छोटी सी मिसाल देखें कि कोलकाता में गंदगी बिहार के लोग ही फैलाते हैं, कहने वाले तृणमूल नेता सुब्रत मुखर्जी पिछले आठ सालों से कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं. पिछले लोकसभा चुनावों में उन्हें बांकुड़ा से टिकट दिया गया, पर वहां से भी पराजय ही हाथ लगी.

उद्योगों के लिए ज़मीन अधिग्रहण के विवादास्पद मामले से निपटने का विश्वास ममता को इसलिए है कि ज़मीन रेलवे की ही होगी. केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के अलावा 41 में से 9 अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज बंगाल में खोले जाने हैं. 94 आदर्श स्टेशनों में से 32 बंगाल के हैं. क्यों भाई! बंगाल के इतने स्टेशनों को आदर्श बनाने की ऐसी भी क्या ज़रूरत है? रवींद्र नाथ टैगोर के नाम पर हावड़ा एवं बोलपुर में दो संग्रहालय और हावड़ा में ही शंभु मित्रा सांस्कृतिक केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है. पूछा जा सकता है कि इनसे महंगाई और बेरोज़गारी से त्रस्त आम जनता को सच में क्या फ़ायदा होगा?

कोलकाता मेट्रो रेल के विस्तार पर क़रीब 100 करोड़ का ख़र्च आने वाला है. भारी घाटे में चल रही सर्कुलर रेल (कोलकाता के चारों तरफ़ चलने वाली रेल सेवा) का भी विस्तार होगा. एक दर्ज़न दुरंत ट्रेनें चलने वाली हैं, जिनमें पांच बंगाल से खुलेंगी. ऑफ सीजन में इन ट्रेनों की कितनी सीटें भरेंगी, यह देखने की बात होगी, क्योंकि इनमें बीच के स्टेशनों के यात्री सवार नहीं हो सकेंगे. महिलाओं के लिए विशेष ट्रेन चलाना भी रेलवे की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं लग रहा है. मुंबई को छोड़ दें तो कोलकाता में इन्हें घाटे में चलना ही चलना है. महिला ट्रेनों में लगभग आधी जगह खाली जा रही है. ज्यादा बुद्धिमानी होती, अगर सामान्य ट्रेनों में ही एक-दो महिला डिब्बे और जोड़े जाते. हरिपुर के परमाणु संयंत्र का भी ममता विरोध कर रही हैं और जहां भी भूमि का अधिग्रहण होना है, उस उद्योग को वह सहमति नहीं दे रही हैं. तो उनके सत्ता में आने पर क्या केवल रेलवे की जमीन पर ही उद्योग लगेंगे? सरकारी घोषणाओं के बारे एक आम राय रहती है कि इनमें से ज्यादा पूरी नहीं होतीं. ममता अगर सोच लेती हैं कि इन घोषणाओं से जनता उन्हें विकास का पुरोधा मान लेगी तो यह उनकी खुशफहमी ही होगी. ममता की सबसे बड़ी समस्या उनका ढुलमुल रवैया है. उनके पास अपना कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है. कई महत्वपूर्ण मसलों पर साफ राय नहीं है. वह विचारों की पटरी बदलती रहती हैं. महिला आरक्षण विधेयक को ही लें. जिन महिलाओं का दिल जीतने के लिए उन्होंने रेल बजट में महिला स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उन्हीं महिलाओं की किस्मत बदलने वाले विधेयक पर उन्होंने वोटिंग का बॉयकाट किया. इस मुद्दे पर साफ कहिए तो मुस्लिम वोटों के लोभ में वह मुलायम और लालू के साथ हो गईं. क्या बंगाल की महिलाएं इस बदलाव पर निगाह नहीं डालेंगी? इसके पहले भी मुस्लिम वोटों के फैक्टर को देखते हुए ममता बारी-बारी से कभी भाजपा से तो कभी कांग्रेस से चुनावी गठबंधन करती रही हैं.

इस तरह गठबंधन धर्म के पालन में भी ममता को 10 में से 4 नंबर ही मिलेंगे. पिछले लोकसभा चुनावों में सीटें देने के मामले पर उन्होंने कांग्रेस को खून के आंसू रुलाया. दक्षिण बंगाल से तो उन्होंने पंजे को घुमाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया. अभी कुछ माह पहले सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में मेयर की कुर्सी को लेकर ममता के अड़ियल रवैये ने कांग्रेस को माकपा का समर्थन लेने पर मजबूर किया. कांग्रेस से मनमुटाव की एक ताजा मिसाल तब दिखी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मालदा दौरा टल गया. हुआ यह कि गनी खान के नाम पर बनने वाले इंजीनियरिंग संस्थान के आधारशिला समारोह में उनके परिवार वालों ने ममता को निमंत्रित नहीं किया था. कुछ महीनों बाद राज्य में 86 नगरपालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं और ममता मोल-तोल में लग गई हैं. पर कांग्रेस के नेताओं ने भी ठान लिया है कि वे अब ममता के आगे नहीं झुकेंगे. दीपा दासमुंशी और अधीर चौधरी ने अभी से बयानबाजी शुरू कर दी है. देखिए टकराव की नौबत आती है या मामला आराम से सुलट जाता है.

पार्टी के संचालन के मामले में मायावती के नक्शेकदम पर चलती हैं ममता. आंतरिक लोकतंत्र का घनघोर अभाव है. सच तो यह है कि ममता पार्टी में नंबर दो का कोई प्रावधान नहीं रखना चाहतीं. कुछ माह पहले उन्होंने पार्टी के सांसद एवं गायक कबीर सुमन को पार्टी में अतिथि कहकर संबोधित किया था. पिछले साल नवंबर में सांसद कोष के पैसे के उपयोग पर पार्टी के स्थानीय नेताओं की दखलंदाजी के खिलाफ इस संवेदनशील कलाकार ने बगावत का बिगुल बजा दिया था. जनवरी में उन्होंने पुलिस अत्याचार के खिलाफ बनी आदिवासियों की समिति के मुखिया छत्रधर महतो की रिहाई की मांग करते हुए अपने माओवादी थीम वाले गीतों की सीडी जारी की. यही नहीं, ममता से बिना पूछे उन्होंने माओवादियों से वार्ता में मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया. अब तो वह ममता को उन्हें पार्टी से निकालने की चुनौती दे रहे हैं. 21 मार्च को ही माओवादियों के खिलाफ ममता के ढुलमुल रवैये से नाराज कबीर ने अपनी ही पार्टी पर माकपा की ही तरह भ्रष्टाचार और हत्या की राजनीति करने का आरोप लगाया है. उनके साथ लेखिका महाश्वेता देवी हैं, जो कभी ममता के साथ थीं. इस तरह ममता का बुद्धिजीवियों से प्रेमालाप भी बंद हो गया है.

जैसा कि द टेलीग्राफ के एसोसिएट एडिटर रशीद किदवई ने चौथी दुनिया को बताया, केंद्र में कोटे के मुताबिक, ममता 2-3 काबीना मंत्री बनवा सकती थीं, पर उन्होंने केवल खुद को ही इस दर्जे में रखा. जैसे कि पार्टी का कोई दूसरा नेता इस काबिल ही नहीं था. जहां तक कांग्रेस से रिश्ते का सवाल है, ममता को समझना चाहिए कि ट्रेन के पिछले डिब्बों की भी अहमियत कम नहीं होती.

तृणमूल के कुछ मंत्रियों ने शिकायत की है कि उनके मंत्रालयों के अफसर उन्हें भाव नहीं देते. पर दीदी क्या करेंगी, उन्होंने ही तो मंत्रियों को महीने में 15-20 दिन बंगाल में गुजारने को कहा है. लोकसभा चुनावों के बाद से पैदा हुए घनघोर संकट की इस घड़ी में माकपा क्रिकेटर धोनी की तरह कूल रहकर फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में है. हालांकि पार्टी लोकप्रियतावाद में यकीन नहीं रखती, पर चुनाव करीब आने पर करुणानिधि की तरह उपहार बांटने से लेकर दूसरे तरह के लोकप्रियतावर्द्धक कदम उठा सकती है. हम देख चुके हैं कि राज्य में औद्योगिकीकरण की गति तेज करने के लिए उसने मार्क्सवादी सिद्धांतों की बलि दी थी. वाममोर्चा सरकार ने ममता के बंगाली रेल बजट के मुकाबले में 22 मार्च को पेश राज्य के बजट को मनभावन रखने की कोशिश की है. कोशिश इसलिए कहेंगे कि ममता की तरह वाममोर्चा के पास कोई पैसे वाला दादा (वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी) नहीं है. सरकार ने बैक फायर करने वाली औद्योगिक नीति को गुडबॉय बोल दिया है और वह फिर से किसानों एवं गरीब तबके के लोगों को लुभाने के कदम उठा रही है. उसने राज्य के पिछड़े मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों की बहाली भी. अपने कैडरों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी पार्टी कई तरह के कार्यक्रम चला रही है और जमीनी स्तर पर जनता की नाराजगी दूर करने के लिए जनसंपर्क चल रहा है. चुनाव तक हर हालत में विवादास्पद मसलों में हाथ न डालने की भी रणनीति पार्टी ने बनाई है. सरकार समय पर चुनाव कराना चाहती है. राज्य के मछली पालन मंत्री एवं सोशलिस्ट पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने दो बार कहा है कि इस गठबंधन को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए. हालांकि माकपा की रणनीति यह है कि चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में ही कराए जाएं और इस बीच ममता की संभावित गलतियों का फायदा उठाया जाए. कॉमरेडों को उम्मीद है कि चुनावों में दिखी ममता लहर मई 2011 तक जरूर धीमी पड़ जाएगी. मालूम हो कि केवल 1991 में चुनावी खर्च बचाने के लिए विधानसभा चुनाव एक साल पहले लोकसभा चुनावों के साथ कराए गए थे. समय के साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर बदलाव का भी एक आधार होता है. माकपा की दुर्गति ज्यादातर नकारात्मक वोटों की वजह से दिखी है, पर एक साल बाद लाल किले में सेंध लगाने के लिए ममता को जनता का विश्वास जीतना होगा, तभी उनका मां, माटी और मानुष का नारा कारगर हो सकेगा.

feedback@chauthiduniya.com

बुद्धदेव भट्टाचार्य

कबीर सुमन

भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने भी राज्य के पूर्व सैनिकों की भावना का सम्मान करते हुए अवकाश प्राप्त जनरल खंडूरी को सूबे की सत्ता की कमान सौंप कर देश के सैनिकों को एक संदेश देते हुए सैन्य परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया.

दिल्ली, 5 अप्रैल–11 अप्रैल 2010

चौथी दुनिया

सियासी तैयारियों का केंद्र बन रहा है उत्तर प्रदेश

अजय कुमार

राजनेताओं की अचानक बढ़ी चहलक़दमी से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. दरअसल यह तैयारी आने वाले 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए है. कांग्रेस ने तो लोकसभा चुनाव के बाद ही राहुल गांधी के नेतृत्व में मिशन 2012 पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन बसपा ने 15 मार्च 2010 की महारैली में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर कांग्रेस, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के कथित दुष्प्रचार से सतर्क रहने की हिदायत देते हुए तैयारी का संकेत दिया है. इसका अर्थ है कि दोनों तरफ़ से पुरजोर तैयारी आरंभ हो गई है.

दलित वोटरों पर मायावती को अटूट विश्वास दिखता तो है, पर यही विश्वास उन्हें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के उनके इस वोट बैंक पर प्रभाव बढ़ाने के कारण टूटने भी लगता है. उन्होंने पहले तो युवराज के दलित प्रेम को ढकोसला करार देकर दलितों को आगाह किया लेकिन जब बात नहीं बनी तो लखनऊ में महारैली के माध्यम से कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया. बसपा सुप्रीमो मायावती को दलित समाज की कमज़ोर नब्ज़ की अच्छी पहचान है. यही वजह थी कि अपनी माला रैली में माया ने भाषण के दौरान अपनी बात ऐसे पेश की जैसे पूरी दुनिया उनकी और उनके समाज की दुश्मन हो. मायावती बसपा के संस्थापक कांशीराम का हवाला देते हुए यह कहने से भी नहीं भूलतीं कि मान्यवर ने पहले ही आगाह किया था कि जैसे–जैसे बसपा की ताक़त बढ़ेगी, वैसे–वैसे बसपा विरोधी नेता बसपा को अदालती चक्करों में फंसाएंगे. इस बीच 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मायावती के लिए ज़रूर राहत की ख़बर आई कि बसपा की महारैली पर कथित रूप से दो सौ करोड़ रूपये ख़र्च करने और माया को माला पहनाए जाने की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग बेकार है.

उधर एक बार प्रदेश की सत्ता पर क़ाबिज़ रही भाजपा का हाल भी बुरा है. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश को लेकर भटकाव साफ़ दिखाई देता है. पिछड़ों की राजनीति में दख़ल रखने वाले कल्याण सिंह कभी भाजपा के एकदम क़रीब दिखने लगते हैं तो कभी उनसे दूरी बनाए रखने की कसमें खाते हैं. वरुण गांधी को लेकर भी भाजपा का द्वंद्व साफ़ झलकता है. कभी भाजपा वरुण को पीछे की कतार में खड़ा कर देती है तो कभी पार्टी को उन में यूथ भाजपा दिखने लगता है. भाजपा के लिए नई मुसीबत बाबा रामदेव बन गए हैं. उनकी शीघ्र ही एक नया राजनैतिक दल बना कर लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा से भाजपा नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई हैं.

अमर सिंह और आजम ख़ान जैसे विद्रोही नेताओं का भय सपा को सताता रहता है. जाति की राजनीति पर विश्वास करने वाले नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि 2012 के विधान सभा में कौन से मुद्दे को हथियार बनाया जाए. बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ी क़ानून–व्यवस्था से जनता हलकान है, लेकिन इन मुद्दों के साथ एक लंबी लड़ाई की तैयारी किसी पार्टी ने की नहीं है.

इस समय उत्तर प्रदेश के 28 सांसदों और 142 विधायकों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चल रहा है. दर्ज़नो तो ऐसे हैं जिन पर हत्या, लूट, तस्करी तथा गैंगस्टार जैसे आपराधिक मामले चल रहे हैं. इसमें किसी एक दल को दोषी नहीं माना जा सकता है. इस हम्माम में सभी नंगे हैं. हाल ही में संपन्न विधान परिषद के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का नज़ारा ऐसा बदला कि कुछ माह पहले तक जिन्हें पुलिस खोज रही थी, अब वे माननीय हो गए हैं.

मायावती अभी उधेड़बुन में हैं, इसलिए रोज नित्य नए–नए प्रयोग करती रहती हैं. अभी वह तय नहीं कर पा रही हैं कि उनके लिए दुश्मन नंबर एक कौन है. अबकी बार ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए गोपाल नारायण मिश्र, रामवीर उपाध्याय और ओपी त्रिपाठी के कंधों पर डाली गई है. ठाकुर वोटरों के लिए बादशाह सिंह, जयवीर व धनंजय सिंह तथा वैश्य समाज के लिए अखिलेश दास और नरेश अग्रवाल को आगे किया गया है. वैश्य समाज को ख़ुश करने के लिए ही नरेश अग्रवाल को राज्यसभा भेजा गया. उनके एजेंडे में दलित सबसे ऊपर थे और रहेंगे. माया का यह फ़ार्मूला हमेशा हिट रहता है.

सपा प्रमुख भी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ युवाओं को भी रिझाने में लगे हैं. अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना कर उन्हें राज्य की राजनीति में सक्रिय करने को इसी से जोड़ कर देखा जाता है. अमर सिंह का साथ छोड़ना नेताजी के लिए सबसे बड़ा झटका रहा, वहीं आज़म खां के हमलों से भी वह आहत रहे. कल्याण से बेमेल दोस्ती के कारण अल्पसंख्यक उन्हें शक़ की नज़रों से देखने लगे. फिर भी मुलायम के तेवर फीके नहीं पड़े हैं.

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मिशन 2012 पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमीं बार–बार नाप रहे हैं. लोकसभा चुनाव से पहले तक जहां राहुल दलित प्रेम में डूबे थे, वहीं अब उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग है. दलितों का दिल जीतने के लिए उन्होंने उनके साथ चौपाल लगाई, उनके साथ भोजन किया और रात गुजारी वहीं युवाओं को अपना बनाने के लिए वह उनसे राजनीति में आने का आग्रह कर रहे हैं. वह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर युवाओं का मन टटोलते हैं. तो युवा संगठनों और प्रोफेशनल्स से दिल के तार जोड़ते हुए भी दिख जाते हैं. वह प्रदेश भर में घूम–घूम कर युवाओं को लगातार इस बात का अहसास कराने की कोशिश करते रहते हैं कि वह उनके साथ राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि उनको राजनीति में साथ लेकर चलना चाहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

दाग़दार दामन को निशंक दबंगई से धोना चाहते हैं

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड राज्य के मुखिया डा. रमेश पोखारियाल निशंक पर जिस तरह एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे है, उससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि सूबे के मुखिया का दामन बेदाग़ नहीं है. यह बात दीगर है कि रंगमंच एवं पत्रकारिता की उपज निशंक अपने दामन पर लगे दाग़ को अपनी दबंगयी से लोकतांत्रिक रास्ते से हट कर धोने का लगातार प्रयास कर रहे है.

सूबे के मुख्यमंत्री की कार्य शैली में पूरी तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने की झलक देखी जाने लगी है. जिसके चलते निशंक की कार्यप्रणाली ने कांग्रेस और बसपा जैसे प्रमुख विपक्षी दलों के कान तो खड़े ही कर दिए है, साथ ही उनके दल के खंडूरी जैसे ईमानदार छवि के नेता भी अपनी उपेक्षा के बावजूद चुप रहने में अपनी भलाई समझ रहे है.

सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पद को अनुशासन में रह कर छोड़ा, उससे उनकी छवि एक ईमानदार और अनुशासन प्रिय सिपाही की बनी. पर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी अपनी अपनी नई टीम के गठन में खंडूरी को नज़रंदाज़ कर दिया. बताया जाता है कि गडकरी ने ऐसा निशंक के इशारे पर किया. भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी के रूप में अवकाश प्राप्त करने वाले जनरल खंडूरी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण के अपने फ़ैसले के पूर्व भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के पूर्व इस दल में ईमानदार छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा देखने के साथ सैन्यअधिकारी के सम्मान का सपना भी देखा था. अवकाश प्राप्त अधिकारियों में इसका एक अच्छा संदेश भी गया था. खंडूरी ने भी केंद्रीय मंत्री के रूप में एक ईमानदार मंत्री की छवि पेश करने के साथ सैनिक बाहुल्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी के साथ नारायण दत्त तिवारी सरकार को भी धूल चटाई थी. अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने उत्तराखंड की जनता को यह अहसास कराया कि कांग्रेस के कुशासन से कोई फौजी ही निज़ात दिला सकता है. राज्य की जनता ने उन्हीं के आह्वान पर तिवारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका.

भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने भी राज्य के पूर्व सैनिकों की भावना का सम्मान करते हुए अवकाश प्राप्त जनरल खंडूरी को सूबे की सत्ता की कमान सौंप कर देश के सैनिकों को एक संदेश देते हुए सैन्य परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया. राज्य की सत्ता संभालकर जनरल खंडूरी ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि के साथ एक अनुशासन प्रिय और कठोर शासक के रूप में दिखे. उनकी ईमानदारी राज्य के भू–माफ़ियाओं सहित सत्ता का दोहन कर काली कमाई करने वालों पर बहुत भारी पड़ी जिसके चलते वे ऐसे लोगों की आंख की किरकिरी बन गए. देश में संपन्न हुए संसदीय आम चुनाव में जहां एक ओर एनडीए सरकार के फीलगुड की हवा कांग्रेस के राहुल गांधी के हाथों निकली, वहीं राज्य की पांच सीटों पर रिश्तेदारों की मनमानी टिकट वितरण से भी भाजपा का बुरा हाल हुआ. इस चुनाव में भाजपा की हार का ठीकरा जहां जनरल के सिर फूटा, वहीं राहुल गांधी के युवा कार्ड की बल्ले–बल्ले हो गई. राजनैतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस हार के लिए अकेले खंडूरी को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. मौक़ा मिलते ही राजनीति के खिलाड़ी निशंक ने जनरल के ख़िलाफ़ बग़ावत का झंडा बुलंद करने वालों को हवा देकर राज्य से जनरल की विदाई करा दी.

डा.निशंक सरकार पर हरिद्वार महाकुंभ में सरकारी धन की खुली लूट के आरोप के साथ ही घटिया निर्माण के अरोप की क़ालिख़ अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 700 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं की खुली बिक्री का आरोप सड़क से सदन तक जड़ दिया. प्रतिपक्ष के नेता हरक सिंह रावत का आरोप है कि सरकार के मुखिया के इशारे पर शराब व्यवसायियों को बिना गुण दोष की विवेचना किए 11 परियोजनाएं आवंटित कर दी गई हैं. हरिद्वार कुंभ में कुल 571 करोड़ की 306 योजनाओं में सरकार द्वारा भारी लूट के आरोपों के कांग्रेसी नेता सीबीआई द्वारा जांच चाहते हैं.

राज्य सरकार ने सूबे में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्ज़ा दे दिया है. संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे जयराम ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी उसे संस्कृत भाषा के साथ छल किया जाना बताते हुए कहते है कि राज्य में संस्कृत से जुड़ी संस्थाओं का बुरा हाल है सरकार ऐनकेन प्रकारेण अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है. उनका कहना है कि सरकार बालू की दीवार बना कर जनता के साथ धोखा कर रही है. पिथौरागढ़ में जल के स्रोत विषैले हो चुके हैं, जनता को पीने के पानी का भारी संकट झेलना पड़ रहा है. यह इलाक़ा संसदीय कार्य मंत्री का है. यद्यपि सूबे के मुख्यमंत्री अपनी सरकार पर लगे सभी आरोपों को एक सिरे से ख़ारिज करते है, पर आग के बिना धुआं उठने का सच उन्हें बेदाग़ नहीं छोड़ रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

फोटो–प्रभात पाण्डेय

क्या डॉ. लोहिया समाजवादियों को याद हैं?

शशि शेखर

समाजवादी आंदोलन का इतिहास जुड़ने से ज़्यादा टूटने का रहा है. जिस डा. लोहिया को कांग्रेस के ख़िलाफ़ मोर्चा बनाने में जनसंघ से समझौता करने में परहेज नहीं हुआ, उसी जनसंघ के नए चेहरे भाजपा को लेकर समाजवादी खेमों में पिछले अनेक वर्षों से खींचतान मची हुई है. यह और बात है कि अनेक राजनीतिक दबावों के कारण शरद यादव और नीतीश कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को स्वीकार किया और अब बिहार या झारखंड या दूसरी जगहों पर भाजपा के साथ सरकार चलाना मंजूर किया है. डा. राम मनोहर लोहिया की जन्मशती पर आयोजित सभा में भी थोड़ी बहुत खींचतान दिखती रही. पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्य प्रकाश मालवीय ने तो सीधे सीधे प्रकाश करात, शरद यादव और ए. बी. वर्द्धन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब देश में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू हुआ तो इन नेताओं ने क्रीमी लेयर की नई थ्योरी गढ़ ली, लेकिन राज्यसभा में महिला आरक्षण के बिल के समय क्रीमी लेयर को भूल गए. उन्होंने डा. लोहिया को याद करते हुए कहा कि वे महिलाओं को बराबर का हक़ देने के पक्ष में रहते थे, पर यहां उनके अनुयायी दो खेमों में चले गए. उनका इशारा शरद यादव और नीतीश कुमार की ओर था.

कभी अगस्त क्रांति के नायकों में से एक रहे समाजवादी चिंतक डा. राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि लोग मेरी बात समझेंगे ज़रूर, पर शायद मेरे मरने के बाद. इसीलिए एक साम्यवादी(कम्युनिस्ट)नेता, प्रकाश करात यह कहते हैं कि लोहिया के सप्त क्रांतियों में स्त्री–पुरुष समानता, आर्थिक असमानता, रंग–विभेद, जाति–विभेद, शस्त्र होड़ और निजी संपत्ति जुटाने जैसे मसलों के ख़िलाफ़ आंदोलन की बात है और यदि इसके साथ सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ भी लोहिया की आवाज़ को जोड़ दें तो यह समाजवादियों और साम्यवादियों का एक साझा आंदोलन बन सकता है. करात ने यह बयान विरोध की राजनीति का झंडा बुलंद करने वाले अनेक राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने दिया. मंच पर माकपा, भाकपा, भाजपा, कांग्रेस, जद(यू), जद(एस), सपा, आरएसपी और लोजपा के सभी महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे. ऐसे मंच और ऐसे अवसर पर अगर करात ऐसी बातें कहते हैं तो निश्चित तौर पर इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ होंगे. ज़ाहिर है, यह बयान भविष्य में एक राजनीतिक विकल्प की ओर भी इशारा करता है. हालांकि, भारतीय राजनीति ने अनेक मौक़ों पर ऐसे राजनीतिक विकल्पों को बनते–टूटते देखा है. जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने लोहिया जन्मशताब्दी समागम का उदघाटन करते हुए कहा कि गांधी के बाद लोहिया ही एक ऐसे नेता रहे, जिन्होंने जनता को सबसे अधिक प्रभावित किया. हालांकि ऐसा कहते हुए शरद यादव जेपी को भूल गए क्योंकि मंच तो लोहिया का था. उन्होंने यह भी कहा कि वे ख़ुद कभी लोहिया से मिले नहीं, लेकिन उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़ कर ही लोहिया की विचारधारा पर चलने के लिए प्रभावित हो गए.

इस मौक़े पर भाकपा के ए.बी बर्धन ने कहा कि जिस तरह से ख़ुद साम्यवादी आंदोलन आज की तारीख़ में बिखरा हुआ है, कुछ वैसा ही हाल समाजवादी आंदोलन का भी है. उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत क्रांति की है, अगर कोई क्रांति नहीं होती है तो सिर्फ़ लोहिया को याद करने का क्या फ़ायदा, केवल माला पहनाने से कुछ नहीं होता. बर्धन ने समाजवादियों और साम्यवादियों को एक साथ मिल कर भारत को समाजवाद की तरफ़ ले चलने का आह्वान भी किया. आरएसपी नेता अबनी राय ने कहा कि लोहिया के नाम को आगे बढ़ाने के लिए लोहिया के काम को आगे बढ़ाना चाहिए. जस्टिस राजेंद्र सच्चर का यह कहना कि इस देश में समाजवाद और साम्यवाद को एक साथ चलना चाहिए था, दरअसल अतीत की ग़लतियों को याद कर सीख लेने जैसा ही लगता है. लेकिन समाजवादियों और साम्यवादियों एक साथ नहीं मिल पाने के लिए क्या सिर्फ़ साम्यवादियों को ही ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए? या फिर उन नेताओं को भी, जिन्होंने राजनीति तो लोहिया के नाम पर की लेकिन लोहिया के विचारों पर चलने की ज़हमत कभी नहीं उठाई. और कुछेक ने कोशिश की भी तो किनारे लगा दिए गए. छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी नेता स्व. जनेश्वर मिश्र का समाजवादी पार्टी में सम्मान तो बहुत था, लेकिन सपा की राजनीति में उनका कितना चलता था, यह सबको मालूम है.

बहरहाल, इतना तो साफ़ हो गया कि लोहिया के विचारों से सहमत न होने वालों या सहमत होकर भी उस पर न चलने वालों को भी आज लोहिया और उनकी विचारों की प्रासंगिकता समझ में आने लगी है. डा. लोहिया का वह नारा *समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ* इस बात की ताकीद करता है कि कोई राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब इसके लोगों को बराबरी का हक़ मिल जाए. आज जब 33 फ़ीसदी महिला आरक्षण या 15 फ़ीसदी अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, समर्थन और विरोध का तमाशा चल रहा है तो ऐसे मौक़े पर ख़ुद को लोहिया का चेला बताने वाले और सभी दलों के नेताओं को लोहिया के विचारों को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए.

shashishekhar@chauthiduniya.com

विश्व भर में उर्जा के उत्पादन और उसके इस्तेमाल के लिहाज़ से डब्ल्यूएसएसडी के प्रस्तावों में कई अहम बातों की चर्चा है.

जोहानेसबर्ग पृथ्वी सम्मेलन था दीर्घकालिक विकास के लिए

जस्टिस पी. सथाशिवम

दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग में जो वैश्विक सम्मेलन (डब्ल्यूएसएसडी), 2002 में हुआ था, वह मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था, हालांकि तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने उसका बहिष्कार किया था. इसीलिए उसके एजेंडे में ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उतना अहम नहीं था. इससे भी बड़ी बात यह थी कि अनेक महत्वपूर्ण फ़ैसले कहीं दूर लिए जा रहे थे. चीन और रूस, जो कि दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्रदूषण फैलाने वाले देश हैं, ने जलवायु परिवर्तन पर 1997 में हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते, क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी देने की घोषणा कर दी. इन घोषणाओं की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन इसके साथ ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण क़दम था.

यदि जोहानेसबर्ग सम्मेलन की तुलना 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से करें तो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति यह बेरुख़ी और भी सतह पर आ जाती है. रियो सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर सदस्य राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी थी. ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा साधनों के इस्तेमाल को लेकर भी अमेरिका सहमत नहीं था और यही वजह थी कि सदस्य राष्ट्र इस बाबत भी कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने में नाकाम रहे. ब्राजील सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से साल 2010 तक विश्व भर में कुल ऊर्जा के इस्तेमाल का 10 प्रतिशत ग़ैर-परंपरागत स्त्रोतों से होने का लक्ष्य रखा था और इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंवायरोन्मेंटल लॉ (सीआईईएल) का भी समर्थन हासिल था.

विश्व भर में ऊर्जा के उत्पादन और उसके इस्तेमाल के लिहाज़ से डब्ल्यूएसएसडी के प्रस्तावों में कई अहम बातों की चर्चा है. ग्लोबल वॉर्मिंग भले ही सम्मेलन के एजेंडे में शामिल न हो, लेकिन सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के दिमाग़ में यह बात ज़रूर थी. इसके द्वारा सुझाई गई योजना में उन क़दमों पर अमल किया जाना भी शामिल था, जिनकी मदद से ऊर्जा संसाधनों की निरंतर उपलब्धता और उन तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके. इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई थीं. पहली यह कि ऊर्जा के ग़ैर-परंपरागत स्त्रोतों को प्रोत्साहन और कुल उर्जा खपत में उनके योगदान को बढ़ाना और दूसरी यह कि ऊर्जा संसाधनों के सही इस्तेमाल और उनके संरक्षण की तकनीकों का विकास और विकासशील देशों तक इन तकनीकों के सुलभ हस्तांतरण को बढ़ावा. इनके अलावा बाज़ार की विसंगतियों को दूर करना जिसमें टैक्स प्रणाली में सुधार और सब्सिडियों को समाप्त करना शामिल है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अक्षय ऊर्जा से जुड़े तकनीकों के उपयोग के लिए सही वित्तीय माहौल तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना और समयबद्ध तरीक़े से क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी देना भी शामिल किया गया.

सम्मेलन के इन प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा के रूप में देखा गया था. साथ ही अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण क़ानून के विकास की दिशा क्या हो, इस पर गंभीर चर्चाएं की गई. सदस्य राष्ट्र गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के इस्तेमाल में अपने लक्ष्य से भटकें नहीं, इसके देखरेख की ज़िम्मेदारी सीआईईएल की रही है.

अब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि युनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कन्फ्रेंस, 2009 वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर आयोजित आख़िरी सम्मेलन है. इस सम्मेलन के माध्यम से पहली बार सभी प्रमुख राष्ट्रों के अलावा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली ग़ैर सरकारी संस्थाएं भी एक मंच पर आईं. हालांकि, तमाम उम्मीदों के विपरीत क्योटो प्रोटोकॉल के प्रस्तावों को सदस्य देशों के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की दिशा में यह सम्मेलन कुछ ख़ास नहीं कर पाया. इसके परिणामस्वरूप हमें अमेरिका, चीन, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोपेनहेगन समझौता देखने को मिला. इस समझौते की शर्तों को मानने के लिए सदस्य देश क़ानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं और न ही इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अगले चरण के रूप में देखा जा सकता है. ग़ौरतलब है कि क्योटो प्रोटोकॉल की मौजूदा समय सीमा 2012 में समाप्त हो रही है. सम्मेलन में इस समझौते की गूंज सुनाई पड़ी लेकिन समझौते के गुप-चुप तरीक़े को लेकर भी सवाल खड़े किए गए. कई देशों ने यह भी माना कि इस करार के चलते कोपेनहेगन सम्मेलन ऐसे किसी समझौते तक पहुंचने में नाकाम रहा, जो सदस्य राष्ट्रों की वैधानिक ज़िम्मेदारियां तय करता और ग़रीब देशों के लिए ख़ास तौर पर लाभकारी होता.

विश्व भर के देशों ने व्यापार से जुड़े अपने क़ानूनों में मनमाफ़िक ढंग से बदलाव किए हैं. ऐसे सभी कारक, जो व्यापारिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए बनाए गए थे, या तो पूरी तरह ख़त्म कर दिए गए हैं या फिर उनकी प्रभावशीलता को कम कर दिया गया है. आर्थिक नीतियों में इन बदलावों से व्यापारिक गतिविधियों में तो तेज़ी आई ही है, इसने वैश्विक व्यापार के विस्तार में पहले से ज़्यादा देशों की भागीदारी भी सुनिश्चित की है. यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित हर बातचीत में व्यापार की अधिक से अधिक चर्चा होने लगी है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी इसकी भूमिका ने चिंताओं को बढ़ाया है. इनमें से कुछ चिंताएं हैं : मुक्त व्यापार के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के अध्ययन के लिए व्यापारिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित एक मॉडल के अनुरूप नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (नाफ्टा) के पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा की गई. इस आधार पर व्यावसायिक उदारीकरण से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को तीन श्रेणियों में बांटा गया- संख्यात्मक, संरचनात्मक और तकनीकी.

आम धारणा के मुताबिक़ व्यापार के विस्तार से आर्थिक गतिविधियों में इज़ाफ़ा होता है और इससे ऊर्जा के इस्तेमाल में भी वृद्धि होती है. यदि बाक़ी चीज़ें अपने पुराने स्तर पर क़ायम रहें तो भी बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और ऊर्जा के ज़्यादा इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी होती है.

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा इस बात पर निर्भर है कि देश की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति कर रही है. यदि व्यापारिक विस्तार ऐसे क्षेत्रों में हो रहा हो जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा भी कम होगी. यही वजह है कि आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर पड़ने वाले असर के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है.

व्यापार के उदारीकरण से ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम दोहन और अपेक्षित दोहन संभव है जिससे सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा में भी कमी आ सकती है. मुक्त व्यापार की हालत में पर्यावरण पर अच्छा असर डालने वाली वस्तुओं, उत्पादों और तकनीकों की क़ीमत में कमी आएगी और उनकी उपलब्धता भी बढ़ेगी. यह उन देशों के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहां ऐसी तकनीकों एवं वस्तुओं का उत्पादन कम होता है या उनकी क़ीमत ज़्यादा है. खुला बाज़ार होने से निर्यातकों को नए उत्पादों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाले तकनीकों के विकास में भी मदद मिलती है. आर्थिक विस्तार से आय में होने वाली बढ़ोतरी समाज को अच्छे पर्यावरण की मांग के लिए भी प्रोत्साहित करता है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की संभावना बनती है.

दीर्घकालिक विकास की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण में होने वाला बदलाव ही है. इस चुनौती की गंभीरता का वास्तविक अहसास अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से ही हो सकता है. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ऐसा ही एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. यह संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुशासन और इसे मुक्त व्यापार की दिशा में मोड़ने के लिए विचार-विमर्श के एक मंच की तरह भी काम करता है. डब्ल्यूटीओ के स्थापना चार्टर में यह स्पष्ट किया गया है कि मुक्त व्यापार के साथ महत्वपूर्ण मानवीय पहलू और उद्देश्य जुड़े हैं जिनमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, दीर्घकालिक विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए वैश्विक संसाधनों का उचित इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसका संरक्षण शामिल है. बहुध्रुवीय व्यापार और पर्यावरण के मुद्दे पर दोहा में हुए सम्मेलन के माध्यम से डब्ल्यूटीओ ने चिरस्थायी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में अपने क़दम और आगे बढ़ा दिए हैं.

डब्ल्यूटीओ और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी)

डब्ल्यूटीओ और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं जो इसके नियमों से भी स्पष्ट होता है :

यूएनएफसीसी की धारा 3.5 और क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 2.3 में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए अपनाए गए तरीक़े किसी भी हालत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकते और इन्हें इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संबंधित पक्षों के सामाजिक,आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर बुरा असर नहीं पड़े. साथ ही, डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में पर्यावरण सुरक्षा के नज़रिए से व्यापारिक गतिविधियों पर कुछ शर्त लगाने की छूट भी दी गई है.

इसके साथ-साथ, इस काम से जुड़ी संस्थाएं डब्ल्यूटीओ और बहुध्रुवीय पर्यावरण समझौतों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी प्रयासरत हैं. उदाहरण के लिए, डब्ल्यूटीओ और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में कार्यरत संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग पहले ही बढ़ रहा है, जैसे यूएनएफसीसी- डब्ल्यूटीओ की व्यापार एवं पर्यावरण पर होने वाली बैठकों में शामिल होता है और यूएनएफसीसी के सम्मेलनों में भी डब्ल्यूटीओ सचिवालय की भागीदारी होती है.

व्यापार में तकनीकी बाधाओं से संबंधित समझौते पर कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड (टीबीटी) जलवायु परिवर्तन से जुड़े तकनीकी मामले के दायरे में आते हैं, जो अन्य चीज़ों के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अनावश्यक बाधाओं को दूर करने की दिशा में नियम क़ानून बनाता है. इस समझौते के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों के लिए व्यापार पर असर डालने वाली तकनीकी जानकारियों का आदान-प्रदान होना भी ज़रूरी है. टीबीटी कमिटी यह सुनिश्चित करती है कि जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए उठाए गए क़दम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के मार्ग में अनावश्यक बाधाएं नहीं खड़ी करते. पर्यावरण से संबंधित जिन तकनीकी मुद्दों पर समिति में विचार-विमर्श हुआ है, वह मुख्य रूप से उत्पादों से संबंधित है, जैसे कारों के लिए ईंधन मानक, ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल से बने उत्पादों का इको-फ्रेंडली होना, डीजल इंजन के लिए उत्सर्जन की सीमा क्या हो आदि. हाल के वर्षों में कई ऐसे मानक तय किए गए हैं जो ऊर्जा संसाधनों के सही इस्तेमाल और उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में लाभदायक हो सकते हैं.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आज की पढ़ी-लिखी मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं धर्म गुरुओं और मौलानाओं के फ़तवों की खुली मुख़ालफ़त कर रही है.

कोई नहीं रोक सकता हमें राजनीति करने से

7, JANTAR MANTAR ROAD, NEW DELHI-0001
नहीं तो
औरतें उठीं नहीं तो
NO HUMAN RIGHTS WITHOUT WOMEN'S RIGHTS

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मुसलमान औरतों का भला राजनीति में क्या काम? वे कैसे आ सकती हैं राजनीति में.अल्लाह ने औरतों को महज़ बच्चा पैदा करने के लिए ही ज़मीन पर भेजा है. उनका काम है कि वे घर बैठें और अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करें.उन्हें डाक्टर और इंजीनियर बनाएं . अच्छे नेता पैदा करें. राजनीति से वे तो दूर ही रहें वही बेहतर है.....

अपने को इस्लाम का विद्वान मानने वाले कुछ धार्मिक नेताओं के इस तरह के बयान के बाद मुसलमान महिलाओं में घोर नाराज़गी है. वे ऐसे मौलानाओं के ख़िलाफ़ गोलबंद हो चुकी हैं. उनमें से लगभग सभी चाहती हैं कि अपने को इस्लाम का प्रवक्ता समझने वालों को यह समझना चाहिए कि अब समय बदल गया है. अब मुसलमान महिलाएं भी पढ लिख रही हैं और देश के तमाम दूसरे कामों में हाथ बंटा रही हैं. ऐसे में वे राजनीति से अलग कैसे और क्यों रहें? आखिर राजनीति हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की नाईश हसन बेहद नागवारी से कहती हैं कि हम ऐसे धार्मिक नेताओं को अपना प्रवक्ता मानने से भी इंकार करते हैं. आखिर ये नेता होते कौन हैं ये तय करने वाले कि हम औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं. जंतर-मंतर पर मशहुर गीतकार जावेद अख्तर के साथ धरने पर बैठी अल्पसंख्यक जमात की इन महिलाओं के चेहरे पर रोष साफ़ नज़र आ रहा है. इनका स्पष्ट कहना है कि जो धर्म निरपेक्ष मुस्लिम नागरिक और कार्यकर्ता हैं वे कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे. क्योंकि यह महिलाओं की समानता और न्याय की दिशा में सबसे कारगर कदम है. अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो देश में ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आग़ाज़ होगा जिससे देश की मुस्लिम महिलाओं समेत सभी वहिष्कृत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी.

गीतकार जावेद अख्तर कहते हैं कि इस तरह के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना और ओछे बयानों से औरतों की गरिमा और उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होता है. ऐसे बयान न केवल महिला विरोधी, अन्यायपूर्ण और अमानवीय हैं, बल्कि भारतीय संविधान में निहित मूल भावना का उल्लंधन भी है. यहां तक कि यह ग़ैर-इस्लामी भी है. ऐसी सोच के पीछे बेहद ख़तरनाक इरादे हैं.मुसलमान औरतें समान नागरिक हैं और अपनी बात पूरी तरह से कहने में सक्षम भी हैं. जब मोहम्मद साहेब ने चौदह साल पहले मुसलमान औरतों को समाज में समान ओहदे का हक़ दे दिया था तो ये लोग कौन होते हैं ऐसी निन्दनीय बातें कर मुसलमान औरतों के वज़ूद को नकारने वाले. मुसलमान औरतों के हक़ के लिए लड़ने वाली, नीसवान नाम की संस्था की शमीम शेख कहती हैं कि यह एक साज़िश है.

ऐसा वे ही कह सकते हैं जो मुसलमान औरतों को गुलाम और बेज़ुबान बना कर रखने के आदी हो चुके हैं. हम औरतें तो सियासत के ज़रिए समाज की सेवा करना चाहती हैं. ताकि अपने देश और परिवार को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकें. पर ये चंद लोग ऐसी वाहियात बातें कर हमें रूसवा कर रहे हैं. अपनी नाराज़गी का इज़हार करने गुजरात से दिल्ली पहुंची, आएशा पठान कहती हैं कि ये धार्मिक नेता कौन होते हैं हम मुसलमान औरतों और अल्लाह ताला के बीच आने वाले ? ये हमारे और ख़ुदा के बीच का मसला है. ये हाफ़िज़ क्यों बन रहे हैं? मुसलिम महिलाओं को इस बात से कोई एतराज़ नही है कि मौज़ूदा आरक्षण बिल में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है. हम मुसलमान औरतें तो बस ये चाहती हैं कि पहले महिला आरक्षण बिल को हर सूरत में लागू किया जाए. बाकी मसले-मसाइल बाद में भी हल हो सकते हैं. क्योंकि इसी में देश की सभी महिलाओं का भला है. और मुल्क की तरक्की भी. रही बात सियासत में हमारी भागीदारी की तो वो तो हम ज़रूर करेंगे. किसी का भी विरोध हमें राजनीति में आने से नहीं रोक सकता.

रूबी अरुण
ruby@chauthiduniya.com

ये फ़तवे बेमानी हैं

महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग को शामिल करने का मुद्दा तो पहले से ही गर्म था, उस पर मदरसे से लेकर शिया धर्म गुरुओं ने अपनी डफली अपना राग की तर्ज पर राजनीति में मुस्लिम महिलाओं के आने के मुद्दे पर विरोध जताना शुरु कर दिया. शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की नज़र में महिलाओं का काम सिर्फ़ बच्चे पैदा करना है न कि राजनीति करना. दूसरी ओर, मदरसे नदवा-तुल उलेमा ने ऐलान किया कि मुस्लिम महिलाओं को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए. देवबंद दारूल उलूम ने एक क़दम आगे बढ़ कर ऐसी महिलाओं को सजा तक देने की बात कही है जो राजनीति में जाने की इच्छा रखती हैं. लेकिन, इस सब के बीच यह जानना भी ज़रूरी था कि आख़िर इन फ़तवों और धमकियों का असर कितना हो रहा है. यही जानने के लिए चौथी दुनिया ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से तालीम हासिल करने वाली मुस्लिम लड़कियों से बात की. इनसे बातचीत के बाद तो यही लगा कि ज़माना सचमुच बदल रहा है. बात हक़ की हो तो, फ़तवों और धमकियों का डर ख़त्म हो जाता है. आज की पढ़ी-लिखी मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं धर्म गुरुओं और मौलानाओं के फ़तवों की खुली मुख़ालफ़त कर रही है. ये लड़कियां पर्दा का विरोध नहीं करती तो ख़ुद के लिए भी विरोध नहीं चाहती. और तो और, बातचीत के दौरान बक़ायदा शरीया का हवाला देते हुए ये कहती है कि इस्लाम में मर्द और औरतों को बराबरी का हक़ है. जामिया विश्वविद्यालय से बायो सांइस की पढ़ाई कर रही बुशरा का कहना था कि मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ़ राजनीति बल्कि सभी क्षेत्रों में आना चाहिए. साइंस स्टुडेंट होने के नाते मैं मानती हूं कि हम लड़कियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और हमें राजनीति से लेकर सभी क्षेत्रों में जाने की सोचनी चाहिए. बुशरा यह भी कहती है कि मुस्लिम महिलाएं अपनी सीमाओं में रह कर भी राजनीति कर सकती है. ज़ाहिर है, बुशरा यह बताना चाहती हैं कि उन्हें अपनी परंपरा या रीति-रिवाज को अपनाने या उसे आगे ले जाने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन धर्म की ग़लत व्याख्या कर के कोई उनके अधिकारों का हनन भी नहीं कर सकता है. तो क्या बुशरा की यह सोच अकेली है. बिल्कुल नहीं. दरअसल, बुशरा उन मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो आज घर की दहलीज़ को पार कर चुकी है और जितना ये अपने कर्तव्यों को ले कर सजग है, उतना ही संजीदा अपने अधिकारों को ले कर भी है. इंटरनेशनल बिजनेस की स्टुडेंट रिफा बताती है कि इस्लाम में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो हम लड़कियों को राजनीति में जाने से रोकता हो. वो कहती है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं. हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं. ऐसे में यह सोच कि मुस्लिम महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, एक निहायत ही ग़लत सोच है. निश्चित तौर पर, इन लड़कियों की सोच उन धर्मगुरुओं और बात-बात पर बेवजह और बिना सोचे-समझे फ़तवा जारी करने वालों के लिए एक संदेश है कि, ज़माना बदल गया है. आगे बढ़ने के लिए परंपरा को न बदले लेकिन नज़रिया तो बदलना ही पड़ेगा. और शायद यह संदेश भी कि बदलते वक़्त में ऐसे फ़तवे बेमानी होते जा रहे हैं.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

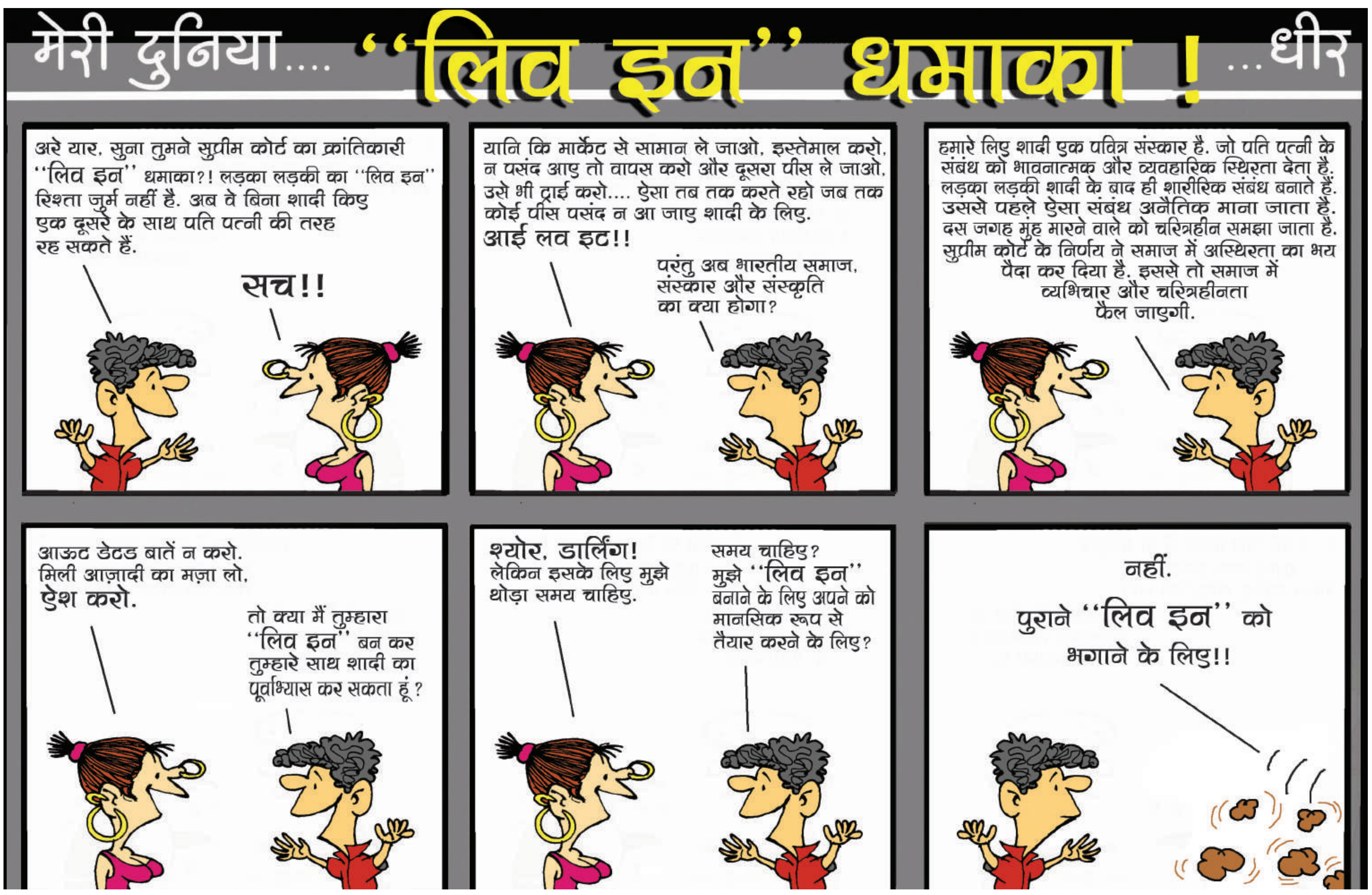
मेरी दुनिया.... "लिव इन" धमाका ! ...धीर
अरे यार. सुना तुमने सुप्रीम कोर्ट का क्रांतिकारी "लिव इन" धमाका?! लड़का लड़की का "लिव इन" रिश्ता जुर्म नहीं है. अब वे बिना शादी किए एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं.
सच!!
यानि कि मार्केट से सामान ले जाओ. इस्तेमाल करो. न पसंद आए तो वापस करो और दूसरा पीस ले जाओ. उसे भी ट्राई करो.... ऐसा तब तक करते रहो जब तक कोई पीस पसंद न आ जाए शादी के लिए. आई लव इट!!
परंतु अब भारतीय समाज, संस्कार और संस्कृति का क्या होगा?
हमारे लिए शादी एक पवित्र संस्कार है. जो पति पत्नी के संबंध को भावनात्मक और व्यवहारिक स्थिरता देता है. लड़का लड़की शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाते हैं. उससे पहले ऐसा संबंध अनैतिक माना जाता है. दस जगह मुंह मारने वाले को चरित्रहीन समझा जाता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने समाज में अस्थिरता का भय पैदा कर दिया है. इससे तो समाज में व्यभिचार और चरित्रहीनता फैल जाएगी.
आऊट डेटड बातें न करो. मिली आज़ादी का मज़ा लो. ऐश करो.
तो क्या मैं तुम्हारा "लिव इन" बन कर तुम्हारे साथ शादी का पूर्वाभ्यास कर सकता हूं?
श्योर, डार्लिंग! लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए.
समय चाहिए? मुझे "लिव इन" बनाने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए?
नहीं.
पुराने "लिव इन" को भगाने के लिए!!

1984 में जब विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक मज़दूरों की मौत हुई थी, तब तत्कालीन सांसद शरद यादव ने राज्यसभा में यह मामला उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था.

बुंदेलखंड के पत्थर खदान मज़दूरों का दर्द

माफ़ियाओं के शोषण से मुक्ति कब मिलेगी?

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पत्थर खदान इलाक़ों से कम से कम 5-6 किमी की दूरी पर आवासीय स्थान बनाए जाएं, ताकि टीबी के ख़तरे से मज़दूरों एवं उनके परिवारों को बचाया जा सके, लेकिन यहां बमुश्किल आधा-एक किलोमीटर की दूरी पर मज़दूर रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर टीबी के मरीज हैं.

सुरेंद्र अग्निहोत्री

गगनचुंबी इमारतों एवं सड़कों की ख़ूबसूरती बढ़ाने के लिए पत्थर का सीना चाक करने और नदी से बालू निकालने वाले मज़दूरों को दो जून की रोटी के बदले सिल्कोशिस नामक रोग मिल रहा है. विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश भाग के ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट आदि ज़िले पूरे भारत में पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हैं. इन्हीं पत्थरों पर मोम की तरह तराशे गए देवगढ़, खजुराहो, कालिंजर, झांसी का किला, मदनपुर, सीरोन, जहाजपुर एवं दुघई के मूर्ति शिल्प को देखने देश से ही नहीं, अपितु विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक बुंदेलखंड आते हैं. लेकिन, आज तक किसी की नज़र उन मज़दूरों की ओर नहीं गई, जिनकी कड़ी मेहनत पर टिका है यहां का मूर्ति शिल्प. हालात इस क़दर बदतर हो गए हैं कि पांच सौ से अधिक पत्थर खदानों में काम करने वाले दस हज़ार से अधिक आदिवासी सहरिया, राइत, दलित एवं निचले तबके के मज़दूर मंदसौर (मध्य प्रदेश) के स्लेट-पेंसिल मज़दूरों की तरह सिल्कोशिस नामक जानलेवा बीमारी के शिकार होकर मौत की कगार पर खड़े हैं. पत्थर काटने के दौरान झड़ने वाली सिलिका नामक धूल सांस द्वारा फेफड़ों में जाने और जमने से इन मज़दूरों के शरीर में सिल्कोशिस नामक रोग पल रहा है और अनपढ़-ग़रीब मज़दूर नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं. इस बीमारी का इलाज अभी संभव नहीं है. सरकार को इस उद्योग से भारी राजस्व मिलता है, लेकिन उसने आज तक इस रोग के प्रति कोई कारगर क़दम नहीं उठाया.

1984 में जब विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक मज़दूरों की मौत हुई थी, तब तत्कालीन सांसद शरद यादव ने राज्यसभा में यह मामला उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में आज तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए. सिल्कोशिस रोग बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश भूभाग में आने वाले कबरई, कुलपहाड़, भरतकूप, शंकरगढ़, भरुआ सुमेरपुर, पहाड़ गांव, मोठ, समथर, धौर्रा, जाखलौन, पटना, पारौल, मदनपुर, डोंगरा, पाली, बालाबेट, जमुनिया, जीरौन एवं बंट आदि इलाक़ों की खदानों में कार्यरत मज़दूरों के शरीर को खोखला कर रहा है. पत्थर खनन में आधुनिक मशीनों के चलन ने परेशानी और बढ़ा दी है. पहले छेनी-हथौड़े से पत्थर चीरने-काटने में धूल कम झड़ती थी, अब कटर का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो रहा है. यही नहीं, इन मज़दूरों को इस जानलेवा बीमारी की कोई जानकारी नहीं है. मज़दूर इसे दैवीय इच्छा मानते हैं. जाखलौन के किनारे पर बसी एक आदिवासी बस्ती में रहने वाली बीस वर्षीय जनकिया, जिसका पति बालचंद 24 वर्ष की उम्र में इसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर गया, ने बताया कि उसके पति के मुंह से पहले ख़ून गिरता था, उसने समझा कि भूत-प्रेत का चक्कर है. बहुत झाड़फूंक कराई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. एक दिन सुबह जब उसने पति को नाश्ते के लिए जगाया तो वह नहीं उठा. जनकिया की तीन छोटी-छोटी लड़कियां हैं. इसी बस्ती की मलीदा नामक विकलांग महिला ने बताया, उसके पति मुंह में ख़ून आने के कारण एक दिन चल बसे. वह पैसे के लिए ललितपुर गई थी, लेकिन साहब ने कहा कि पैरों से कहीं काम होता है, काम तो हाथ से होता है. इस महिला ने ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक इस विधवा का आवेदन स्वीकार नहीं हुआ.

इसी प्रकार ग्राम बंट निवासी मल्थू ने बताया कि उसका 25 वर्षीय बेटा पत्थर खदान पर कार्यरत था. वह सिल्कोशिस का शिकार होकर चल बसा. अब उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है. हरजुआ (35), मुन्नू (20), पिन्ना (30), मोहन (35), हरपा (50) जैसे कई आदिवासी इस रोग का शिकार बने. आदिवासी दमरू की कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उसके तीन बेटे चुन्नीलाल (23), सुनुआ (25) और बड़जोग (30) इस रोग का शिकार होकर दुनिया से विदा हो गए. चौथा बेटा भगौने भी सिल्कोशिस का शिकार है. गौना के समीप स्थित खदान में काम करने वाले राइत खुमान के 20 वर्षीय बेटे की भी इसी बीमारी के चलते पिछले साल मौत हो गई. ललितपुर जनपद का क्षयरोग विभाग जानकारी देने में आनाकानी करता है. वह न तो पुष्टि करता है और न ही इंकार.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री विशंभर प्रसाद निषाद कहते हैं कि प्रदेश में खनिज नियमावली का घोर उल्लघंन हो रहा है. खनन माफ़ियाओं की मिलीभगत से रोज़ाना करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है. बालू का पट्टा देने में निषादों-केवटों को मिलने वाली प्राथमिकता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कबरई, झांसी, भरतकूप एवं शंकरगढ़ के क्रेशरों को मनमानी करने की छूट दे रखी है. नियम है कि हवा की दिशाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त ऊंचाई की विंड ब्रेकिंग वाल का निर्माण किया जाए. परिसर के भीतर वाहनों के आवागमन के लिए पक्की सड़क बनाई जाए. भूमि पर जल उत्सर्जन के स्रोतों पर वाटर स्प्रिंकलर्स (पानी के फव्वारे) बनाए जाएं. स्टोन क्रशर परिसर के चारों ओर पर्याप्त चौड़ाई की हरित पट्टिका विकसित की जाए. स्क्रीन को कवर किया जाए.

पत्थर खदान मज़दूरों की लड़ाई लड़ने के लिए जब लोग आगे आते हैं तो ग्रेनाइट, राकफास्पेट एवं डायस्पोर जैसे क़ीमती खनिज और सैंडस्टोन आदि पर क़ब्ज़ा जमाए बैठे माफ़िया चांदी के चमकते सिक्कों के माध्यम से मामला बराबर कर लेते हैं. मज़दूर नेता बाबूलाल मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़े.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पत्थर खदान इलाक़ों से कम से कम 5-6 किमी की दूरी पर आवासीय स्थान बनाए जाएं, ताकि टीबी के ख़तरे से मज़दूरों एवं उनके परिवारों को बचाया जा सके. लेकिन, यहां बमुश्किल आधा-एक किलोमीटर की दूरी पर मज़दूर रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर टीबी के मरीज हैं. बचाव के लिए मज़दूरों को हेलमेट, दस्ताने और जूते तक नहीं मिलते. पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े करने वाली क्रशर मशीन से झड़ने वाली गर्द से मज़दूरों को टीबी की जानलेवा बीमारी हो जाती है. टीबी का शिकार होते ही शुरू हो जाती है मालिकों की क्रूरता और मज़दूरों के दुर्भाग्य की कहानी. मालिक उस मज़दूर को नौकरी से निकाल देते हैं, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में टीबी की पुष्टि हो जाती है, ताकि उन्हें इलाज न कराना पड़े और मर जाने पर मुआवज़ा न देना पड़े. कबरई (महोबा) क्रशर जोन में हज़ारों मज़दूर टीबी के मरीज हैं. यहां के खेत क्रशर से झड़ने वाली धूल के चलते बंजर होते जा रहे हैं. किसान वातावरण में फैली धूल के कारण जानलेवा बीमारियों की गिरफ़्त में आ चुके हैं. मध्य प्रदेश की खदानों में काम करने वाले दिगवार नामक गांव के आदिवासी हरपे ने बताया कि उसके यहां भी खदान में काम करने वाले दो नौजवान पिछले वर्ष अकाल मौत के शिकार हो गए. जब आदिवासियों को बताया गया कि खदानों में काम करने से जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें. सरकार ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है. रेंज वाले लकड़ी लाने पर मारते हैं. पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा. ग्राम बंट के मनु, जगते, सुंदर एवं बंटू, ग्राम जहाजपुर के मोती, कल्लू, अजुद्दी एवं खिम्मा, ग्राम मजुनिया के भगवानदास, कोमल सिंह, भगवान सिंह एवं खिलावन और ग्राम पाली के राम प्रसाद एवं हलकू समेत 500 से अधिक लोग सिल्कोशिस से पीड़ित हैं. ज़िला क्षय रोग अधिकारी द्वारा 125 से अधिक लोगों की प्रारंभिक जांच की गई, जिनमें सिल्कोशिस के लक्षण पाए गए.

एक अध्ययन के अनुसार, यह रोग कम उम्र के मज़दूरों में अधिक होता है. अमझरा घाटी, मदनपुर, धौर्रा, बंद, जहाजपुर एवं जाखलौन आदि क्षेत्रों की खदानों में 19 साल से भी कम उम्र के मज़दूर काम कर रहे हैं. यहां एक माफ़िया सरदार की खदानों पर सबसे ज़्यादा नाबालिग मज़दूर पत्थर काटने का काम करते हैं, लेकिन राजनीति में होने के कारण आज तक किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस सरदार का कुछ बिगाड़ सके. मदनपुर के पास स्थित खदानों में कुछ मज़दूर बंधुवा जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं. बताया गया कि ऐसे लोगों को पेशगी की रकम देकर काग़ज़ों पर अंगूठा लगवा लिया जाता है. उसके बाद मात्र एक वक़्त की रोटी के बदले उन्हें पत्थर काटने का काम करना पड़ता है. कभी-कभी तो अवैध खदानों में इन्हीं मज़दूरों से रात में भी पत्थर कटवाने का काम लिया जाता है. इस क्षेत्र में सिल्कोशिस के शिकार अधिकतर युवा हुए हैं, जिनकी उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच है. डॉ. सैयद के अनुसार, कम उम्र के लोगों को यह रोग प्राय: जल्दी होता है. ग्राम बंद निवासी खिम्पा की हालत दयनीय है. उसके पास ललितपुर आने के लिए किराए के पैसे तक नहीं हैं. घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तिस पर यह रोग. कई दिनों से परिवार में एक वक़्त की रोटी की समस्या बनी हुई है. पट्टे की ज़मीन साहूकार ने ज़ब्त कर ली है.

मज़दूरों को पत्थर काटने के बदले केवल 15 रुपये मज़दूरी दी जाती है. समाजवादी चिंतक राजेंद्र रजक ने इन मज़दूरों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया है. जानलेवा बीमारी सिल्कोशिस के संदर्भ में खनिज अधिकारियों का कहना है कि यह काम स्वास्थ्य विभाग का है, इसका इलाज वही करेगा. पत्थर खदान मज़दूरों की लड़ाई लड़ने के लिए जब लोग आगे आते हैं तो ग्रेनाइट, राकफास्पेट एवं डायस्पोर जैसे क़ीमती खनिज और सैंडस्टोन आदि पर क़ब्ज़ा जमाए बैठे माफ़िया चांदी के चमकते सिक्कों के माध्यम से मामला बराबर कर लेते हैं. मज़दूर नेता बाबूलाल मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़े. सर्वोच्च न्यायालय ने आशानुरूप फ़ैसला भी किया, लेकिन क्रशर मालिक मज़दूरों का ख़ून चूसने से बाज नहीं आए. क्रशर मालिक मज़दूरों का नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ाते और इलाज कराने या मुआवज़ा देने से साफ़ मुकर जाते है. यही हाल पत्थर खदानों का है. श्रम क़ानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. मज़दूरों का शोषण करने के लिए नए-नए फार्मूले अपनाए जाते हैं. खनिज संपदा के धनी बुंदेलखंड में माफ़ियाओं और सरकारी तंत्र ने ग़रीबों एवं मध्यम वर्ग का जीना मुहाल कर दिया है. इसीलिए यहां लालसेना और माओवादियों का ख़तरा मंडराने लगा है. शंकरगढ़ और भरतकूप में दस्तक दे चुके माओवादी आदिवासियों को संगठित करने में लगे हैं. अगर समय रहते बुंदेलखंड के मज़दूरों को खनिज माफ़ियाओं से राहत नहीं दिलाई गई तो क्षेत्र के अमन-चैन को ग्रहण लग सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति जैविक संसाधनों तक पहुंच, जैव तकनीक में उनके इस्तेमाल और अनुवांशिकी विज्ञान के बीच के घालमेल को सतह पर लाती है.

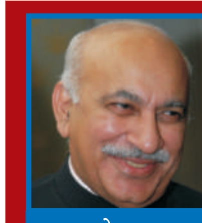

एम जे अकबर

माया, श्रेय और सम्मान

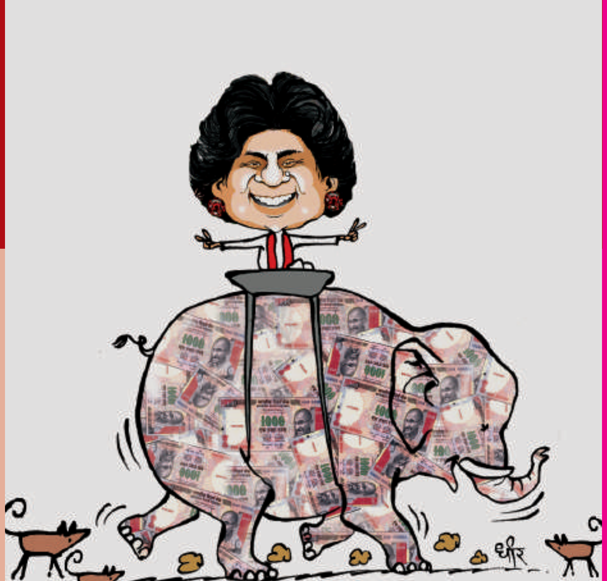

किसी रविवार की अलसायी सुबह को मायावती, जिन्हें आजकल गहनों की जगह रुपयों की माला ज़्यादा भाने लगी है, पर आप कितना गुस्सा हो सकते हैं. बात उस दिन की है, जब मायावती की जय–जयकार हुई और देखते ही देखते रुपयों से गुंथी माला उनके गले में पहना दी गई. यदि इस घटना पर बने कार्टूनों की संख्या पर ग़ौर करें तो गुस्से का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. यह मालाकांड किसी को भी उत्तेजित करने के लिए काफ़ी है. वैसे भी मायावती अंग्रेजी दां भारतीयों पर झुंझलाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़तीं, क्योंकि राजनीति, व्यावहारिकता और मनोविज्ञान के धरातल पर वह उनके विपरीत ध्रुव पर खड़ी हैं. लेकिन थोड़ा रुकिए, समय के चक्र को पीछे ले जाकर दोबारा सोचिए. अपनी साफगोई और स्पष्टवादिता के लिए उन्हें नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत सी ग्रेड तो मिल ही जाना चाहिए. मायावती वही काम खुले आकाश के नीचे कर रही हैं, जो काम अन्य राजनीतिज्ञ बंद कमरे के अंदर करते हैं. यहां यह बात भी मायने रखती है कि माया की माला के लिए रुपये पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिए थे. यह किसी लॉबिंग ग्रुप द्वारा किसी उपकार के एवज में दिया गया कालाधन नहीं था.

हम मायावती की ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बंद कमरे की चाहरदीवारी में भी उन्हें ऐसे काम करने से शायद कोई गुरेज नहीं है. लेकिन यह भी सही है कि आलोचनाओं की इस भरमार के पीछे छुपे पाखंड की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए. भारतीय राजनीति के लिए यह वैसी ही स्थिति है, जैसे किसी तीखी गंध वाले बदबूदार कमरे में हल्की ख़ुशबू वाले इत्र का छिड़काव कर दिया गया हो. राजनीति आज ख़र्चीली होती जा रही है और राजनीतिज्ञ बर्बाद. कुछ लोग पांच करोड़ रुपये के ख़र्च में बारे में सोच कर चौंक उठते हैं, लेकिन यह चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि राजनीति के मौजूदा दौर में यह रकम तो कुछ भी नहीं है.

मायावती अपने विरोधियों को कभी भी अंजाने में नाराज़ नहीं करतीं. वह जब भी ऐसा करती हैं, जानबूझ कर ही करती हैं. मायावती दलित सशक्तीकरण की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं. इस प्रक्रिया की शुरुआत आज़ादी से पहले भीमराव अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवी के नेतृत्व में हुई थी. छुआछूत के ख़िलाफ़ उनके आंदोलन ने उन्हें अंग्रेजों के भारत में अलग राजनीतिक ज़मीन की मांग के लिए प्रेरित किया. हालांकि उन्हें जल्द ही यह महसूस हो गया कि इतिहास के उस मुक़ाम पर उनके लिए सामंजस्य ही सबसे अच्छा विकल्प था. वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के साथ उनके पूना पैक्ट ने दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक विकास का प्रमुख आधार बना.

इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कांशीराम ने की, जब उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को सिरे से ख़ारिज करते हुए दलितों को कांग्रेस के दायरे से बाहर निकालने का अभियान छेड़ा. यह काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि गांधी जी ने दलितों को जो नाम दिया था, उसे ज़ुबान पर लाना भी आज ग़ैरक़ानूनी है. कांशीराम ने व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी और भारतीय राजनीति की दिशा बदल कर रख दी. कांशीराम की उत्तराधिकारी कही जाने वाली मायावती ने उनकी विरासत पर ही सत्ता की कुर्सी तक का सफर पूरा किया, वह भी किसी अन्य राजनीतिक दल के सहयोग के बिना. यह उपलब्धि ख़ास है, क्योंकि 1990 के दशक की समाप्ति तक इस संभावना को दिवास्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता था. मायावती ने अपने राजनीतिक तेवर को नया रंग देते हुए यह ख़ास मुक़ाम हासिल किया है.

चुनौती एक संज्ञा है, लेकिन क्रोध के लिहाज़ से देखें तो यह क्रिया भी है. जब–जब मायावती अपनी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति का प्रदर्शन करती हैं तो यह उनके समर्थकों, उनके वोट बैंक के लिए एक स्पष्ट संदेश की तरह होता है. वह यह कि सत्ता का स्रोत धन है और सत्ता अब किसी की जागीर नहीं है. उनकी भी नहीं, जिन्होंने हज़ारों सालों से दलितों को प्रताड़ित किया है. वह हर ऐसे क़ानून का मख़ौल उड़ाने से भी नहीं चूकतीं, जिसने दलितों को सामाजिक दासता और आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाए रखने में योगदान किया है. वह उस व्यवस्था को भी अंगूठा दिखाने से परहेज़ नहीं करतीं, जिसमें अन्य पार्टियां अपने काले धन को छुपाने में कामयाब होती हैं. जबकि ख़ुद उनसे हर पैसे का हिसाब रखने की अपेक्षा की जाती है. राजनीति के मैदान में वह खेल का तरीक़ा बदलने की कोशिश कर रही हैं. उनके लिए धन के खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन का वही महत्व है, जो उनके प्रतिद्वंद्वियों के लिए गोपनीयता का. सच तो यह है कि यदि सीबीआई सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की विमान यात्राओं की ईमानदारी से जांच करे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाकर चलना मायावती की राजनीतिक मजबूरी है. निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना ऐसी है कि जीत हासिल करने के लिए अन्य वर्गों का समर्थन हासिल करना उनकी विवशता है. मुसलमान उनके स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए पहले ही आपाधापी मची है. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ संबंध बनाए रखना भी उनकी राजनीतिक ज़रूरत है. सरकारों का पुनर्निर्वाचन रैलियों से नहीं होता, यह तो शासन तंत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. रैलियों से समर्थकों का विश्वास बढ़ता है, जबकि सुशासन से इस विश्वास का विस्तार होता है.

लेकिन इन सबके बीच इस बात को न भूलें कि मायावती की उस माला ने लंबा सफर तय किया. पैसे की उगाही से लेकर उसे गूंथने और फिर मुख्यमंत्री की गर्दन से लेकर उनकी आलमारी तक पहुंचने की इस लंबी यात्रा में एक रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ. पैसों की माला का प्रचलन भारत के लिए नया नहीं है. नेताओं से लेकर शादी में दूल्हों तक का इससे सम्मान किए जाने की परंपरा काफी पुरानी है. महिला आरक्षण बिल पर संसद में हंगामे के बाद देश भर में मशहूर हो चुके जदयू सांसद एजाज़ अली के पटना पहुंचने पर उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट पर ही उन्हें नोटों की माला पहनाई. कोई शक़ नहीं कि उसमें हज़ार रुपये वाले नोट नहीं थे, लेकिन बिहार में सौ रुपये में बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता है. ताज्जुब की बात तो यह है कि एजाज़ अली की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही उसमें से सारे नोट निकल चुके थे. यह बिहारियों की आदर्शवादिता का एक और उदाहरण है. मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचारधारा की तर्ज पर उसमें से सबको अपना–अपना हिस्सा मिला. मांग और ज़रूरत के हिसाब से और बिना किसी बिचौलिए की दख़लंदाज़ी के. पैसा उन्हीं लोगों ने दिया था, जो देना चाहते थे और यह उन लोगों तक पहुंच गया, जिन्हें इसकी ज़रूरत थी. नेता को मिला तो केवल नकद रहित इनाम.

feedback@chauthiduniya.com

कांची कोहली

जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी के बीच का घालमेल

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार यानी एनबीए ने उत्तराखंड के देहरादून डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेस के साथ एक समझौता किया है. उसने तीन जनवरी 2008 को अमेरिका स्थित लिबेनन में मास्कोमा कॉरपोरेशन को जैविक संसाधन हस्तांतरित करने के लिए समझौते की यह प्रक्रिया पूरी की. समझौते के तहत संस्थान ने काफ़ी संख्या में जंगली या पालतू जानवरों जैसे–भैंस, भेड़ एवं बकरा आदि से एनारोबिक फंगी (ऐसे फंगी, जिसे हवा की ज़रूरत नहीं होती) को अलग कर हस्तांतरित करने की इजाज़त दे दी है. इस प्रक्रिया में शाकाहारी जानवरों को भी शामिल किया गया है. समझौते पर सहमति एक साल के लिए बनी है. ज़ाहिर है, करार की तमाम प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई है, लेकिन आम लोगों को करार की विशेष जानकारियों से वंचित रखा गया है.

ज़ाहिर है, इस तरह की मंज़ूरी भारत के बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के नज़रिए से अनिवार्य है. किसी भी जैविक संसाधन को विदेशी कंपनियों या संस्थानों को हस्तांतरित किए जाने से पहले एनबीए की सहमति आवश्यक है. अगर हस्तांतरित होने वाले संसाधन के व्यवसायिक इस्तेमाल की संभावना हो, तो उससे होने वाले मुनाफ़े के विभाजन की प्रक्रिया क्या हो, करार की शर्तों में इसका उल्लेख भी ज़रूरी है. 2003 में गठित एनबीए अब तक ऐसे 266 प्रस्तावों को मंज़ूरी दे चुका है.

यह समझौता बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावों को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया का एक उदाहरण पेश करता है, लेकिन ऐसी कई बातें हैं, जो फिर भी हमारी समझ से परे हैं. एनबीए के समझौता पत्र को उसकी वेबसाइट (www.nbaindia.org) पर अपलोड तो किया गया है, लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई है कि इस जैविक संसाधन को आख़िर किस उद्देश्य से एक अमेरिकी कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है. समझौते के काग़ज़ातों या सहमति पत्र में न तो कंपनी के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न ही उसके कामकाज के बारे में. इसमें बस इतना ही बताया गया है कि इन जैविक संसाधनों को जांच के लिए देश के बाहर भेजा जा रहा है.

कंपनी देश के अलग–अलग हिस्सों से इन संसाधनों को एकत्र कर सकती है. इसमें राजस्थान के बीकानेर एवं जयपुर, हरियाणा का करनाल, उत्तर प्रदेश के मेरठ एवं आगरा, उत्तराखंड के देहरादून एवं टिहरी और मध्य प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर आदि शहर शामिल हैं. वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई सूचना में इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई है. आप इन जानकारियों की तह में जाएं तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं. मास्कोमा कॉरपोरेशन का डार्ट माउथ रीजनल टेक्नोलॉजी सेंटर, जहां इन जैविक संसाधनों को भेजा जा रहा है, सेल्यूलोज बायोमास से इथेनॉल के उत्पादन के तरीक़ों पर शोध कार्यों में लगा है. वस्तुत: बोस्टन स्थित मास्कोमा एक एनर्जी बायोटेक कंपनी है, जो सेल्यूलोज बायोमास से दूसरी पीढ़ी के जैविक ईंधनों के उत्पादन और उसके प्रसार में लगी है. कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि मास्कोमा विश्व की जानी–मानी शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी–ग़ैर सरकारी एवं निजी संगठनों के साथ अपने जुड़ाव और साझीदारी से ग़ौरवान्वित है.

ग़ौरतलब तथ्य यह है कि डॉल्फिन एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से विदेश भेजे जाने वाले इन जैविक संसाधनों का इस्तेमाल इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाएगा, जो देश में बायो–डीजल उद्योग का एक आवश्यक तत्व है. इन संसाधनों के इस्तेमाल के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा मास्कोमा में निवेश करने वाले लोगों के नाम देखकर लगाया जा सकता है. इनमें फ्लैगशिप वेंचर्स, खोसला वेंचर्स सहित ऑटो मोबाइल क्षेत्र की जेनरल मोटर्स और मैराथन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कई नामी–गिरामी कंपनियां शामिल हैं. दरअसल, एक मई, 2008 को ही मास्कोमा ने सेल्यूलोज इथेनॉल के विकास के लिए जेनरल मोटर्स के साथ भी नया करार किया है.

सेल्यूलोज से बना इथेनॉल दूसरी पीढ़ी के जैविक ईंधनों के उत्पादन के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण है. मौजूदा समय में इसके उत्पादन के लिए जत्रोपा, पोंगेमिया और गन्ने का इस्तेमाल होता है. सेल्यूलोज से इथेनॉल के उत्पादन के लिए लकड़ी, घास और पौधों के न खाए जाने वाले हिस्सों का उपयोग होता है. जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक रूपांतरण का इस्तेमाल उत्पादन की इस प्रक्रिया का आधार है. अमेरिकी कृषि मंत्रालय (यूएसडीए) की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक़, सेल्यूलोज से जैविक ईंधन के उत्पादन में एनारोबिक फंगी के उपयोग पर अभी शोध कार्य जारी है.

इन सब बातों से एक चीज तो स्पष्ट है कि हस्तांतरण की इस पूरी प्रक्रिया का एक व्यवसायिक दृष्टिकोण भी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है. हालांकि संस्थान ने जब बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रूल्स, 2004 के फॉर्म–4 में एनबीए के सामने अपना आवेदनपत्र दिया होगा तो उसे मास्कोमा कॉरपोरेशन और उसके उद्देश्यों की पूरी जानकारी देनी पड़ी होगी. यही नहीं, फॉर्म में समझौते से होने वाले हर आर्थिक, सामाजिक, जैव तकनीक, विज्ञान संबंधी या दूसरे लाभों के बारे में भी जानकारी देने की ज़रूरत होती है. इससे एक बात तो साफ़ है कि या तो इन सब बातों का ज़िक्र फॉर्म में नहीं किया गया था या फिर एनबीए वाणिज्यिक पहलुओं को समझने में नाकाम रहा, क्योंकि ऐसा होने पर समझौते से होने वाले लाभों के विभाजन के लिए भी दिशा निर्देश तय किए गए होते.

इस समझौते के प्रावधानों में यह भी उल्लिखित है कि इसकी शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इन जैविक संसाधनों को एक बार विदेश भेज दिया गया तो फिर उस पर नज़र रखने के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है. यह भी संभव है कि कल कॉरपोरेशन इसे अपने नए आविष्कार के रूप में प्रचारित करे. यह भी संभव है कि इन जैविक संसाधनों को दोबारा भेजने की ज़रूरत ही न पड़े, क्योंकि जैव तकनीक के क्षेत्र में आश्चर्यजनक आविष्कार अक्सर सूक्ष्मतम जीवाणुओं से ही हो जाते हैं.

ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति जैविक संसाधनों तक पहुंच, जैव तकनीक में उनके इस्तेमाल और अनुवांशिकी विज्ञान के बीच के घालमेल को सतह पर लाती है. और, यह तो केवल बानगी भर है. बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के क्रियान्वयन में कई और ऐसे घालमेल हैं. रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ह्यूमन इक्विड्स रिलेशनशिप को जंगली गदहों के बालों और ख़ून के नमूनों की जांच का अधिकार दे दिया गया है, जबकि इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी उपलब्ध नहीं है. अमेरिका की नोवोजाइम्स बायोलॉजिकल इंक को भी बैसिलस और स्यूडोनोमस जीवाणुओं के व्यवसायिक इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है. कंपनी इस आधार पर केरल के मालमपुझा के जंगलों में पौधों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी. फिर इसका प्रायोगिक इस्तेमाल टमाटर एवं धान आदि की फ़सलों पर किया जाना है. नोवोजाइम्स एक शीर्ष कंपनी है. माइक्रोबायोलॉजी, जैव एवं जीन तकनीक के क्षेत्र में इसे महारत हासिल है.

एक ओर जहां जैविक संसाधनों तक पहुंच और जीन रूपांतरण में इसके इस्तेमाल के बीच का घालमेल हमें हैरान करता है, वहीं इससे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट की कमियां भी उजागर हो रही हैं. संसाधनों तक पहुंच बनाने, उनके हस्तांतरण और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों को लेकर इसमें पारदर्शिता का नितांत अभाव है. जबकि एनबीए द्वारा स्वीकृत 358 प्रस्तावों में से 268 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से ही संबंधित हैं और अक्टूबर 2009 तक ऐसे 205 आवेदन एनबीए के पास लंबित पड़े थे. चूंकि एनबीए की वेबसाइट पर सूचनाओं का नवीकरण नहीं होता, इसलिए इन प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली या नहीं, यह जानने के लिए सूचना का अधिकार ही एकमात्र विकल्प है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई संगठनों का इन मामलों से संबंध है. एक ओर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीआरए) है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान हैं. वहीं पेप्सी और सिनजेंटा सीड्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं. सच तो यह है कि यह तूफान से पहले की शांति भर है और बेहतर होगा कि आने वाले समय में हम इस तूफ़ान से मुक़ाबले के लिए अभी कमर कस लें.

लेखिका ग़ैर सरकारी संस्था कल्पवृक्ष से जुड़ी हैं

feedback@chauthiduniya.com

शाहरुख ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया

चौथी दुनिया के 8–14 मार्च 2010 के अंक में शाहरुख खान–फॉक्स ने ठाकरे और पूरे देश को मूर्ख बनाया शीर्षक से प्रकाशित डॉ. मनीष कुमार का आलेख दिलचस्प है. अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म माई नेम इज खान के बारे में इतनी जानकारी पाकर बहुत खुशी हुई. मेरे विचार से इतनी बातें कोई भी नहीं जानता था. इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो कुछ घटित हुआ, वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला. सिनेमाघर मालिक भी इसकी रिलीज से डर रहे थे. यह और बात है कि फिल्म उतनी हिट नहीं हो पाई, जितनी इसके बाबत हर किसी ने कल्पना की थी. यह कहना भी ठीक नहीं है कि शाहरुख और उनकी इस फिल्म ने सभी को मूर्ख बनाया. आपकी नजरें ऐसा कह सकती हैं, पर जैसा माहौल फिल्म की रिलीज से पहले देश भर में था, उससे कोई भी अंजान नहीं था. शाहरुख ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया. यह तो एक संयोग ही था या अनहोनी, जिसकी इतनी चर्चा हो गई.

–राजकुमार शर्मा राही, *उत्तम नगर, नई दिल्ली.*

■ शाहरुख खान–फॉक्स ने ठाकरे और पूरे देश को मूर्ख बनाया आलेख पढ़कर मुझे लगता है कि इस मामले में आपने एकतरफा स्टैंड अपनाया. आपने लिखा कि फिल्म माई नेम इज खान को व्यापक प्रचार दिलाने के लिए शाहरुख खान और फॉक्स ने यह सारा तमाशा किया. थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि उन्होंने ऐसा किया, तो क्या ऐसा करना अपराध है? हर निर्माता–वितरक चाहता है कि उसकी फिल्म को व्यापक प्रचार मिले, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. यही बाजार का शाश्वत नियम है. इसमें बुराई क्या है? आपने अपनी काबिलियत दिखाते हुए एक पूरा पेज शाहरुख–फॉक्स को अपराधी ठहराने में खर्च कर दिया, मगर बाल ठाकरे की गुंडागर्दी पर दो शब्द भी नहीं लिखे. आप जैसे पत्रकारों की इसी कलमतोड़ कारीगरी ने इस फिल्म को इतना चर्चित बना दिया कि जो शख्स कभी सिनेमा नहीं देखता था, उसने भी बड़े चाव से टिकट खरीद कर इस फिल्म को देखा और जमकर तारीफ की. आज हमारे देश में दूल्हा–दुल्हन भी रियलिटी शो के जरिए चुने जा रहे हैं, विधिवत विवाह भी संपन्न हो रहे हैं. और तो और, नेता–अभिनेता से लेकर धार्मिक गुरु और बाबा तक अपनी–अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं. अगर शाहरुख और फॉक्स ने भी यही किया तो पहाड़ क्यों टूट पड़ा? मैं तो तारीफ करता हूं शाहरुख और फॉक्स की, जिन्होंने अपने मार्केटिंग हुनर से एक नया इतिहास रच दिया. आपने इस फिल्म पर एक शब्द भी नहीं लिखा. माई नेम इज खान अन्य मसाला फिल्मों की भीड़ से अलग है. इसमें और कुछ हो न हो, लेकिन यह फिल्म इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश बेहद सादगी के साथ देती है. निदा फाजली के इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं: जब तुम किसी से गिला रखना, अपने सामने भी आईना रखना.

–बिस्मिल्लाह महबूबा (अर्पित), *धनबाद, झारखंड.*

कुपोषण की समस्या और देश

22–28 मार्च 2010 के अंक में मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ परिशिष्ट में विनय दीक्षित की रिपोर्ट ने जो सच उजागर किया है, वह चिंताजनक है. कुपोषण सिर्फ किसी राज्य विशेष की नहीं, बल्कि पूरे देश की एक बड़ी समस्या है. केंद्र सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए.

–रागिनी सक्सेना, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

मुसलमानों का दर्द

बिहार में मुसलमान शीर्षक से प्रकाशित आलेख में बड़ी बारीकी से कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली गई है. वाकई सच यही है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक दलों को मुस्लिम समाज अनायास ही याद आने लगता है. मुसलमानों का हित क्या है, परेशानी क्या है, उनके लिए क्या होना चाहिए जैसी चिंताएं हर किसी को सताने लगती हैं. लेकिन, हकीकत के धरातल पर कोई भी किसी के प्रति चिंतित नहीं है. यह सिर्फ अपनी सत्ता बचाने अथवा उसे दोबारा हासिल करने के पुराने घिसे–पिटे तरीके हैं. यह सब कुछ जनता भी जानती है.

–मोहम्मद शादाब, *रामपुर, उत्तर प्रदेश.*

पान किसानों की परेशानी

कभी प्रकृति की मार तो कभी सरकारी नीतियों के चलते परेशानी झेलना किसानों की नियति है. मौसम साथ देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. ऐसे में अगर किसानों को शासन की ओर से कोई राहत मिल जाती है तो परिस्थितियों से लड़ना उनके लिए कुछ आसान हो जाता है. भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इस सच्चाई को नजरअंदाज करके हम विकास और खुशहाली की कल्पना भी नहीं कर सकते.

–निशीत कुमार शर्मा, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

दादा का डंडा

चौथी दुनिया के 15 मार्च के अंक में यूपीए सरकार द्वारा पेश बजट पर आपने आम आदमी की पीठ पर दादा का डंडा शीर्षक से जो आलेख प्रकाशित किया है, वह लाजवाब है. असल में कांग्रेस के पास दिखाने वाले तो अनेक दांत हैं, पर काम के लायक शायद एक भी नहीं. आम आदमी को मुद्रास्फीति, कागजी ग्रोथ और आंकडों के जाल से कोई मतलब नहीं होता. उसका सामना जब बाजार से होता है और उसकी जेब कटने लगती है तो वह बौखला जाता है. ऐसे में उसे सरकार के तमाम दावे खोखले लगते हैं. कहना नहीं चाहिए, पर यह मानना ही होगा कि एनडीए की सरकार हर हाल में बेहतर थी. अर्थ व्यवस्था में पारंगत होना किताबी ज्ञान के कारण तो आम बात है, असली बात यह है कि आप देश की जनता को क्या दे रहे हैं. कांग्रेस की अबतक कि सभी सरकारें जनता को देने से ज्यादा जनता से लेती रही हैं.

–राकेश कुमार, *दमोह, मध्य प्रदेश.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं.

संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11 नोएडा

(उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

सच्चाई यह है कि हम आज भी सबको उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं हैं. विशेषकर उन्हें, जो समाज में हाशिए पर हैं.

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई आशा

चलिए, आशा की किरण तो दिखाई दी. भारत में जैसा राजनैतिक माहौल है और जिस तरह राजनैतिक दल अपनी सोच बदल रहे हैं, उससे नहीं लगता कि कुछ बुनियादी बदलाव आसानी से हो पाएंगे. वाई एस आर ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसका वायदा उन्होंने अपने घोषणापत्र में किया था. पर इसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इसे अवैध बताया. राजनैतिक दलों में छिपी ख़ुशी दिखाई दी. कहीं कोई राजनैतिक हलचल नहीं हुई. आंध्र प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध कह कर चार फ़ीसदी आरक्षण की अनुमति आंध्र प्रदेश सरकार को दे दी है. इसके दूसरे पहलुओं पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ भी बनाएगी. जहां राजनैतिक दल ख़ामोश हो जाएं, वहां सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फ़ैसला आशा की किरण के अलावा क्या माना जा सकता है.

दरअसल आशा की किरण हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वे लाइनें, जिनमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, सवाल यह नहीं है कि वे हिंदू हैं या मुसलमान, बल्कि सवाल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का है. सिर्फ़ इसलिए कि वे मुसलमान हैं, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता. सबसे बड़ी अदालत की यह समझदारी एक रास्ता दिखाती है, बताती है कि राजनीति भले भूलने की कोशिश करे, पर हमारे संविधान की रक्षक सबसे बड़ी अदालत सामाजिक स्थिति की वजह से कमज़ोर वर्गों को उनके हाल पर नहीं छोड़ने वाली.

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, इसकी मांग कोई राजनैतिक दल संगठित रूप से नहीं कर रहा है. इतना ही नहीं, देश के मुस्लिम संगठन भी इसे लागू करने की मांग नहीं कर रहे. मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय अधिवेशन में तो इसे अनदेखा करने की बात भी कुछ वक्ताओं ने की और कहा कि सच्चर रिपोर्ट ही सही रिपोर्ट है. दरअसल रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट समाज में कई अंतर्विरोधों को सामने ला सकती है, इसलिए सभी इस पर एकमत हैं कि रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट को एक किनारे कर दिया जाए. हक़ीक़त यह है कि सच्चर कमीशन ने जिन सवालों की ओर इशारा किया है, उनका हल रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट में है.

अचानक रंगनाथ मिश्र कमीशन को लेकर संदेह पैदा किए जाने लगे हैं. एक संगठन एक गोष्ठी करता है, जिसमें कमीशन की सदस्य आशा दास कहती हैं कि यह रिपोर्ट बदली गई है. आशा दास इस आयोग की सचिव भी थीं. अब वह इस रिपोर्ट को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बता रही हैं. रिपोर्ट आए तीन साल से ज़्यादा हो गए हैं. क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपने से पहले आशा दास ने अपना कोई विरोध कमीशन में दर्ज़ कराया था? यह आयोग सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर काम कर रहा था, तो क्या आशा दास ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में कोई ख़त लिखा था? आशा दास ऐसी ताक़तों का खिलौना बन गई हैं, जो देश के ग़रीब तबकों को कोई हिस्सा देना ही नहीं चाहतीं. एक संगठित अभियान रंगनाथ मिश्र कमीशन और उसकी रिपोर्ट के ख़िलाफ़ प्रारंभ हो गया है.

> अचानक रंगनाथ मिश्र कमीशन को लेकर संदेह पैदा किए जाने लगे हैं. एक संगठन एक गोष्ठी करता है, जिसमें कमीशन की सदस्य आशा दास कहती हैं कि यह रिपोर्ट बदली गई है. आशा दास इस आयोग की सचिव भी थीं. अब वह इस रिपोर्ट को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बता रही हैं.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

इसमें मुस्लिम नेता भी शामिल हो गए हैं. कुछ जाने और कुछ अनजाने, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही निकलने वाला है. आप बहस कीजिए कि मुसलमानों में जाति प्रथा है या नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ग़रीब हैं या नहीं, इसे तो साफ़ कर लीजिए. अगर ग़रीबों को राहत मिलती है तो इसका विरोध ख़ुद मुसलमानों के भीतर से हो, यह बात मुश्किल से समझ में आती है. यहीं सुप्रीम कोर्ट का वाक्य, जो हम लिख चुके हैं, उसे फिर लिखना चाहते हैं, सवाल यह नहीं है कि वे हिंदू हैं या मुसलमान, बल्कि सवाल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का है. सिर्फ़ इसलिए कि वे मुसलमान हैं, उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता.

इस शुरुआत को रुकने नहीं देना चाहिए. समाज के जिन वर्गों के हाथ में सुविधाएं हैं, वे इसे बांटना नहीं चाहते हैं और जिन्हें दूर भगाने की कोशिश की जा रही है, वे अगर खड़े हो गए तो क्या होगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा है. वंचित वर्गों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा है. हमने अपनी संवाददाता को जंगलों में भेज रखा है. उसके अनुसार, न कपड़े हैं, न खाना है, न घर है. फिर भी नक्सलवाद है. पुलिस या सेना को पता ही नहीं है कि पकड़ना किसे है, पर वह पकड़ रही है. किससे और कहां लड़ना है, साफ़ नहीं है, पर लड़ाई चल रही है. समाज के वे वर्ग जो सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि देश की सोलह प्रतिशत आबादी के ग़रीब भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएं.

इन्हें नहीं पता कि अगर इनके हाथों में हथियार आ गए तो देश में कैसी आग लग जाएगी. अभी दस साल भी नहीं बीते हैं कि हम भूल गए हैं कि पंजाब में उग्रवाद की लहर ने कितना परेशान कर दिया था. वे केवल एक से दो प्रतिशत थे. हम तो सोलह प्रतिशत को कोने पर ढकेल देना चाहते हैं. हमारे रिश्ते हमारे किसी पड़ोसी से ठीक नहीं हैं और हमें यह डर भी नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों को मुल्क में घुसने का मौक़ा ख़ुद दे रहे हैं.

होना तो यह चाहिए कि स्थिति की गंभीरता को समझ, संपूर्ण राजनीतिक बिरादरी को गंभीरता दिखा, कम से कम रोटी की गारंटी देने वाली योजनाएं हर कोने पर पहुंचानी चाहिए. नक्सलवाद गोली से नहीं, रोटी और रोजी के अवसरों से शांत होगा. देश के वंचित, दलित अल्पसंख्यकों को अवसर देना ही होगा. अगर उन्हें अवसर नहीं मिलते तो वे भी वही करने लगेंगे, जो आज जंगलों में नक्सलवादी कर रहे हैं. हम बिल्कुल नहीं डराना चाहते, पर हमें लगता है कि कोशिश करने के अवसर भी खत्म होते जा रहे हैं. क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीख लेंगे? कम से कम उन्हें तो उनका हक़ दें, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट देने की अनुमति दे रहा है. और फिर यह केवल आंध्र प्रदेश में क्यों, सारे देश में क्यों नहीं? इसके लिए राजनैतिक साहस की ज़रूरत है, जिसे अपने भीतर पैदा करने की क्षमता चाहिए. अगर आज इसकी कोशिश नहीं करते तो कल इसका वक़्त नहीं रहेगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

जातिगत आरक्षण : व्यवस्थागत ख़ामियों का प्रतिबिंब

डॉ. सौमित्र मोहन

सरकारी एवं ग़ैर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण का मुद्दा बार-बार हमारे सामने आता रहा है. ठीक उसी दैत्य की तरह, जो हर बार अपनी राख से ही दोबारा पैदा हो जाता है. इस मुद्दे पर विचार-विमर्श की ज़रूरत है. हमें यह सोचना होगा कि क्या आरक्षण वाकई ज़रूरी है. वैसे तो जाति आधारित आरक्षण को संविधान की शुरुआत के दस साल बाद ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, पर हमें आज भी इस आरक्षण के दैत्य से लड़ना पड़ रहा है. इसकी वजह यह है कि हम समाज के निचले वर्ग को बराबरी का हक़ दे पाने में असफल रहे हैं. समानता की नींव पर मूल्य आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है.

सच्चाई तो यह है कि जाति आधारित आरक्षण जैसी बुरी व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि अरस्तू और उनके जैसे अन्य समाजशास्त्री कहते हैं, बराबर वालों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए और जो बराबर नहीं हैं, उनके साथ उनके स्तर का ही व्यवहार किया जाना चाहिए. इस तरह एक ऐसा समाज जो जाति के अलावा अन्य कई स्तरों पर भी बंटा हुआ था, उसमें सामाजिक संतुलन को बनाए रखने और हर इंसान को व्यक्तिगत विकास के बराबर मौक़े उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ क़दम उठाना वक़्त की ज़रूरत थी.

एक ओर वे लोग हैं, जो हज़ारों सालों से सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर बने रहे हैं और दूसरी ओर वे लोग हैं, जो सदियों से प्रताड़ना के शिकार होते रहे हैं. ऐसे में आप इन दोनों वर्गों के बीच बराबरी के व्यवहार की उम्मीद भी नहीं कर सकते. यदि हम में से कुछ लोग योग्यता और क्षमता के पैमाने पर समाज के हर तबके के साथ बराबरी के व्यवहार का तर्क रखते हैं तो यह भी याद रखना होगा कि समाज के एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के चलते हमारे अंदर स्वाभाविक पूर्वाग्रह भी मौजूद होते हैं. हो सकता है, हम इन दुर्भावनाओं के प्रति जागरूक न हों, लेकिन फिर भी हम इन्हें आसानी से अपने अंदर पाल लेते हैं, उन्हें तार्किकता की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं तो इसकी वजह यही है कि इनसे हमारी ख़ुद की भलाई जुड़ी होती है. आख़िरकार दुनिया असमानताओं से भरी है, जहां समाज अलग-अलग स्तरों पर बंटा हुआ है. समाज में उच्च और निम्न दो स्तर हैं, जो प्रतियोगिता, सामाजिक आत्मविश्वास, सांस्कृतिक श्रेष्ठता, सामाजिक वातावरण, वास्तविकताओं एवं अवसरों, स्वहित की पहचान और यहां तक की अनुवांशिक पहचान के आधारों पर एकदम अलग हैं.

सत्यमेव जयते
अन्य राज्यों के तरह विहार में भी दलित आयोग का गठन करो। लोजपा
समाज को मत बांटो लोजपा
दलित एकता भाई-भाई इन्हे किसी से नही लड़ाई लोजपा
दलितों के ... अविलम्ब पुरा करो
... पर अत्याचार ... करो / लोजपा
दलितो का बैंक लॉग पुरा करो / लोजपा
दलितों के बीच फूट मत डालो लोजपा

इसमें कोई संदेह नहीं कि सद्भावनापूर्ण पक्षपात की अवधारणा पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था समाज के सभी तबकों को समानता के स्तर पर लाने के लिए तात्कालिक ज़रूरत थी. लेकिन, यह अभी तक क़ायम है तो इसकी एकमात्र वजह लोकप्रियतावादी राजनीति और किसी अन्य आधार पर समाज को गोलबंद करने में हमारे राजनीतिक दलों की नाकामयाबी है. यदि हम समाज के कमज़ोर और अधिकार विहीन तबके को ज़िंदगी की ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने में सफल हुए होते तो वही लोग आज आरक्षण की इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो चुके होते या फिर आरक्षण का मुद्दा आज भारतीय राजनीति में हाशिए पर आ चुका होता.

सच्चाई यह है कि हम आज भी सबको उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं हैं. विशेषकर उन्हें, जो समाज में हाशिए पर हैं. आरक्षण ने सामर्थ्य और योग्यता के नाम पर भारतीय समाज के विशेष अधिकार पाने वाले और विशेष अधिकार न पाने वाले वर्गों के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी है. समाज का कमज़ोर तबका ख़ुद पर शासन करने वाले तबके के मुक़ाबले स्वाभाविक रूप से सुविधाहीन है. सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि पक्षपात का लंबा इतिहास है, बल्कि इसलिए भी, क्योंकि वह लगातार दुराग्रह और दुर्भावनाओं का शिकार होता रहा है. आज़ादी के साठ साल बीत जाने के बाद भी हम समाज के सभी वर्गों के लिए उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं, जिससे कमज़ोर तबका सालों से फ़ायदे में रहने वाले तबके से बराबरी के आधार पर मुक़ाबला कर सके और इसीलिए आरक्षण का जिन्न बार-बार बोतल से बाहर आकर उछलने लगता है.

हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल की बड़ी भूमिका होती है. इसीलिए जब एक विकासशील लोकतांत्रिक समाज में कमज़ोर और अधिकारों से वंचित लोगों को परे धकेल दिया जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी संख्या की ताक़त का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं. फिर अंकों का यह खेल राजनीति पर हावी होने लगता है और सामाजिक स्तर पर संख्या बल का इस्तेमाल सामाजिक हैसियत को ऊपर उठाने के लिए होने लगता है. भारत में पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है. जाति पर आधारित राजनीतिक दलों और समूहों का देश में हुआ विकास इसी बात की पुष्टि करता है.

अगर हम पिछले कुछ समय की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि राजनीतिक पार्टियां ख़ुद में सीमित होती जा रही हैं. एक जाति विशेष की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए वे यह उम्मीद करती हैं कि इससे उनकी आकांक्षाओं को ज़्यादा अहमियत मिलेगी. इसीलिए भारतीय समाज में लोकतांत्रिक भावना और सेवाओं ने जातिगत आरक्षण का विकृत रूप धारण कर लिया. यही वजह है कि भारत जैसे बहुलवादी देश में आज गठबंधन की सरकार है, जो समाज के अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक समूहों के सहयोग से बनी है. पहचान पर आधारित राजनीति करके उक्त दल लगातार विकास कर रहे हैं. ग़ौरतलब है, पिछले कुछ समय से राजनीति का यह अंदाज़ भारत में लगातार बुलंदियों पर है.

ये सभी एक पिछड़े और पुरातनपंथी समाज के लक्षण हैं. जब तक हम समाज के सभी वर्गों को वास्तविक रूप से समानता की रेखा पर नहीं लाते, तब तक इस तरह की संकीर्ण विचारधारा हमारी राजनीति पर हावी रहेगी. किसी भी समाज के संतुलित विकास की पहली शर्त यही होती है कि मानव संसाधनों पर निवेश किया जाए. बहुत पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इस तथ्य को स्वीकारते हुए कहा था कि कम योग्यता, संकीर्ण सोच और दोहरे चरित्र वाले लोगों के साथ एक महान देश की कल्पना नहीं की जा सकती.

भले ही पहली नज़र में जाति आधारित आरक्षण नकारात्मक प्रतीत होता है, लेकिन हमारे समाज में इसकी दूसरी भूमिका भी है. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में कई ऐसे हैं, जो भारत के साथ ही विकास की राह पर अग्रसर हुए थे, लेकिन आज वे दौड़ में पीछे छूट चुके हैं, जबकि भारत दिनोंदिन एक ताक़तवर देश के रूप में उभर रहा है. इसका कारण है कि हमने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक मूल्यों के विभाजन में संतुलित रवैया अपनाने की लगातार कोशिश की है. यहां सभी वर्गों के नैतिक मूल्य आज भी जीवित हैं. जबकि इसी प्रयास में अन्य देशों को रक्तपात का सामना करना पड़ा और आज वे या तो हाशिए पर हैं या सामाजिक रूप से असफल हो चुके हैं. वहीं भारत सुदृढ़ बन रहा है और यहां सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं. इन बदलावों की गति धीमी ज़रूर है, यह एक शांतिपूर्ण क्रांति की तरह है, लेकिन इन बदलावों से लगभग सभी वर्गों के लोग संतुष्ट हैं.

हाल में आए सुप्रीमकोर्ट के उस फ़ैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, जिसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है. लेकिन इसका दायरा बढ़ा कर इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी शामिल किया जाना चाहिए. जिस तरह ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का तर्क दिया गया, उसी तरह अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों के क्रीमी लेयर को भी आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. हालांकि क्रीमी लेयर का मापदंड क्या हो, यह सवाल अभी भी तमाम विसंगतियों से जूझ रहा है और इसीलिए इसे सुधारने एवं तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है.

सुप्रीमकोर्ट का मानना है कि ग्रेजुएट लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन जिस दर से हमारे देश में ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह तर्कसंगत नहीं लगता है. हमें यह मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में तमाम तरह की ख़ामियां हैं. हमारे शिक्षा तंत्र के विभिन्न स्तरों पर जिस तरह शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जिस तरह राजनीति का खेल खेला जाता है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. राजनीतिक खींचतान से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है और इससे कई बार शिक्षा की गुणवत्ता भी पृष्ठभूमि में जाने को मजबूर होती है. राजनीतिक दख़लंदाज़ी और आपसी खींचतान ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को आज मौजूदा हाल में ला खड़ा किया है. हालांकि इसमें कई अपवाद भी हैं, लेकिन अपवाद तो अपवाद ही होते हैं. हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को इनसे छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है.

मौजूदा समय में जाति आधारित आरक्षण भले ही सुनने में बेसुरा लगे, लेकिन यह हमारे समाज की सच्चाई है और यह शायद तब तक जारी रहेगा, जब तक हम इस बात की गारंटी नहीं देते कि सभी वर्गों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समान सुविधाएं मिल रही हैं और सभी वर्गों को विकास के समान अवसर मिल रहे हैं. सभी के लिए समान अवसरों के साथ प्रगतिवादी और समतामूलक समाज का निर्माण आज हमारी ज़रूरत बन चुका है. और, ऐसा होने के बाद ही जाति आधारित आरक्षण की राजनीति के ताबूत में आख़िरी कील ठोंकने की उम्मीद की जा सकती है.

(लेखक प. बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

कैमरे के अलावा इसमें प्रयुक्त तकनीक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (मेम्स) अंतरिक्ष तकनीक केपरीक्षण में कमाल दिखाएगी.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

भ्रष्ट राशन दुकानदारों का इलाज है आरटीआई

भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत के पीछे का एक मक़सद यह भी था कि कम आय वाले लोगों और ग़रीब आदमी को दो वक़्त का भोजन नसीब हो सके, लेकिन ग़रीब लोगों का भोजन भी भ्रष्टाचारियों की गिद्ध दृष्टि से बच नहीं सका. लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ग़रीबों के हिस्से का राशन अधिकारी से लेकर राशन दुकानदार तक मिल-बांट कर खा रहे हैं. इनसे जो बच जाए, वही जनता के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन आरटीआई (सूचना कानून) के पास वह ताक़त है जिससे इन भ्रष्ट, बेईमान और असंवेदनशील राशन दुकानदारों और अधिकारियों को रास्ते पर लाया जा सकता है. बशर्ते, जनता ख़ुद जागरूक हो जाए. जंग लगी व्यवस्था से सवाल पूछ कर उन्हें अपनी ताक़त का अहसास कराएं. चौथी दुनिया आपकी लड़ाई में हर क़दम पर आपके साथ है. इस अंक में हम राशन व्यवस्था से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं. बिहार, सहरसा के निवासी सुभाष चंद्र राय ने पत्र के माध्यम से हमें सूचित किया है कि उनके गांव का राशन दुकानदार राशन बांटने में कैसे घपले करता है और तमाम शिक़ायतों के बाद भी अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. सुभाष चंद्र राय को हमारा सुझाव है कि वह इस अंक में प्रकाशित आवेदन का इस्तेमाल करें ओर हमें भी यह बताएं कि आवेदन देने के बाद से इस पूरे मामले में क्या क्या प्रगति हुई है. हमारा विश्वास है कि आरटीआई आवेदन डालते ही अधिकारी हरकत में आएंगे. आगे, यदि कोई औए समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं.

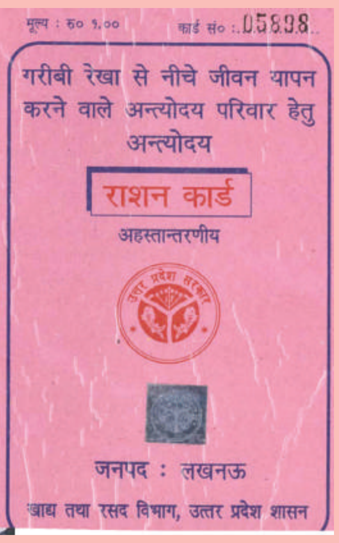

मूल्य : रु० 1.00 कार्ड सं० :.05898..

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्त्योदय परिवार हेतु

अन्त्योदय

राशन कार्ड

अहस्तान्तरणीय

जनपद : लखनऊ

खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते है तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा, सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते है या हमें पत्र भी लिख सकते है. हमारा पता है:-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेलः rti@chauthiduniya.com

सवाल–जवाब

मेरी समस्या मेरे गांव का राशन दुकानदार है जो राशन देने में लगातार हेराफेरी करता है. कभी चावल देता है तो गेहूं नहीं. कभी गेहूं देता है तो किरोसीन तेल नहीं. राशन दुकानदार की मनमर्जी इतनी ज़्यादा है कि हमें देता गेहूं है और कार्ड पर चीनी अंकित कर देता है. और जब हम इस पर आपत्ति करते हैं तो छाती ठोंक कर चुनौती के स्वर में कहता है कि जाओ, जो करना है कर लो, 20 हज़ार रुपयों में हम मामला सुलझा लेंगे. इस संबंध में मैंनें खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी और बीडीओ के यहां शिक़ायत भी की है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. चौथी दुनिया में आरटीआई कॉलम देखकर कुछ आशा जगी है.

सुभाष चंद्र राय, बघवा, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा.

सुभाष जी, इस अंक में हम राशन दुकान और राशन की मात्रा से संबंधित एक आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं. आशा है, यह आपके काम आएगा. इसके अलावा, आपने जो शिकायत बीडीओ और खाद्य आपूर्ति अधिकारी के यहां की है उस पर भी आरटीआई क़ानून के तहत एक आवेदन देकर यह पूछ सकते हैं कि अब तक आपकी शिक़ायत पर क्या कार्रवाई की गई है. अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इसकी वजह और इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के नाम और उसके पद नाम के बारे में भी पूछ सकते है.

चौथी दुनिया.

राशन दुकान और राशन की मात्रा से संबंधित आरटीआई आवेदन

दिनांक :

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी
पता...............................

विषय:-सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आवेदन.

महोदय, मै....(नाम)...(गांव का नाम) का निवासी हूं. मेरा राशन कार्ड संख्या...और राशन दुकान संख्या....हैं. कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं.

1. मेरे राशन कार्ड पर प्रत्येक महीने जारी किए गए राशन, किरोसीन तेल इत्यादि की मात्रा जो आपके रजिस्टर में दर्ज़ है, का पूर्ण विवरण निम्न सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं.
   क. महीना.
   ख. जारी किए गए राशन और किरोसीन तेल की मात्रा
   ग. तारीख़, जब राशन और किरोसीन बांटा जाना था.
2. राशन दुकान से संबंधित पिछले छह माह का निम्नलिखित ब्योरों की एक सत्यापित फोटोकॉपी भी उपलब्ध कराएं.
   क. मास्टर कार्ड रजिस्टर
   ख. प्रतिदिन की बिक्री का रजिस्टर
   ग. डेली स्टॉक रजिस्टर
   घ. मासिक स्टॉक रजिस्टर
   च. असेसमेंट बुक
   छ. कैश मेमो
3. अभी तक उक्त राशन दुकानदार के ख़िलाफ़ कितनी शिकायत दर्ज हुई है? इन शिकायतों के बाद उन पर की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें.

मै दस रूपए का आवेदन शुल्क जमा कर रहा हूं.

भवदीय
नाम-

हस्ताक्षर
पता-

ज़रा हट के

नैनो सेटेलाइट जुगनू

छह मार्च, 2010 आईआईटी कानपुर के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन था, क्योंकि संस्थान ने इसी दिन अपनी स्थापना के 50 बरस पूरे किए. यह ऐतिहासिक दिन आईआईटी कानपुर के लिए उपलब्धियों के लिहाज़ से भी यादगार बना. संस्थान ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक प्रभावी क़दम बढ़ाया. यहां के छात्रों ने देश का सबसे छोटा नैनो सेटेलाइट बनाकर उसे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सौंप दिया. इस नैनो सेटेलाइट का नाम जुगनू है. यह पूर्णतः स्वदेशी है. राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जुगनू का अनावरण करके इसे इसरो को सौंप दिया, जिस पर इसके प्रक्षेपण की ज़िम्मेदारी है. ग़ौरतलब है कि आईआईटी कानपुर का यह प्रोजेक्ट इसरो की मदद से ही चल रहा था. अब इसरो जांच करने के बाद इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा. इसके प्रक्षेपित होते ही आईआईटी कानपुर दुनिया के उन चुनिंदा शिक्षण संस्थानों में शुमार हो जाएगा, जिनका अपना सेटेलाइट होगा.

देश में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला आईआईटी कानपुर दूसरा शिक्षण संस्थान है. इससे पहले अन्ना यूनिवर्सिटी द्वारा अपना सेटेलाइट तैयार किया गया, जो 40 किलो वजनी माइक्रो सेटेलाइट की श्रेणी का था. लेकिन, पहला नैनो सेटेलाइट बनाने का श्रेय आईआईटी कानपुर को मिला. उसने यह श्रेय इसरो से भी छीन लिया. जुगनू का वज़न महज़ 3 किलो है. इसकी लंबाई 34 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है. आईआईटी कानपुर के अलग-अलग विभागों के क़रीब पचास छात्रों की एक टीम ने इसे तैयार किया है. जुगनू को तैयार करने में क़रीब एक साल का वक़्त लगा. इस प्रोजेक्ट का ज़िम्मा मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नलिनाक्ष व्यास पर था, जबकि टीम लीडर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के छात्र शांतनु अग्रवाल थे. इस बेहद पेचीदा और धीरज वाले काम को पूरा करने में छात्रों को इसरो के वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिलता रहा. जुगनू जैसा नाम है, वैसा ही इसका काम भी है. मुख्य रूप से इसका काम रोशनी से जुड़ा है. इसमें लगा कैमरा धरती के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरें खींचकर आने वालो ख़तरों से आगाह करेगा. संस्थान के कोऑर्डिनेटर प्रो. व्यास के मुताबिक़, जुगनू धरती से 600-700 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में होगा. यह एक दिन में पृथ्वी के 12 से 13 चक्कर लगाएगा. इसका इंफ्रारेड कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा. कैमरे की क्षमता सतह के कुछ मीटर भीतर तक तस्वीरें लेने की है. इससे खेती, मृदा, मृदा कटाव एवं नदियों में प्रदूषित पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी. इसकी तस्वीरें इसरो के साथ भी साझा की जाएंगी.

कैमरे के अलावा इसमें प्रयुक्त तकनीक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (मेम्स) अंतरिक्ष तकनीक के परीक्षण में कमाल दिखाएगी. यह इस सेटेलाइट का सबसे अहम हिस्सा है. इसे हम सेटेलाइट का दिमाग़ कह सकते हैं, जो सेटेलाइट को नियंत्रित करेगा. ये छोटी मशीनें एक मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से के बराबर हैं. इसके अलावा इसमें जीपीएस लगा हुआ है और आपातकाल में संचार के काम आने वाला ब्रीकन रेडियो भी. हालांकि देश में इसका इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में यह संचार के लिए बेहद मददगार है. यह इसरो के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुए नैनो उपकरणों को यहीं के छात्रों ने डिज़ाइन और डेवलप किया है. अब तक सेटेलाइट के लिए इस्तेमाल में आने वाले ऐसे ज़रूरी उपकरण बड़े साइज़ में ही इसरो द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन आईआईटी कानपुर ने इसे नैनो साइज़ का कर दिया है. माना जा रहा है कि यह आविष्कार इसरो के सेटेलाइटों के लिए भी बेहद कारगर और लागत कम करने वाला साबित होगा. डॉ. व्यास के मुताबिक़, इसी तरह इसमें दो छोटे कंप्यूटर लगे हैं, जो आईआईटी में ही डिज़ाइन और डेवलप हुए हैं. सबसे ख़ास बात यह है कि सोलर ऊर्जा से चलने वाले सेटेलाइट जुगनू को सिर्फ़ 3.5 वॉट बिजली की ही ज़रूरत पड़ेगी और इसे बनाने में क़रीब 15 लाख रुपये ही ख़र्च हुए हैं, जबकि पूरा प्रोजेक्ट क़रीब ढाई करोड़ रुपये का बताया जाता है. डॉ. व्यास का कहना है कि ख़र्चा दो करोड़ से कम हुआ है. इसमें भू-केंद्र की स्थापना शामिल है, जिसका आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा.

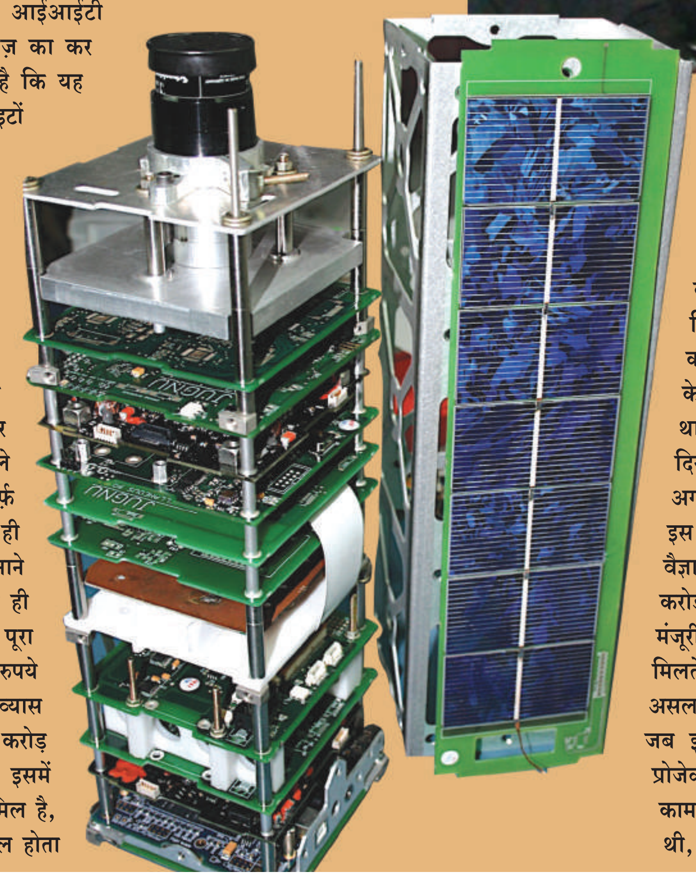

छात्रों की वह टीम, जिसने जुगनू बनाया.

इस प्रोजेक्ट को इसरो की मंजूरी अगस्त 2008 में ही मिल गई थी, लेकिन इस पर करार जनवरी 2009 में हुआ. प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक़्क़तें कम नहीं थीं. कोई भी ऐसा नहीं था, जिसने इससे पहले सेटेलाइट बनाने में काम किया हो. एक साल में दो सेमेस्टर के बीच यह छात्रों के लिए बड़ा इम्तिहान था. वे जो पढ़ रहे थे, वही उन्हें बनाकर दिखाना था. छात्रों का यह इम्तिहान अगस्त 2008 में ही शुरू हो गया था. जब इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी इसरो के वैज्ञानिकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई तो ढाई करोड़ रुपये के बजट वाले इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दिलाने में पांच घंटे लग गए. मंज़ूरी मिलते ही टीम इस अभियान में जुट गई. पर असल काम आठ जनवरी 2009 में शुरू हुआ, जब इसरो के साथ एमओयू साइन हुआ. प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि इस काम को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2010 थी, पर टीम ने ग्यारह महीने पहले ही जनवरी में इसे तैयार करके इसरो के हवाले कर दिया.

डॉ. व्यास बताते हैं कि सबसे बड़ी दिक़्क़त थी पीसीबी बोर्ड की. इसमें 25 से 30 बोर्ड लगने थे, लेकिन समस्या यह थी कि पूरी हिंदी बेल्ट में दिल्ली से पहले कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन का काम नहीं होता था. बोर्ड के डिज़ाइन तो छात्रों ने तैयार कर लिए, लेकिन इसे बनवाने के लिए दिल्ली, अहमदाबाद या फिर बंगलुरू का रुख़ करना पड़ता था. बीच में काम की रफ़्तार धीमी तब पड़ी, जब सेमेस्टर परीक्षाएं आ गईं.

हालांकि इसरो की महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान की असमय समाप्ति के बाद इस जुगनू पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे. जुगनू पर दिन-रात काम कर रहे छात्र संशय की स्थिति में थे, लेकिन उदास छात्रों ने अपने काम पर मायूसी को हावी नहीं होने दिया और जी-जान से जुगनू पर काम करते रहे. जुगनू जब तैयार होने वाला था, उस वक़्त होली की छुट्टियों में कई छात्र अपने घर भी नहीं गए. जुगनू को सौंपने के बाद अब छात्र परिसर में ही स्थापित इसके भू-केंद्र में जाकर दूसरे सेटेलाइटों के संदेशों को समझने का अभ्यास कर रहे हैं. फ़िलहाल यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में बनाया गया है, लेकिन स्थाई केंद्र परिसर में ही बनकर लगभग तैयार है. अब छात्र उस दिन के इंतज़ार में बेक़रार हैं, जब इसरो इसे अंतरिक्ष में छोड़ने का ऐलान करेगा. इस बीच उस नए सेटेलाइट पर भी कैंपस में चर्चा शुरू हो गई है, जिसे जुगनू के बाद तैयार किए जाने की योजना है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

5 अप्रैल–11 अप्रैल 2010

मेष
21 मार्च से 20 अप्रैल
व्यस्तता बढ़ेगी. निजी संबंध मज़बूत बनेंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. यात्रा-देशाटन की दिशा में प्रगति होगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. देवदर्शन के योग बनेंगे. आर्थिक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा.

वृष
21 अप्रैल से 20 मई
व्यक्ति विशेष या जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. उपहार-सम्मान मिलने की संभावना है. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी. दूर कहीं यात्रा पर न जाएं.

मिथुन
21 मई से 20 जून
रचनात्मक दिशा में किए जा रहे कार्यों में सफलता मिलेगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी. यात्रा में अपनी वस्तुओं के प्रति सचेत रहें. किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी होने या खोने की आशंका है.

कर्क
21 जून से 20 जुलाई
घर के मुखिया या संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा. व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. भागदौड़ रहेगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.

सिंह
21 जुलाई से 20 अगस्त
जीविका के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन, सम्मान, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होगी. मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है.

कन्या
21 अगस्त से 20 सितंबर
पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. रुपए-पैसे के लेनदेन में सावधानी बरतें, व्यर्थ की समस्या आ सकती है. आर्थिक मामलों में जोख़िम न उठाएं. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. चले आ रहे कार्य में सफलता मिलेगी.

तुला
21 सितंबर से 20 अक्टूबर
जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. यात्रा-देशाटन की दिशा में लाभ मिलेगा. भौतिक उपलब्धि के द्वार खुलेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में सफलता के योग बने हुए हैं. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

वृश्चिक
21 अक्टूबर से 20 नवंबर
शासन-सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. आय के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन आय और व्यय दोनों पर नियंत्रण बनाए रखें.

धनु
21 नवंबर से 20 दिसंबर
वाहन चलाने में सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना होने की आशंका है. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. भौतिक दिशा में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

मकर
21 दिसंबर से 20 जनवरी
अधूरा पड़ा हुआ कार्य पूरा होगा. मांगलिक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. किसी के विवाद में न उलझे, नहीं तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है. सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

कुंभ
21 जनवरी से 20 फरवरी
अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन उस दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें. धन, सम्मान, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. किसी कार्य में व्यस्त हो सकते हैं.

मीन
21 फरवरी से 20 मार्च
खास तौर से वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें और झगड़े से बचें. उपहार, सम्मान या अन्य प्रकार की भौतिक उपलब्धि हासिल होगी. सामाजिक दायित्व की पूर्ति होगी. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी. अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
दिल्ली, 5 अप्रैल–11 अप्रैल 2010

बलूच लोगों के अपहरण और हत्या जैसी वारदातें चरम पर पहुंच चुकी हैं. इतना ही नहीं, पुनर्वासित लोगों को भी बेघर करने जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं आम हो चुकी हैं.

बलूचिस्तान

विकास का वादा बनाम विनाश का भय

बलूचिस्तान ऑपरेशन की शुरुआत तो ग्वाडोर परियोजना की घोषणा के साथ हुई थी, लेकिन इसकी बुनियाद रखी गई हत्या, अपहरण और दिल को दहला देने जैसी वारदातों के साथ. ग्वाडोर बंदरगाह की बात तो की गई, लेकिन वादा केवल वादा ही बनकर रह गया. बलूचिस्तान में सैनिकों के लिए घर इसलिए भी बनाए गए, क्योंकि बलूच राष्ट्रवादियों के मन में कहीं न कहीं ग्वाडोर परियोजना को लेकर भय हो चुका था. जैसा कि बुगती दस्तावेज में भी उल्लेख किया गया है. बलूच राष्ट्रवादियों के इसी डर का नतीजा है कि उन्होंने इन सारी बातों की जानकारी लिखित रूप से सरकार समेत मामले से जुड़ी तमाम कमेटियों को भी दे दी थी. हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि दुर्भाग्यवश कमेटी निष्पक्ष रूप से नतीजे तक नहीं पहुंच सकी थी. आरक्षणों को देखते हुए सरकार ने बंदरगाह पर काम करना शुरू तो कर दिया, लेकिन राष्ट्रवादियों पर यह कहकर निशाना भी साधा कि वे विकास विरोधी हैं. यह भी कह डाला कि यह विरोध इसलिए है, क्योंकि उनकी संख्या कम है. बलूचिस्तान के 72 कबीलाई सरदार हमारी तरफ़ थे और बाक़ी तीन मेंगल, मेरी और बुगती हमारी विचारधारा के विपरीत थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अपने अधिकारों से वंचित न होना पड़ जाए. केंद्र सरकार और बलूचिस्तान के बीच मतभेद 1948 से शुरू हुए और यह विवाद ऐसा गहराया, जो आज तक क़ायम है. हाल की बात करें तो हालात और भी बदतर हो चुके हैं. एक ओर बंदरगाह के विकास को लेकर पहल की जा रही है तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे छलावा भी बता रहे हैं. आज बलूचिस्तान का मतभेद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है. नवाब अख्तर खान बुगती जैसे बहादुर सहित हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं. नवाबजादा बलाच, मेरी बुगती, देलरा आलम खान, डॉ. अल्लाह नज़्र और दूसरे हज़ारों बलूच नेता एवं उनके समर्थक पहाड़ों में लौट चुके हैं. अख्तर जान मेंगल, अब्दुल नाबी बंग्लोई, आलम पार्कानी, असलम गर्गानदी, लता मुनिर, जानजेब एवं रफीक खोसा समेत सैकड़ों बलूचों को जेल में भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा.

गुलाम मोहम्मद बलूच, मुनिर मेंगल एवं हसन संगत मारी जैसे हज़ारों लोगों का अपहरण कर लिया गया. सेंदक परियोजना में बलूचिस्तान को एक फ़ीसदी, चीन को 80 फ़ीसदी और केंद्र सरकार को 19 फ़ीसदी मिलने का प्रावधान है. कमज़ोर लोगों का संगठन पूनम इस सबका एक शांत गवाह बनकर रह गया है. बलूचिस्तान के पश्तून राष्ट्रवादी केवल मीडिया में बयान देने तक ही सीमित हो चुके हैं. सिंध के राष्ट्रवादी भी इन तमाम मामलों को समाचारपत्रों में विज्ञापन और बयानबाज़ी के माध्यम से भविष्य में मदद करने का वायदा कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर बलूची महिलाओं ने भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कराची से क्वेटा प्रेस क्लब तक विरोध के बिगुल को तेज़ कर दिया है. ग्वाडोर के राजस्व से एक फ़ीसदी देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. जनरल मुशर्रफ ने बंदरगाह का उदघाटन किया था. राष्ट्रवादियों ने ग्वाडोर बंदरगाह को एक धोखा करार दिया है. जम्हूरी वतन पार्टी, हक तवर, बलूचिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन, बलूचिस्तान राष्ट्रीय पार्टी और दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों ने बलूच के खोए अधिकारों को वापस दिलाने के लिए सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ कर दिया है. जाम यूसुफ ने केंद्र सरकार के प्रति अपने विश्वास को बख़ूबी जताया है. यही नहीं, बलूच के रक्षक कहे जाने वालों के साथ अंतिम दम तक लड़ने का वचन भी निभा रहे हैं. अहसान शाह जैसे लोग गुपचुप तरीक़े से बलूच समुदायों पर निशाना साधते हैं. सरदार यार मोहम्मद यह कहकर नाटकीय बर्ताव कर रहे हैं कि उनके दुश्मनों को ख़त्म किया जाए या उनके दुश्मनों की बुरी नीतियों पर अंकुश लगे. वहीं दूसरी ओर गृहमंत्री शोएब नौशरवान गिरफ़्तारियों से तो ख़ुश हैं, लेकिन पुनर्वासित लोगों को बेघर किए जाने से दुःखी भी हैं.

बलूच लोगों के अपहरण और हत्या जैसी वारदातें चरम पर पहुंच चुकी हैं. इतना ही नहीं, पुनर्वासित लोगों को भी बेघर करने जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं आम हो चुकी हैं. एमएमए और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार लूट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में कहीं भी पीछे नहीं है. वहीं सरकार के मंत्री ने भी पश्तून राष्ट्रवाद को जमकर बढ़ावा दिया है. जो लोग बलूचिस्तान के नहीं हैं, उनका वहां रहना दूभर होता जा रहा है. एमक्यूएम ने भी बलूच में अंदरूनी विवाद को हवा देने में काफी हद तक योगदान किया है. हालात यहां तक हैं कि कराची में बलूची एक–दूसरे की जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं. यही वजह है कि लेयारी एक बार फिर युद्धभूमि में तब्दील होता जा रहा है. कराची में भी बलूचियों के अधिकार के लिए आवाज़ें उठ रही हैं. यही नहीं, कराची में रह रहे बलूची भी बलूचिस्तान के प्रति अपने त्याग और बलिदान को बख़ूबी दिखा रहे हैं. ज़ाहिर है, अगर जुर्म करने वाला ही जुर्म के शिकार लोगों पर अपना आरोप थोपने की कोशिश कर रहा तो हालात क्या हो सकते हैं, इसका अंदाज़ सहज ही लगाया जा सकता है.

राष्ट्र निर्माण का काम एक नाज़ुक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए इच्छाशक्ति, साहस और एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत होती है. दूसरी ओर हमें जो देखने को मिल रहा है, वह है केवल मतभेद, गिरफ़्तारी, अपहरण, हत्या, बम विस्फोट और रॉकेट हमले. आख़िर वहां विकास किया जाए तो कैसे? सच तो यह है कि केंद्र सरकार ने भी घृणित रूप से आग में घी डालने का काम किया है. सरकार सद्भाव और स्नेह के बदले अपहरण और हत्याएं जैसे तोहफे निर्दोष लोगों के बीच बांट रही है. ज़ाहिर है, इस मारकाट भरी ज़िंदगी से तो अब लोगों को पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश शासन ही अच्छा लगने लगा है. पुराने दिनों में इस इलाक़े की सुंदरता लोगों को अभी भी याद है, जो यहां की घाटियों से लेकर झूलते हुए चिड़ियाघर और मनमोहक झरनों के रूप में फैली हुई थी. ख़ूबसूरत नज़ारे अभी भी बरक़रार हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि यहां रहने वाले इंसानों का वजूद ही आज ख़तरे में नज़र आ रहा है.

बात फिर उसी मुद्दे की करते हैं, जहां से हमने शुरुआत की थी. ग्वाडोर पोर्ट में बलूचिस्तान की केवल एक फ़ीसदी हिस्सेदारी, स्थानीय बेरोज़गार लोगों की जगह बाहर के लोगों को नौकरी, 40 सालों के लिए इस पोर्ट को सिंगापुर की एक कंपनी के हाथों में सौंप देना और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखना आख़िर कहां तक उचित है? दरअसल, इससे यह साबित होता है कि ग्वाडोर बंदरगाह बलूचियों के लिए नहीं, बल्कि केवल शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए है. इस वजह से बलूच समुदाय विकास के बजाय विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. ग्वाडोर परियोजना अभी भी एक मृग मरीचिका है.

feedback@chauthiduniya.com

कोइराला के बाद नेपाली कांग्रेस का भविष्य

आर्य सभ्यता की एक ख़ासियत है, किसी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद हम उसकी अच्छाइयों और उपलब्धियों को बढ़ा–चढ़ा कर पेश करने की कोशिश में अक्सर उसे भगवान के समतुल्य खड़ा कर देते हैं. वास्तव में हमारी संस्कृति में मृत्यु सभी बुराइयों और पापों को धोने वाली कारक बन जाती है. नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की मृत्यु के बाद उनकी याद में बहे आंसू और श्रद्धांजलियों में हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है. नज़रिया चाहे जो भी हो, लेकिन यह सत्य है कि नेपाल में चल रही शांति प्रक्रिया के मद्देनज़र और उनके स्तर के योग्य उत्तराधिकारी की कमी ने कोइराला की मृत्यु के बाद नेपाली राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है, जिसकी भरपाई मुश्किल है. कई लोगों की राय में इससे देश के नए संविधान और माओवादी लड़ाकों के भविष्य पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे हैं.

सबसे बड़ी अनिश्चितता तो नेपाली कांग्रेस के नए नेतृत्व को लेकर है. 1948 में बी पी कोइराला द्वारा नेपाली कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कोइराला परिवार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अहम हिस्सा रहा है. अपने जीवनकाल में जी पी कोइराला ने बेटी सुजाता कोइराला को पार्टी में कोइराला परिवार के अगले प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. और, मौजूदा हालत में परिवार का कोई अन्य सदस्य नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व का दावेदार बनता नज़र नहीं आता. इसे देखते हुए कोईराला की मृत्यु के बाद पार्टी को नेतृत्व देने की ज़िम्मेदारी अब उसकी दूसरी पीढ़ी के नेताओं के कंधों पर है. पार्टी के एकमात्र जीवित संस्थापक सदस्य के पी भट्टराई राजनीति से दूर हो चुके हैं. ऐसी हालत में नेपाली कांग्रेस को सहारा देने का काम पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं के जिम्मे आता है–शेर बहादुर देउबा, कार्यकारी अध्यक्ष सुशील कोइराला और संसदीय दल के नेता रामचंद्र पौडेल. यदि उक्त तीनों मिलकर प्रयास करें, तभी देश की इस सबसे पुरानी और बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के कायाकल्प की कोई संभावना बनती है. तीनों नेता इसके लिए तैयार हो भी जाएं, तब भी जी पी कोईराला के नेतृत्व क्षमता की कमी आने वाले कई सालों तक महसूस होती रहेगी.

नेपाल के दूरगामी हितों के नज़रिए से एक लोकतांत्रिक और केंद्रीय शक्ति के रूप में नेपाली कांग्रेस का पुनरुद्धार बेहद अहम है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखें तो पार्टी के नए नेतृत्व का चरित्र कैसा हो, यह विचारणीय प्रश्न है. पार्टी के नए नेतृत्व, चाहे वह एकल हो या बहुल, में नैतिक आधार, दूरदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता समय की मांग है. व्यक्तिगत गुणों–अवगुणों की अपनी अहमियत है. हालांकि नेतृत्व के मौजूदा दावेदारों पर नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादा आशावान नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है. तीन बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके शेर बहादुर देउबा 1990 के दशक के अंत तक एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे. उनकी सादगी, मिलनसार स्वभाव और स्वच्छ छवि ने आम जनता का ध्यान खींचा, लेकिन तबसे लेकर अब तक स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं. अब देउबा न केवल अमीर बन चुके हैं, बल्कि उनकी जीवनशैली और व्यवहार में भी बदलाव आ चुका है. अब वह आम लोगों से ज़्यादा मिलने–जुलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सुविधाभोगी बन चुके हैं. जिस तरह जी पी कोईराला अपने जीवनकाल में बेटी को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करते रहे, उसी तरह देउबा भी अपनी पत्नी को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. कोइराला के साथ उनकी जुगलबंदी भी फलदायक नहीं रही, क्योंकि देउबा पार्टी के संसदीय दल के नेता पद के लिए हुए चुनाव में हार गए. इसके बाद उनके कई समर्थक भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नज़रों में उनकी विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है. देउबा यदि अपने रवैये में सुधार लाएं तो उनके लिए संभावनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं.

सुशील कोइराला की छवि बेदाग़ है, लेकिन उनकी सांगठनिक क्षमता संदेह के दायरे में है. पिछले दो दशकों में कई बार उन्होंने केंद्र में मंत्री पद से इंकार किया तो इसकी वजह उनकी त्याग की भावना नहीं थी, बल्कि मंत्रालय चला पाने के प्रति वह आश्वस्त नहीं थे. पार्टी में अपने विरोधियों को किनारे लगाने के लिए साजिशें रचने में कई बार उनका नाम आया है. कई लोग उन्हें नेतृत्व के लायक़ नहीं मानते, फिर भी जी पी कोइराला के समर्थक माने जाने वाले कई पार्टीजन उनकी सादगी के चलते उन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार हो सकते हैं. रामचंद्र पौडेल में काफी संभावनाएं दिखती हैं. उनके पास ज्ञान का भंडार है और पार्टी की विचारधारा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है. हाल के दिनों में उन्होंने माओवादियों के व्यवहार और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाकर साहस का परिचय भी दिया है. लेकिन, उनका अस्थिर व्यक्तित्व और पार्टी में उनके समर्थकों की कम संख्या उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा है.

यदि उक्त तीनों नेता अपनी कमज़ोरियों को दरकिनार करते हुए एक–दूसरे का सहयोग करें तो नेपाली कांग्रेस में नेतृत्व की समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन चीज़ें देखने में जितनी आसान लगती हैं, उतनी वास्तव में होती नहीं हैं. सुशील कोइराला और रामचंद्र पौडेल का धड़ा पिछले कुछ समय से पार्टी को सामूहिक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देउबा अभी भी इस दायरे से बाहर हैं. यदि वह अपनी जिद पर अड़े रहे तो यह न केवल ख़ुद देउबा के लिए आत्मघाती हो सकता है, बल्कि पार्टी के लिए भी नुक़सानदायक है. पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे अर्जुन नरसिंह केसी, रामचरण महत, नरहरि आचार्य, प्रकाशमान सिंह एवं विमलेंद्र निधि आदि भी सामूहिक नेतृत्व की इस विचारधारा में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं.

वास्तविकता तो यह है कि जी पी कोइराला के दौर को छोड़कर नेपाली कांग्रेस में शुरू से ही सामूहिक नेतृत्व प्रचलित रहा है. स्थापना के दिनों में इसका नेतृत्व मातृका, बी पी और सुबर्ण शमशेर की तिकड़ी के हाथों में था. इसके बाद 1983 में बी पी कोइराला की मृत्यु से पहले तक बी पी, गणेशमान और के पी के हाथों में कमान थी, जबकि इसके बाद गणेशमान, के पी और जी पी कोइराला ने मोर्चा संभाला. पार्टी के इस सामूहिक नेतृत्व के खाते में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, जैसे 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत, 1959 के चुनावों में प्रभावशाली जीत, 1980 में जनमत संग्रह और 1990 में लोकतंत्र की वापसी. ईमानदारी से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सामूहिक नेतृत्व की यह अवधारणा पार्टी के अलावा देश के लिए भी काफी फ़ायदेमंद रही है. पुराने दौर के उन महान नेताओं के मुक़ाबले आधुनिक दौर के इन स्वार्थी नेताओं से ज़्यादा उम्मीदें लगाना बेमानी है. फिर भी यदि इन नेताओं का व्यक्तिगत अहं उन्हें पार्टी और देशहित में एक मंच पर आने से रोकता है, तो वे इतिहास के पन्नों से प्रेरणा ले सकते हैं.

अच्युत वागले
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक नेपाल के वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक हैं)

VARSHA
Unisex Salon & Spa
•Rebonding •Streaking
•Perm •Color Touch-up
•Hair Spa •Facial
•Bleach •Pedicure
•Manicure •Waxing
•Bridal &
Pre-bridal Make-up
•Party Make-up
14, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi
Tel: 26329688/89/90
Email: varshasalonandspa@gmail.com

चौथी दुनिया

प्रेम और करुणा की वर्षा करते हैं साई : गजेंद्र चौहान

विकास कपूर

बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत में ज्येष्ठ पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले गजेंद्र चौहान से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वापर युग के धर्मराज युधिष्ठिर से ही मिल रहे हों. बातचीत में सादगी, विचारों में स्पष्टता और सत्य के प्रति कठोर निष्ठा ही गजेंद्र चौहान को औरों से अलग कर देती है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं उसके राजनीतिक अभियानों को पूरा समय देने वाले गजेंद्र फ़िल्म इंडस्ट्री में भी हर दिल अजीज़ हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि फ़िल्मों में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने वाले गजेंद्र चौहान जब ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तो फ़िल्म दाग़ देखने के कारण उन्हें अपने पिता के गुस्से का शिकार होना पड़ा था. फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में गजेंद्र ने भी कठोर संघर्ष किया, लेकिन परमेश्वर की कृपा एवं गजेंद्र की सच्चाई को आख़िर में विजय मिली और एक समय गजेंद्र ने केवल 27 दिनों में 34 फ़िल्में साइन कीं. गजेंद्र द्वारा अभिनीत फ़िल्मों में *मेरे जीवन साथी, धड़कन, बाग़वान, परवाना, अंदाज़, तुमको न भूल पाएंगे, गुमनाम है कोई, इंटरनेशनल खिलाड़ी, राजा की आएगी बारात, हिम्मतवर और डांसर* आदि प्रमुख हैं. महाभारत के अतिरिक्त जिन धारावाहिकों में गजेंद्र ने अभिनय किया, उनकी सूची बहुत लंबी है. ऐसा कहा जाता है कि भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में अब तक जितने भी सफल धारावाहिक बने हैं, उनमें गजेंद्र ने अभिनय अवश्य किया है. गजेंद्र चौहान साई बाबा के सच्चे भक्त हैं. पिछले दिनों उनसे उनकी साई भक्ति पर एक लंबी बातचीत हुई. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

ॐ साई राम गजेंद्र भाई!

ॐ साई राम.

सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनने के लिए ढेर सारी बधाई.

धन्यवाद.

अपने जीवन में आप साई बाबा की कृपा का अनुभव किस प्रकार करते हैं?

मैं मुंबई आने के बाद बहुत समय तक शिरडी नहीं गया. पहली बार शिरडी जाने का सौभाग्य तब मिला, जब मेरा बेटा बारहवीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था और उसने साई बाबा से मन्नत मांगी कि उसकी मेहनत और बाबा की कृपा से यदि उसके 90 प्रतिशत से अधिक मार्क्स आएंगे तो वह शिरडी जाएगा. उसकी मेहनत और साई की कृपा रंग लाई, शमशेर 92 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुआ. हम सपरिवार शिरडी गए. यह मेरी पहली शिरडी यात्रा थी. बाबा के दर्शन पाकर मैं निहाल हो गया. उनकी आंखों से प्रेम और करुणा की वर्षा हो रही थी.

उसके बाद तो आपका लगातार शिरडी जाना शुरू हो गया होगा?

शमशेर ने जब मेडिकल की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, तब हम दोबारा शिरडी गए. वह दीवाली का समय था और हमें बताया गया कि शिरडी में इतनी भीड़ होगी कि दर्शन के लिए कम से कम तीन दिन लग जाएंगे. मुझे लौट कर मुंबई पहुंचना था. मन में प्रश्न था कि कहीं बाबा के दर्शन किए बिना ही न लौटना पड़े. रास्ते में हम एक होटल में चाय पीने रुके तो एक देहाती से दिखने वाले आदमी ने हमें आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा कि मन के प्रश्नों को भुलाकर सच्ची श्रद्धा से शिरडी जाओ, साई तुम्हें दर्शन ज़रूर देंगे. मैं उसकी बात पर चकित था, परंतु और अधिक चकित तब हुआ, जब शिरडी पहुंचते ही भारी भीड़ के बाद भी मुझे बाबा के पावन दर्शन मिल गए.

आपको क्या लगता है, चाय की दुकान पर जो व्यक्ति आपको मिला था, वह साई बाबा ही थे?

भले ही वह स्वयं साई न हों, परंतु उनका कोई भक्त अथवा प्रेरित किया हुआ व्यक्ति ज़रूर था.

बाबा को देखकर आपके भीतर कैसी अनुभूति होती है?

ऐसा लगता है, मानों वह बड़े प्रेम से अपने पास बुला रहे हों और उनके पास पहुंचते ही हमारे दु:ख–दर्द सब ग़ायब हो जाते हैं. ॐ साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

हमारी भक्ति

साईबाबा के जीवन और सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से सम्बन्धित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साईभक्त के विचार यहां प्रकाशित किये जायेंगे.

आज का विषय : शिरडी यात्रा से जीवन में क्या सुख मिलता है?

आपके जवाब

1. तीर्थयात्रा तो सुखकर ही होती है, शिरडी के साईबाबा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेते हैं, इतना ही नहीं समाधि मंदिर में बाबा के पार्थिव के दर्शन के बाद मन में भक्ति, श्रद्धा और सबुरी की दृढ़ भावना जन्म लेती है. इतना ही नहीं शिरडी पहुंचकर भक्त को बाबा के पार्थिव के नहीं बल्कि साक्षात् दर्शन होते हैं और भक्तों का जीवन सुखकर हो जाता है.

देवेन्द्र गुप्ता, *कानपुर, उत्तर प्रदेश (सर्वश्रेष्ठ विचार)*

2. शिरडी धाम में बिना साईबाबा की इच्छा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता और जिसे बाबा की अनुमति मिल जाती है उसके जीवन में केवल सुख ही सुख की वर्षा होती है.

मीनाक्षी माथुर, *फतेहपुर–उत्तर प्रदेश.*

3. मैं अब तक शिरडी नहीं जा पाया हूं लेकिन उसके बारे में अपने दोस्तों से बहुत सुना है कि वहां जाकर ज़िन्दगी का हर सुख बाबा की दुआ से मिल जाता है. मैं प्रतिदिन बाबा को सलाम करता हूं और दुआ मांगता हूं कि वे मुझे शिरडी आने की इजाजत दे जिससे मेरा जीवन सुखमय हो.

अरशद ख़ान, *पटना–बिहार*

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साईबाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर–17517, मोतीलाल नगर नम्बर–1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई–58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999989427 पर एसएमएस करें.

अगले सप्ताह का विषय

क्या महासमाधि के बाद भी साईबाबा भक्तों को दर्शन देते हैं?

माला संस्कृति की संस्कृति

आजकल राजनीतिक गलियारों में माला संस्कृति की गूंज काफी तेज़ी से सुनाई दे रही है. इस गूंज में सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि माला अपना स्वरूप बदल रही है. कुछ समय पहले तक फूलों से बनी माला ही अपने आराध्य, गुरु अथवा किसी राजनेता को पहनाने की परंपरा थी, परंतु अचानक फूलों की सुगंध बिखेरती माला का भी बाज़ारीकरण हो गया और फूल के स्थान पर नोट गूंथे जाने लगे. अब प्रश्न यह उठता है कि माला संस्कृति की शुरुआत कब और कैसे हुई? प्राचीन भारतीय इतिहास में इस चिर परिचित माला संस्कृति के कई दिलचस्प उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं. त्रेता युग के प्रवर्तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के संबंध में माला से जुड़ी कई कथाएं हैं, परंतु ऐसा कभी कहीं नहीं पढ़ने को मिलता कि पुष्प अथवा किसी अन्य द्रव्य से बनी माला श्रीराम को पहनाई गई हो. श्रीराम ने विशेष रूप से वनवास काल में अपने हाथों से पुष्पों की वेणी गूंथकर अपनी प्रिया सीता जी के बालों में लगाई थी. एक और उदाहरण मिलता है कि श्रीराम का आश्रय पाकर वानरराज सुग्रीव ने जब अपने पराक्रमी भाई एवं सूर्यभक्त बालि को ललकारा और उसके पराक्रम से बुरी तरह आहत होकर युद्ध में पीठ दिखाकर भागे, तब श्रीराम ने उन्हें पुन: बालि से युद्ध करने की प्रेरणा दी और बताया कि तुम दोनों के मध्य इतनी अधिक समानता थी कि मैं बालि पर लक्ष्य ही नहीं साध पाया. दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए श्रीराम ने अपने हाथों से फूलों की माला गूंथी और सुग्रीव के गले में डाल दी. इसी पुष्प माला के कारण श्रीराम सुग्रीव एवं बालि में स्पष्ट अंतर कर पाए और उन्होंने अपने तीर का संधान कर बालि का वध किया.

द्वापर युग के प्रवर्तक योगीराज श्रीकृष्ण भी प्रतिदिन कुंद पुष्पों की वेणी अपनी प्रिया राधा रानी के केशों में लगाने के लिए गूंथा करते थे. कंस वध के लिए श्रीकृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आ गए, तब उनके विरह में तड़पती राधा रानी ने कुंद पुष्पों की एक माला गूंथ कर यमुना में प्रवाहित कर दी. देवयोग से उस समय श्रीकृष्ण मथुरा में यमुना तट पर अपने प्रिय सखा उद्धव के साथ बैठे थे. तभी उन्हें राधा रानी की माला बहती दिखाई दी. श्रीकृष्ण ने उद्धव से जब उस पुष्प माला का उल्लेख किया तो ब्रह्म की सत्ता मानने वाले उद्धव ने उनसे परिहास शुरू कर दिया. उद्धव का कहना था कि ऐसी मालाएं मथुरा की मालिनें प्रतिदिन गूंथती हैं. इस बात का क्या प्रमाण है कि यमुना में बहती यह माला आपकी प्रिया राधा रानी ने गूंथी है? तब श्रीकृष्ण ने कहा कि राधा की माला पथभ्रष्ट नहीं हो सकती और सचमुच वह माला पानी में बहती हुई श्रीकृष्ण के चरणों में आ लगी. उस माला को हाथ में लेकर श्रीकृष्ण राधा रानी की मधुर यादों में खो गए. उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, परंतु राधा–कृष्ण के इस अलौकिक प्रेम का रहस्य ब्रह्म को समझ लेने वाले परम विद्वान उद्धव नहीं समझ पाए. तब श्रीकृष्ण की प्रेरणा से राधा रानी को ब्रह्म का महत्व समझाने के लिए उद्धव ने वृंदावन एवं बरसाने की यात्रा की और उनका ब्रह्म तिरोहित हो गया. वह राधा रानी से भेंट के बाद राधा–कृष्ण के सच्चे उपासक बन गए.

परंतु प्रश्न यह उठता है कि प्रेम और आदर भावना की प्रतीक पुष्पमाला का बाज़ारीकरण कब और कैसे हुआ? शायद इस कलियुग में पुष्पमाला ने अपना स्वरूप बदला होगा, क्योंकि उससे पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता. कई जगहों पर रत्नों की बहुमूल्य माला का उल्लेख है. ऐसी ही एक माला लंकाधिपति विभीषण ने अयोध्या की महारानी सीता जी को भेंट की थी, जो उन्होंने बजरंगबली को उपहार स्वरूप दे दी थी, परंतु उसमें अपने सीता–राम को ढूंढते बजरंगबली ने उसके मनकों को चबा–चबाकर तोड़ डाला था. शिरडी के साई बाबा ने भी अपने जीवन में कई बार अपने भक्तों से पुष्पों की माला ग्रहण की है, परंतु प्रमाणित है कि बाबा कभी भी पुष्प की माला के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य से बनी माला स्वीकार नहीं करते थे. परंतु आजकल के राजनेताओं को पुष्पमाला में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है. वे तो द्रव्यों से बनी मालाएं पहनने के लिए उत्साहित रहते हैं. जिस देश की आधी से अधिक आबादी आज भी मुश्किल से एक समय का खाना खा पाती हो, उस देश के राजनेता यदि द्रव्यों से बनी मालाएं पहनें तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है. साईभक्तों, शिरडी साई बाबा फाउंडेशन का साई भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है. हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साईचरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साई भक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साईभक्ति को और अधिक दृढ़ करने और सदगुरू साई समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम साईभक्त......................और फोन नंबर................कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें. ॐ साई राम.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

Giriraj Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

हमारे मीडियाकर्मी भी क्यों पीछे रहते. उन्होंने शीर्षक दिया रामनवमी पर लाखों ने लगाई डुबकी और नीचे डबल कॉलम ख़बर लगाई कि घाट सूने रहे, रास्ते ख़ाली, लागू रहा ट्रैफिक प्लान. यानी चित भी मेरी पट भी मेरी.

मक़बूल पर फ़िदा क्यों हों?

अनंत विजय

जब मैंने मक़बूल फ़िदा हुसैन के भारत छोड़ने और क़तर की नागरिकता स्वीकार करने पर सेक्युलरवादियों के दोहरे चरित्र को उजागर करता हुआ लेख चौथी दुनिया में लिखा तो मेरे विवेक और मेरी समझ, मेरी विचारधारा, मेरी शिक्षा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. मुझे कालिदास का कुमारसंभव पढ़ने और खजुराहो की प्रसिद्ध मूर्तियां देखने–समझने के अलावा प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने का उपदेश दिया गया. मुझे इस बात पर घेरने की कोशिश की गई कि मेरी बातें भगवा ब्रिगेड या संघियों से क्यों मिलती–जुलती हैं. जिन लोगों ने मुझे इस तरह की सलाह दी, मुझे नहीं मालूम कि उनकी समझ कितनी बेहतर है और उन्होंने कालिदास को कितना पढ़ा है. उन्होंने कितनी बार खजुराहो की मूर्तियां देखी हैं, लेकिन उन्हें मैं यह बता दूं कि हुसैन ने अपनी जीवनी और अपनी एक पेंटिंग दस्तख़त करके मुझे भी दी है, जो मेरे लिए अमूल्य धरोहर है. हुसैन की पेंटिंग को समझने का दावा करने वाले उनके तथाकथित समर्थकों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर घोर चिंता है और उन्हें लगता है कि हुसैन के भारत छोड़ कर चले जाने से संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार पर हमला हुआ है. उन्हें यह सोचने–समझने की भी ज़रूरत है कि जब भी कोई अपने आपको अभिव्यक्त करने के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता की अपेक्षा करता है तो स्वत: उससे ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार भी अपेक्षित हो जाता है. भारत माता की नंगी तस्वीर बनाने पर हुसैन के ख़िलाफ़ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने ख़ारिज कर दिया, साथ ही अपने फ़ैसले में कला और उसकी समझ को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियां भी कीं. लेकिन हुसैन द्वारा उन्नीस सौ सत्तर में बनाई गईं सरस्वती और दुर्गा की नंगी तस्वीरों के एक दूसरे मामले में वर्ष 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जे डी कपूर का भी एक फ़ैसला आया था. उन्होंने आठ अप्रैल 2004 के अपने फ़ैसले में लिखा, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि देश के करोड़ों हिंदुओं की इन देवियों में अटूट श्रद्धा है. एक ज्ञान की देवी हैं तो दूसरी शक्ति की. इन देवियों की नंगी तस्वीर पेंट करना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो है ही, साथ ही उनके धर्म और आस्था का भी अपमान है.

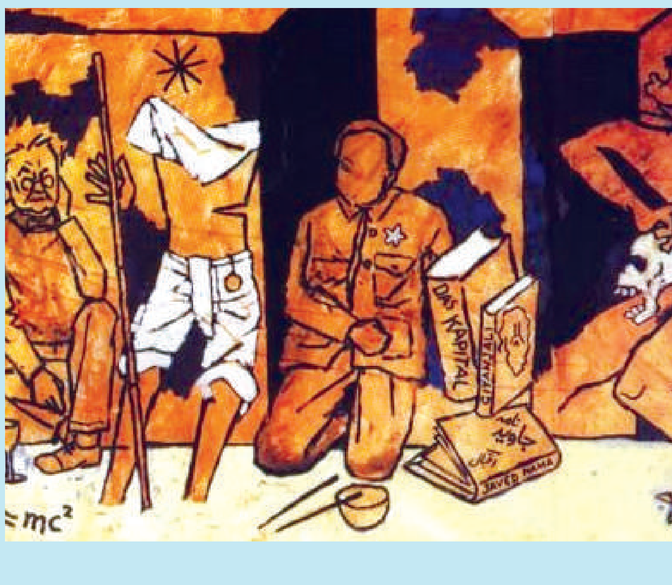

शब्द, पेंटिंग, रेखाचित्र और भाषण के माध्यम से अभिव्यक्ति की आज़ादी को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्ज़ा हासिल है, जो हर नागरिक के लिए अमूल्य है. कोई भी कलाकार या पेंटर मानवीय संवेदना और मनोभाव को कई तरीक़ों से अभिव्यक्त कर सकता है. इन मनोभावों और आइडियाज़ की अभिव्यक्ति को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है. लेकिन कोई भी इस बात को भुला नहीं सकता कि जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता होगी, उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी होती है. अगर किसी को अभिव्यक्ति का असीमित अधिकार मिला है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि इस अधिकार का उपयोग वह अच्छे काम के लिए करे, न कि किसी धर्म या धार्मिक प्रतीकों या देवी–देवताओं के ख़िलाफ़ विद्वेषपूर्ण भावना के साथ उन्हें अपमानित करने के लिए. हो सकता है कि उक्त धार्मिक प्रतीक या देवी–देवता एक मिथक हों, लेकिन इन्हें श्रद्धाभाव से देखा जाता है और समय के साथ ये लोगों के दैनिक–धार्मिक क्रियाकलापों से इस कदर जुड़ गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ अगर कुछ छपता है, चित्रित किया जाता है या फिर टिप्पणी की जाती है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती ही हैं. किसी भी धर्म के देवी–देवताओं की आपत्तिजनक या नीचा दिखाने वाली तस्वीरें या पेंटिंग समाज में रोष और एक–दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा करती हैं.

अगर यह मान लिया जाए कि इस तरह की तस्वीरें कला का एक नमूना भर हैं, तब भी इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि इस तरह के कृत्य जानबूझ कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या फिर अपमानित करने के दायरे में ही आते हैं, क्योंकि ये देवी–देवता करोड़ों लोगों के आराध्य हैं. एक बार फिर मैं यह कहता हूं कि ये देवी–देवता एक मिथक हो सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह से नग्न रूप में उनको चित्रित किया जाता है तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या समाज की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती है. यह बात याचिकाकर्ता (हुसैन) को समझनी चाहिए कि वह एक अलग धर्म से संबंधित हैं.

अगर याचिकाकर्ता को लोगों की धार्मिक भावनाओं की गहराई का एहसास नहीं है तो वह अपने धर्म या फिर किसी और धर्म पर हाथ आज़माकर देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि धार्मिक भावनाओं की जड़ें कितनी गहरी होती हैं. इस तरह के काम दो अलग–अलग धर्मों को मानने वालों के बीच वैमनस्य की खाई को और गहरा करते हैं. साथ ही सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के बीच बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं. याचिकाकर्ता ने महाभारत की पात्र द्रौपदी, जिन्हें हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं, को भी पूरी तरह से निर्वस्त्र चित्रित किया है, जबकि चीरहरण के वक़्त भी द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई थीं. इस पेंटिंग में जिस तरह से द्रौपदी का चित्रण हुआ है, वह साफ़ तौर से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नफ़रत पैदा करने वाला है. अपने बारह पन्नों के फ़ैसले में विद्वान न्यायाधीश ने और भी कई बातें कहीं और अंत में शिक़ायतकर्ताओं की याचिका ख़ारिज कर दी. धार्मिक भावनाओं को भड़काने, दो समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने आदि के संबंध में जो धाराएं (153 ए और 295 ए) लगाई जाती हैं, उनमें राज्य या केंद्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, जो इस मामले में नहीं थी. आप को शायद याद होगा कि जब यह मुक़दमा चल रहा था तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी. यह तो हुई अदालत और न्यायाधीश की बात. आपको एक और उदाहरण देते चलें, जिससे हुसैन की महानता (?) और उनके पूर्वाग्रह से परदा हटता है. हुसैन ने एक बार महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, अलबर्ट आइंस्टीन और हिटलर की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें हिटलर को उन्होंने नंगा दिखाया था. जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी को अपमानित करने का यह उनका अपना तरीक़ा है. उनकी इस टिप्पणी के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ और कहने की ज़रूरत है. मार्क्स के अंधभक्तों, धर्म निरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़तरे पर विलाप करना बंद करो. अपनी आंखों पर चढ़ा लाल चश्मा उतारो, तभी तर्कसंगत बातें भी होंगी और विमर्श भी.

(जस्टिस कपूर के जजमेंट के चुनिंदा अंशों के अनुवाद में हो सकता है कि कोर्ट की भाषा में कोई त्रुटि रह गई हो, लेकिन भाव वही हैं)

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

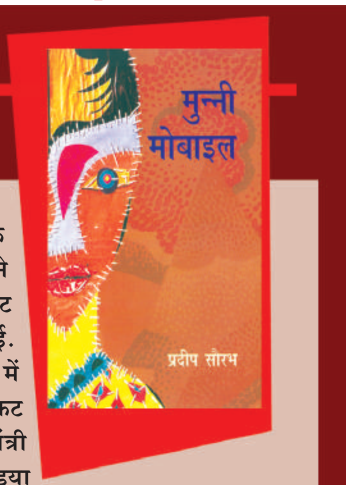

प्रदीप सौरभ

मोदी को अक्षरधाम के रूप में एक और मुद्दा मिल गया था. मोदी आग उगलते घूम रहे थे. उनकी आग को अक्षरधाम पर आतंकी हमले ने और धधका दिया. हमले के बाद मोदी ने गुजरात की अस्मिता के सवाल को और ज़ोर से उठाया. पाकिस्तान को धमकी दी. मियां मुशर्रफ को ललकारा. इस तरह उन्होंने धर्म के साथ देशभक्ति का मसाला भी अपने भाषणों में भर दिया. इस मशक़्क़त ने आत्मविश्वास खो चुके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया.

मोदी के रंगबिरंगे आधी बांह के कुर्ते भी अब तक लोगों में लोकप्रिय हो चुके थे. डिज़ायनरों ने उसे मोदी कट का नाम दिया था. उनकी हर अदा पर लोग दीवाने हो गए थे. मोदी को देखने, छूने और सुनने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही थी. अपने को विशेष लुक में पेश करने के शौक़ीन मोदी कभी कार्टियर का चश्मा पहन कर पेश होते, कभी पगड़ी. तलवार दिखाते वक़्त तो उनके अंदर शिवाजी प्रवेश कर जाते. वैसे भी मोदी शौक़ीन मिजाज़ आदमी हमेशा से रहे हैं. गांव में और जब वह स्टेट ट्रांसपोर्ट की कैंटीन में काम करते थे, तो भी अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखते थे. गांव में अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए वह लोटे में कोयला डाल कर प्रेस किया करते थे. जूते–चप्पल भी उनके पास सैकड़ों हैं. संघ परिवार के प्रचारक वाले उनमें कोई गुण नहीं हैं. मोदी की नौटंकी जारी थी. मोदी को मुख्यमंत्री बने एक साल पूरा हो चुका था. मोदी के पास उपलब्धि के नाम पर गोधरा कांड और अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला ही था. इस दौरान सैकड़ों लोगों को ज़िंदा जलाने का कीर्तिमान भी गुजरात में पहली बार स्थापित हुआ. मोदी राज में विचार और बहस की जगह त्रिशूल और तलवारों ने ले ली. हिंदू ब्रिगेड से असहमति राज्य में एक अपराध है. मीडिया को भी उनकी भाषा बोलने के लिए बाध्य किया जाता रहा. नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकियां खुलेआम दी जा रही थीं. इन्हीं उपलब्धियों के साथ मोदी गांधीनगर दोबारा पहुंचना चाहते थे.

देरी थी तो चुनाव के ऐलान की. आख़िर वह दिन भी आ गया. 12 सितंबर को मतदान की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी. हिंदू ब्रिगेड ज़ोर–शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई. कांग्रेस ने भी नरम हिंदू कार्ड खेला. मोदी के प्रचार में नाटकीयता बढ़ गई थी. उनकी प्रस्तुति हिटलर, बाला साहेब ठाकरे और अमिताभ बच्चन की कॉकटेल थी. हिटलर की तरह वह बहुसंख्यक समुदाय को डराते, बाला साहेब ठाकरे की तरह फतवे जारी करते और अमिताभ बच्चन की तरह भावुक अभिनय करते.

चुनाव प्रक्रिया के दौरान मोदी की पार्टी में अपने विरोधियों से भी ख़ूब ठनी. पार्टी के बड़े नेताओं केशुभाई से लेकर हरेन पंडया और कांशीराम राणा तक वह सबसे भिड़े. सबको उन्होंने उनकी औकात दिखाई. टिकट बंटवारे में उन्होंने अपनी चलाई. केशुभाई पटेल के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री रहे हरेन पंडया का टिकट उन्होंने काट दिया. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंडया को टिकट देने की अपील को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया. मोदी पार्टी से ऊपर उठ चुके थे. उनमें गुरूर कूट–कूट कर भर चुका था.

अंतत: 12 दिसंबर को मतदान हो गया. 15 दिसंबर 2002 को मतपेटियां जब खुलने लगीं तो भारतीय जनता पार्टी की आंधी उससे बाहर आई. गुजरात में कमल खिल चुका था. जीत पार्टी की नहीं, मोदी की हुई थी. लेकिन एक बार मोदी ने फिर पैंतरा बदला. जीत के बाद जब वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रकट हुए तो भावुक होकर बोले, पार्टी मां की तरह होती है. उससे ऊपर कोई नहीं होता.

feedback@chauthiduniya.com

तीन चौथाई कुंभ ऐसे ही निबट गया है

डॉ. कमलकांत बुधकर

हरिद्वार का महाकुंभ 2010 जैसे तैसे तीन चौथाई निबट चुका है. मुख्य स्नान शेष है जो अगले पंद्रह दिनों में संपन्न हो जाएगा और तब मेले का प्रशासन और पुलिस दोनों ही लंबी तान लेंगे. 14 अप्रैल की सुबह सवेरे सूर्य मेष राशि में संक्रमण करेंगे. चंद्र भी तब मेष में होंगे और गुरु तो कुंभ राशि में 21 दिसंबर से ही चल रहे हैं. 14 की सुबह जैसे ही सूर्य मेष में आएंगे वैसे ही पुराणचर्चित कुंभ का ज्योतिषीय योग उपस्थित हो जाएगा जो कहते हैं प्राणि मात्र के लिए मांगलिक होगा. ऐसे मांगलिक क्षणों में गंगा के तटों पर एकत्र होकर स्नानादि करना हर आस्तिक हिंदू की साध होती है. इसी साध को पूरा करने के लिए लोकप्रिय सरकारें कुंभ जैसे महामेलों के लिए व्यवस्थाएं करती हैं. सड़कें बनाती हैं, पुल बनाती हैं, शिविर लगाती हैं, अस्पताल, राशन की दुकानें, विभिन्न सहायता काउंटर खोलती हैं, बिजली पानी की व्यवस्था करती हैं, अतिरिक्त बसों–रेलों का संचालन करवाती हैं और सर्वोपरि आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े ख़र्चीले प्रबंध करती है.

उत्तराखण्ड सरकार ने भी यह सब किया. कुछ ख़ुद किया और कुछ उधार मांग कर, सहायता की याचना करके किया. महीनों तैयारियां हुईं. मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों की मॉनीटरिंग तले चले अभियान, दर्ज़नों सचिवों और आला अफ़सरों की तैनाती, उनके पचासों दौरे, सैकड़ों अधीनस्थ अफ़सर, हज़ारों सुरक्षाकर्मी, लाखों के बजट और करोड़ों अरबों का गुणाभाग. सब कुछ हुआ पर कुंभनगर की सड़कें ठीक से न बन पाईं. ललतारौ से लेकर हरकी पौड़ी तक की मुख्य सड़क तो बनी ही नहीं. जो सड़कें बनीं उनकी गुणवत्ता प्रश्नों के घेरे में आ गई. प्रश्नों के जवाब नदारद हैं और महाकुंभ तीन चौथाई निबट चुका है. बिजली पर करोड़ों ख़र्च हुए पर शाही और पेशवाई की बात तो दूर छोटा सा जुलूस भी निकल जाए तो इलाक़े की बिजली गुल कर दी जाती है. कारण सिर्फ़ यह है कि विभाग को अपने किए पर विश्वास ही नहीं है. उपभोक्ता बिजली का उपभोग करेंगे तो समस्या आ सकती है. बिजली ही नहीं होगी तो समस्या आएगी ही नहीं! सांप ही नहीं होगा तो लाठी टूटने का प्रश्न ही नहीं है. मुख्य स्नान दिवसों पर शहर बिना बिजली के तड़पता रहा है और तीन चौथाई महाकुंभ ऐसे ही बीत गया है.

कुंभ का स्वास्थ्य विभाग सर्वाधिक नाकारा सिद्ध हो रहा है. फिर भी स्वास्थ्यकर्मियों की सारी मांगें मानी जा रही हैं. इसके बावजूद सारा कुंभ नगर गंदगी से अटा पड़ा है और अफ़सरों और मातहतों का तालमेल ऐसा है कि स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल की धमकी देते या हड़ताल करते ही नज़र आते हैं अक्सर. तीन चौथाई कुंभ बीत चुका है ऐसे ही, बाक़ी भी बीत ही जाएगा.

पानी की स्थिति तो यह रही है कि साधुसंतों के अखाड़ों और शिविरों में ही कई कई दिन तक पानी नहीं आया तो कनखल, ज्वालापुर जैसी बस्तियों की कौन सुने. बड़े अतिक्रमण क्या छोटे मोटे ठेली खोमचे तक मुख्य मेला दिवसों पर यात्री मार्गों में अवरोध पैदा करते रहे. अलबत्ता साधु संतों के जुलूसों के लिए आम जनता को जमकर परेशान किया गया. शासन प्रशासन ने स्नान दिवस तो ढेर सारे घोषित कर दिए पर स्नानार्थियों को उनके गंतव्य हरकी पौड़ी तक जाने ही नहीं दिया गया. जो धक्के खा खाकर कई कई घंटों में वहां पहुंचे भी उन्हें व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर घाटों और देवालयों से बेरंग लौटा दिया गया.

चर्चा कुंभनगर की

तीन चौथाई कुंभ ऐसे ही बीत चुका है और यही तमाशा बार बार हो रहा है. बाक़ी का कुंभ भी ऐसे ही बीत जाएगा, फिर बात जाएगी अगले बारह बरस को!

कुंभ के आगन्तुकों की संख्याचर्चा भी कुंभ का एक अनिवार्य खेल है. शासन, प्रशासन और पुलिस के सिर पर दोहरा दायित्व आ पड़ा है. उन्हें यह दिखाना और बताना भी है कि कुंभ में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ़ वह सब भी करना है जिससे इतने सारे लोग कहीं सचमुच ही न आ जाएं. परिणामस्वरूप वह हर स्नान दिवस पर मीडिया को बता देता है कि कितने लाख लोग आए. उदाहरणार्थ रामनवमी पर रेलवे ने आंकड़ा जारी किया कि उस दिन 12 हज़ार यात्री हरिद्वार उतरे पर प्रशासन ने लाखों लोगों के रामनवमी स्नान करने की बात कही. यही नहीं रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक आने जाने वालों पर वही सख्ती बरती गई जो सचमुच लाखों लोगों के आने पर भी प्राय: नहीं बरती जाती. इस तरह प्रशासन ने सख्ती से मनवाया कि सामान्य ढंग से संपन्न रामनवमी पर लाखों लोग नहाए. तीन चौथाई कुंभ ऐसे ही निबट गया है, आगे भी निबट ही जाएगा.

हमारे मीडियाकर्मी भी क्यों पीछे रहते. उन्होंने शीर्षक दिया रामनवमी पर लाखों ने लगाई डुबकी और नीचे डबल कॉलम ख़बर लगाई कि घाट सूने रहे, रास्ते ख़ाली, लागू रहा ट्रैफिक प्लान. यानी चित भी मेरी पट भी मेरी. ऐसी ही पत्रकारिता में तीन चौथाई कुंभ निकल गया है, शेष भी निकल ही जाएगा.

वैसे कुंभ की रौनक अब पराकाष्ठा पर है. साधुसंतों के पोस्टरों, बैनरों और होर्डिंग्स से कुंभनगरी अटी पड़ी है. हर खंभे पर बाबाजी की तस्वीर वाला प्रचार पोस्टर है. प्रशासन की मार्गदर्शक पट्टियां तो दिखतीं नहीं, अलबत्ता बाबाओं के बड़े बड़े होर्डिंगों से शहर का हर चौराहा, हर मोड़ और हर मुख्य मार्ग दमक रहा है. तेरह अखाड़ों के डेढ़–दो सौ महामण्डलेश्वर शहर में अपने आश्रमों या प्रशासन द्वारा टेंटों में विकसित मण्डलेश्वर –नगर में डेरा डाले हुए हैं. सरकारी कुंभ काल शुरू होने से पहले ही पचासों मण्डलेश्वर विभिन्न अखाड़ों ने बना डाले हैं. इनमें विदेशी मण्डलेश्वर भी शामिल हैं. विदेशियों को मण्डलेश्वर बनाने में अग्रणी एक महामण्डलेश्वर का तो दावा ही है कि वे अगले कुछ वर्षों में विदेशी मण्डलेश्वरों की लाइन लगा देंगे. अब लोग इसे कुछ भी कहें, विदेशी धन देश में इंवेस्ट तो कराया ही जा रहा है.

कुंभ में केवल मण्डलेश्वर बनाए ही जा रहे हों ऐसा नहीं है. निकाले भी जा रहे हैं. राजनीति के दृश्य धर्म के मंच में भी देखे जा सकते हैं. अभी हाल ही में उदासीन अखाड़े ने अपने एक महामण्डलेश्वर से उनका पद छीन कर उन्हें अखाड़े का दरवाज़ा दिखा दिया. लेकिन इस घटना से पहले ही निकाले गए महामण्डलेश्वर अपना दल बदल चुके थे. वे उदासी से बैरागी बन चुके थे. उदासी पने से बैराग धारण कर बाक़ायदा बैरागी बने इन संत महानुभाव को बैरागी संप्रदाय ने हाथों हाथ लिया और ठेठ रामानन्दाचार्य के सर्वोच्च आसन पर अभिशिक्त कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम पर साधु समाज में ही चिमगोइयां जारी हैं. पर होना जाना कुछ नहीं है.

इन सबके बावजूद कुंभ को लेकर भारी उत्साह है. कहीं हरिकीर्तन हो रहा है तो कहीं रामकथा प्रवचन. कहीं भगवत कथा हो रही है तो कहीं रासलीला प्रदर्शन. हर कैंप में दर्शक को लुभाने का कथित रूप से योग सिद्ध करने का, आत्मज्ञान कराने का पूरा आश्वासन है और उसके लिए पूरा मसाला भी. सुनने की ताक़त बटोरकर अपने कान ताक़तवर बनाइए और गांठ पूरी रखिए. फिर जमकर घूमिए आनंद ही आनंद मिलेगा चारों ओर.

kk@budhkar.in

C✲OL-ER
WE MAKE READING COOL
C✲OL-ER

कूल डिवाइस- कूल-अर

आजकल के हाईटेक युग में युवाओं पर गिज्मों और गैजेट की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है. इसी बढ़ते क्रेज को देखते हुए बाज़ार में हर दिन कोई न कोई गैजेट बाज़ार में उतारा जाता है. ऐसा ही एक स्टाइलिश डिवाइस है, ई-बुक रीडर. हालांकि पहले भी कई ई- बुक बाज़ार में मौजूद हैं, पर इसकी बात ही अलग है. इसका नाम है कूल-ई-रीडर या कूल-अर. अपने नाम की तरह यह अपने लुक और फीचर के मामले में भी एकदम कूल है. यहां तक कि अगर बात इस ई-बुक के वज़न की भी करें तो यह केवल 178 ग्राम का है. जो कैरी करने के लिए एकदम आरामदेह है. इसके अलावा इसकी स्क्रीन की स्पष्टता भी लाजवाब है. इसकी तारीफ़ आप देखते ही कर बैठेंगे. स्क्रीन की ख़ासियत यह है कि यह 800.600 पिक्सल का है. ज़ाहिर है यह आंखों को भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है. इसमें लगने वाले यूएसबी प्रोसेस काफ़ी सरल किस्म के है, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है. कूल-अर लिनेक्स-ओएस के प्रोसेस की तरह काम करता है. इसके अच्छे फीड बैक से उत्साहित कंपनी ने ओएस की सफलता के मद्देनज़र जल्द ही जीपीएल बनाने की जुगत कर डाली है. आपको बता दें कि उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें पीडीएफ, ईपीयूपी, एफबी-2, आरटीएफ, टीएक्सटी, एचटीएमएल, पीआरसी, जेपीजी, और एमपी-3 समेत कई सुविधाओं से लैस की गई हैं. कूल-अर में लगने वाला हैडफोन 2.5 एमएम का है. ग़ौरतलब है कि कैमरे की बात हो या संगीत सुनने की, कूल-अर आपकी तमाम ज़रूरतों पर पूरी तरह खरा उतरने जैसा प्रतीत होता है.

क्रिएटिव ने बनाया पीसी हेडफोन

हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी सोनी ने पीसी हेडफोन बनाने का फ़ैसला किया है. कंपनी का दावा है कि हेडफोन का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ये हेडफोन काफ़ी पसंद आएगा. इस हेडफोन की ख़ासियत है इसका बेहतरीन साउंड इफेक्ट. इसके साउंड इफेक्ट के बारे में ज़्यादा जानें तो यह कंप्यूटर के हेडफोन से भी अलग गुणवत्ता वाली मानी जाती है. हेडफोन दो मॉडल्स में उपलब्ध है- डीआर-350 यूएसबी और डीआर-320 डीपीवी.

दोनों मॉडल्स मल्टी-डायरेक्शनल माइक्रोफोन में उपलब्ध है. आप हेडफोन की साउंड इफेक्ट्स को अपनी सुविधानुसार एडजस्ट कर सकते हैं. संगीत सुनने, गेम्स पर म्यूज़िक को ऑन मोड पर रखने या फ़िल्मी म्यूज़िक मोड़ पर इसका आउटपुट काफ़ी बेहतरीन होता है.

डीआर-350 यूएसबी ब्लैक गोल्ड कलर में आता है जबकि डीआर-320 डीपीवी आपको ब्लैक और रेड कलर में बाज़ार में उपलब्ध मिलेगा. इन सबके अलावा डीआर-310 डीपी हेडसेट भी है जो हेडसेट द्वारा हाल में बनाए हुए मॉडलों में वज़न में सबसे हल्का है. डीआर-310 डीपी हरे, उजले, पिंक और ब्लू रंगों में बनाई जा रही है. इस हेडफोन के लिए ग्राहकों को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा. ये सारे मॉडल आपको बाज़ार में अप्रैल 2010 से मिलने शुरू हो जाएंगे.

बच्चों का किडी जूम कैम

आमतौर पर कैमरे से फोटो खींचना हो तो हम बड़ों के हाथ में कैमरा देना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि पिक्चर ख़राब न हो. लेकिन वीटेक ने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो केवल बच्चों के लिए है. ऐसा लग रहा है कि बच्चे ही इस कैमरे से सबसे ज़्यादा फोटो खींचेंगे. इसीलिए इसका नाम भी बच्चों की च्वाइस को देखते हुए किडीजूम टॉय कैमरा रखा गया है. वीटेक किडीजूम कैमरा कैनन आईएक्सयूएस-200 के मॉडल में उपलब्ध है. किडीजूम दो रंगों- पिंक और ब्लू में आपको बाज़ार में मिलेंगे. इस कैमरे की डिज़ाइन भी बच्चों को देखकर रफ-एंड-टफ तरीक़े से तैयार की गई है. कैमरे का वजन केवल 380 ग्राम है तथा स्क्रीन 1.8 इंच कलर डिस्प्ले के साथ 140-93-58 एमएम का है. किडीजूम कैमरे में 4-एए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. कैमरे में 16 एमबी एक्सपेंडेबल मेमोरी है, साथ ही इंटरनल मेमोरी 2 जीबी का दिया गया है. कैमरे में मिनी-यूएसबी पोर्ट है जो कम्प्यूटर्स में पिक्चर्स के डाउनलोड के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. 0.3 मेगापिक्सल के साथ कैमरे में फोटो खींचने के लिए 640-480 रेज़ोल्यूशन तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है. चूंकि बच्चों के लिए ख़ास तौर से बनाया गया है. इसीलिए इसमें गुणवत्ता को कम और फंक्शनस को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है. यही वजह है कि कैमरे में बच्चे अपनी या दूसरों की आवाज़ को सुनने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आराम से कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें बच्चों के लिए गेम्स भी हैं. तीन गेम्स के साथ कैमरे से बच्चे अपना दिमाग़ी कसरत भी कर सकते हैं. साथ ही कैमरे में एक टेलीविज़न जैक है इसलिए बच्चे कैमरे में मौजूद तीनों गेम्स को टीवी से कनेक्ट भी कर सकते हैं. इससे बच्चे गेम्स का मज़ा टीवी पर भी उठा सकते हैं.

सोनी अब फिल्मी दुनिया में

सोनी पिक्चर्स अब फ़िल्मी दुनिया में क़दम रखने जा रहा है. सोनी का एचडी फ़िल्म बनाने का विचार है और इसके लिए कंपनी ने 6 हॉलीवुड स्टूडियोज के साथ करार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. सोनी टीवी ने इसके लिए पीएस-3 को माध्यम बनाया है, हालांकि इन कंपनियों का मि.फॉक्स और हैरी पॉटर जैसी फ़िल्मों के साथ पहले ही करार हो चुका है.

पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में उतरने वाली सोनी कंपनी ने अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए इसे ब्लॉकबस्टर और लव फ़िल्म के ज़रिए भी प्रसारित करना शुरू कर दिया है.

इसके लिए सोनी ने लॉन्चिंग का प्रारूप भी तय कर लिया है. कंपनी ने सबसे पहले इसे अमेरिका में लॉन्च करने का मन बनाया है लेकिन कब तक यह सपना पूरा होगा इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है. कंपनी इसे अमेरिका के अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में भी लॉन्चिंग करने का विचार बना रहा है.

ZOMBIELAND
Blu-ray Disc
HD DVD

पीको का ईको फ्रेंडली चार्जर

पर्यावरण की रक्षा को लेकर लगभग सभी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ रही है. ऐसे में तकनीकी क्षेत्र भला कैसे पीछे रह सकता है. सोलर चार्जर ने सोलर तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की है. सोलर चार्जर कंपनी पीको ने सनलाइट से चार्ज करने वाली एक ऐसे चार्जिंग सिस्टम का निर्माण किया है जो बैटरी को चार्ज करता है और साथ ही लंबे समय तक बैटरी के बैकअप में मदद भी करता है. बैटरी की चार्जिंग की बात करें, तो धूप में चार्ज होने वाली बैटरियों में मोबाइल आर आई-पॉड की बैटरी भी शामिल है. कंपनी का दावा है यह सोलर चार्जर आमतौर पर मोबाइल की बैटरी को एक बार चार्ज करने पर 35 घंटा और आई-पॉड की बैटरी को 14 घंटे तक बैक अप देने में कारगर साबित होता है. इसका वज़न भी ज़्यादा नहीं है. 49 ग्राम वज़न वाला यह सोलर चार्जर नोकिया, सोनी एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियों के मोबाइल फोन समेत यूसबी के लिए काफी बेहतरीन और उपयोगी होता है. क़ीमत भी इसकी लगभग 17 डॉलर रखी गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ख़ास पलों का ख़ास कैमरा

बात किसी ख़ास पल की हो या किसी पर्व-त्यौहार की. हम ख़ुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बेहतरीन और यादगार पलों की हिफाज़त हमेशा बनी रहे तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक ख़ास कैमरे की. ओलिम्पस ई-600 फोर थर्ड डिजिटल एसएलआर कुछ इसी तरह की खासियत से लैस कैमरा है. नए डिज़ाइनों और स्टाइलिश लुक के लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपना एक ख़ास मुक़ाम बना चुकी ओलिम्पस कंपनी का यह मॉडल कई मायनों में स्पेशल है. ओलिम्पस ई-600 फोर थर्ड डिजिटल एसएलआर है जिसका लेंस 14-42 एमएम है. कैमरे का डीएसएलआर मॉडल अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है, जैसे कि ब्लैक, सिल्वर, व्हाइट. इससे आपका फैशन स्टाइल बरक़रार रहेगा. ओलिम्पस में फ्लैश का बटन कैमरे में पीछे टॉप पर दिया गया है ताकि पिक्चर खींचते समय आपका ध्यान न भटके. इसको हैंडल करते समय आसानी हो इसके लिए मॉडल का वजन मात्र 300 ग्राम रखा गया है. साथ ही 12.3 मेगापिक्सल लाइव एमओएस है, जिससे कैमरे का स्क्रीन काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है और आपको मिलती है बेहतरीन पिक्चर. इसमें आर्ट फिल्टर भी डाला गया है जिसमें अनेक विकल्प होते हैं. यानी पिक्चर या रिकॉर्डिंग को इफेक्टस के माध्यम से , और भी आकर्षक बनाया जा सकता है. रिकॉर्डिंग करते समय हम इसमें स्टिल इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं. ओलिम्पस की गुणवत्ता कहिए कि पिक्चर कैप्चरिंग के वक़्त अगर हाथ भी हिल जाए तो हमारा पिक्चर जर्की या शेकी (धुंधला) नहीं होता है. ऑटो मोड भी है जिससे रोशनी के हिसाब से पिक्चर का ख़ुद-ब-ख़ुद एडजस्टमेंट हो जाता है.

OLYMPUS
M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:2.8

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ब्रासा ने प्रोजेक्ट इंडिया नाम का एक दस्तावेज हॉकी इंडिया को सौंपा है, जिसमें उक्त सारी बातें कही गई हैं.

हॉकी इंडिया को ब्रासा का फार्मूला रास आएगा?

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पिछले महीने हुई विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को आठवें स्थान से ही संतोष करना पड़ा. हालांकि हॉकी के मैदान में भारत के इतिहास के नज़रिए से देखें तो यह प्रदर्शन प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय हॉकी जिस तरह लगातार अवसान की ओर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह नई उम्मीदों का संचार ज़रूर करता है. अपने पहले मुक़ाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह पाकिस्तान की मज़बूत टीम को पटकनी दी, उससे यह भरोसा पैदा हुआ कि हॉकी के खेल में भारत का झंडा एक बार फिर लहरा सकता है. लेकिन, अगले मुक़ाबलों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कोरिया की टीमों के ख़िलाफ़ मिली पराजय के बाद यह नशा जल्द ही काफ़ूर भी हो गया. अब टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद टीम के स्पेनिश कोच जोस ब्रासा ने भारतीय हॉकी के पुनरुत्थान के लिए एक नया फार्मूला पेश किया है. ब्रासा ने अपने प्रस्ताव में टीम के कोच के अधिकारों में वृद्धि की मांग की है और हॉकी के घरेलू ढांचे में भी आमूलचूल बदलाव की वकालत की है.

ब्रासा ने प्रोजेक्ट इंडिया नाम का एक दस्तावेज हॉकी इंडिया को सौंपा है, जिसमें उक्त सारी बातें कही गई हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि कोच के पास खिलाड़ियों के चयन का अंतिम अधिकार होना चाहिए. टीम के चुनाव में राजनीतिक दख़लंदाज़ी बंद हो और पैसे की कमी जैसी कोई समस्या न हो. टीम का सपोर्ट स्टाफ ऐसा हो, जिस पर कोच भरोसा कर सके. कोच के लिए ज़्यादा अधिकारों की वकालत के पीछे ब्रासा का तर्क है कि विदेशों में पहले से ही यही व्यवस्था है. वहां टीम के चुनाव से लेकर उसके प्रदर्शन तक की सारी ज़िम्मेदारी कोच की ही होती है. खिलाड़ियों की हालत में सुधार के लिए ब्रासा ने ग्रेडिंग सिस्टम,बीमा योजनाओं और घरेलू स्तर पर एक लीग की शुरुआत का सुझाव दिया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय हॉकी के कर्ताधर्ता ब्रासा के इन सुझावों को मानने के लिए तैयार होंगे? कोच के अधिकारों में वृद्धि का मतलब है ख़ुद उनके अधिकारों में कटौती. क्या वे इसके लिए राजी होंगे?

देश में हॉकी प्रशासन की मौजूदा हालत को देखते हुए इसकी संभावना कम ही दिखती है. भारतीय हॉकी फेडरेशन के विघटन के बाद हॉकी इंडिया का गठन किया गया, जो एक तदर्थ निकाय भर है. इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय हॉकी प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं. अक्सर दोनों संस्थाएं एक-दूसरे के साथ पॉवर गेम खेलने में व्यस्त रहती हैं, जिससे खेल की हालत तो नहीं सुधरती, उल्टे खिलाड़ियों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ती है. इन संस्थाओं के अधिकारी खेल के बजाय अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने की कोशिश में लगे रहते हैं. ऐसे में ब्रासा की सलाह उन्हें रास आएगी, यह मुमकिन नहीं दिखता. हम यह तो नहीं कह सकते कि ब्रासा के सुझावों को आंख मूंदकर मान लेना चाहिए. यूरोपीय टीमों में कोच सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन भारत में ऐसा शायद ही मुमकिन हो. लेकिन यह जरूर हैकि ब्रासा के सुझावों पर विचार किया जा सकता है. आमूलचूल परिवर्तन न सही, लेकिन बदलाव की शुरुआत की छोटी सी उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वुड्स की वापसी पर शंका के बादल

मशहूर गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स एक बार फिर गोल्फ कोर्स पर वापसी की तैयारी में हैं. पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अप्रैल महीने में अगस्टा मास्टर्स टूर्नामेंट में उनकी मैदान पर वापसी हो सकती है. पिछले साल दिसंबर में कई महिलाओं के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहे वुड्स का पारिवारिक जीवन अभी तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा है. पत्नी एलिन नॉर्डेग्रेन अभी भी उनसे खफा हैं. और तो और, खुलासों का दौर भी अब तक थमा नहीं है. वुड्स के इंटरव्यू के चार दिनों बाद ही एक और पोर्नस्टार डेवोन जेम्स ने उनके साथ शारीरिक संबंध होने का दावा किया. जेम्स ने यह भी कहा कि संबंध को गोपनीय बनाए रखने के लिए वुड्स उन्हें हर महीने एक तय राशि दिया करते थे.

टाइगर वुड्स के लिए ये खुलासे नए नहीं हैं. दिसंबर, 2009 में एक के बाद एक खुलासों में कम से कम एक दर्जन महिलाओं ने उनके साथ संबंध होने का दावा किया था. इनमें कई पोर्न स्टार और मॉडल भी शामिल थीं. कई महिलाओं ने तो वुड्स के साथ वाली अपनी तस्वीरें, एसएमएस और अन्य सबूत भी पेश किए थे. इन खुलासों के चलते ही गोल्फ कोर्स के इस सरताज खिलाड़ी को खेल के मैदान से बाहर होने को मजबूर होना पड़ा था. इस घटनाक्रम से पहले तक उनकी छवि एक आदर्श खिलाड़ी की थी. उनके व्यक्तित्व को विवादों से परे माना जाता था लेकिन इसके बाद आए तूफान ने उनके खेल के साथ-साथ निजी जीवन की भी दिशा बदल कर रख दी. एक बार तो ऐसा लगा कि वुड्स अब दोबारा कभी गोल्फ खेलते नजर नहीं आएंगे. खुद वुड्स ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि वह पहले अपनी निजी जिंदगी को संभालेंगे, तभी गोल्फ के बारे में कोई फैसला करेंगे. अब जबकि वुड्स इसकी तैयारी में हैं, डर इस बात का है कि खुलासों का यह नया दौर कहीं उन्हें उनके इरादों से डिगा न दे. यह न केवल वुड्स के प्रशंसकों के लिए, बल्कि गोल्फ के लिए भी बड़ी त्रासदी हो सकती है.

राज्यवर्धन राठौर कॉमन वेल्थ गेम्स से बाहर

ओलंपिक खेलों में पदक की क्या अहमियत होती है, यह हम भारतीयों से ज्यादा शायद ही कोई और जानता हो. सवा अरब की जनसंख्या वाला हमारा देश हॉकी के स्वर्णिम युग की समाप्ति के बाद से अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से खाली हाथ ही लौटता रहा है. 2004 में एथेंस ओलंपिक के पुरुषों के डबल ट्रैप इवेंट में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता तो यह करोड़ों देशवासियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जैसा था. ओलंपिक की किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में यह भारत का पहला पदक तो था ही, इसने यह उम्मीद भी जगाई कि यूरोपीय खिलाड़ियों के प्रभुत्व वाले खेलों में भी भारत बराबरी के स्तर पर मुकाबला कर सकता है. लेकिन, हैरत की बात है कि वही राज्यवर्धन सिंह राठौर इस साल अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे. और, इसकी वजह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की अदूरदर्शी नीतियां हैं.

एनआरएआई ने इस साल मार्च में खिलाड़ियों के चयन के लिए एक नई नीति की घोषणा की. इस नीति की सबसे बड़ी खासियत है एक बेस लाइन स्कोर, जिसमें खिलाड़ियों के प्वाइंट्स आगे जुड़ते रहेंगे. हर ट्रायल में खिलाड़ियों को मिलने वाले प्वाइंट्स को जोड़ा जाएगा और ज्यादा प्वाइंट्स वाले खिलाड़ी ही भारतीय टीम के लिए चुने जाएंगे. ताज्जुब की बात तो यह है कि 2010 के लिए फरवरी में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप को आधार बनाया गया है, जबकि नई नीति की घोषणा मार्च में की गई है. इसमें शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं दिया गया है और न ही ओलंपिक कोटे की कोई चर्चा है. शूटिंग में मौसम की बड़ी भूमिका होती है. खराब मौसम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होता है. ऐसी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एनआरएआई की नई चयन नीति में इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं है. सबसे हैरत की बात तो यह है कि चयन की नई नीति की घोषणा से पहले खिलाड़ियों या विशेषज्ञों से कोई सलाह नहीं ली गई.

पिछले दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे राठौर फरवरी में हुई इस प्रतियोगिता में शरीक नहीं हुए थे. गत 18 मार्च को पटियाला में हुए आखिरी ट्रायल में उन्होंने कुल 150 में से 140 अंक हासिल किए, लेकिन फिर भी उन्हें टीम के लिए नहीं चुना गया, क्योंकि अन्य शूटरों के प्वाइंट्स राठौर से ज्यादा थे.

अब सवाल यह है कि अक्टूबर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए फरवरी के प्रदर्शन को आधार कैसे बनाया जा सकता है? फिर यह भी सत्य है कि खिलाड़ियों का फॉर्म अस्थायी होता है, स्थायी होती है उनकी प्रतिभा. यह सत्य है कि राठौर एक साल पहले खराब फॉर्म के शिकार थे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अक्टूबर में भी अपनी लय हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे. एनआरएआई ने राठौर के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनों को मानने से इंकार कर दिया. वह स्वाभाविक रूप से काफी निराश हैं. आखिर अपने देश में हो रही किसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कौन खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का सदस्य नहीं बनना चाहेगा. क्या ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ हमारे देश में ऐसा ही व्यवहार किया जाता है. शायद यही वजह है कि पदकों के लिए तरसना हमारी नियति बन चुका है.

COACHING BY EXPERTS
PACIFIC SPORTS COMPLEX
Offers World Class Facilities in
Olympic Size Swimming Pool (50x21 m)
Taekwondo
Table Tennis
Ice Hokey
Yoga
Dance & Music
MEMBERSHIP OPEN
Lajpat Nagar, Near L.S.R., Opp. G.K .- I Petrol Pump New Delhi
Call : 64520554, 64520555, 26452747/48, 9911138192

चौथी दुनिया
दिल्ली, 5 अप्रैल–11 अप्रैल 2010

फ़िल्म के प्रमोशन के मौक़े पर उन्होंने शूटिंग के दौरान हुए कई दिलचस्प वाकयों का ज़िक्र किया. सबसे दिलचस्प घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि सेट पर अक्सर उन्हें अक्षय और रितेश गाइड कहकर छेड़ते थे.

हर हाल में ख़ुश हूं : राइमा सेन

फ़िल्म गॉड मदर से अपना करियर शुरू करने वाली बंगाली बाला राइमा सेन अपने एक अलग तरीक़े के अभिनय के लिए जानी जाती हैं. गॉड मदर के बाद दमन, चोखेर बाली, परिणीता, दस, यात्रा, अंतर महल, दायरा, एकलव्य, फंटूश, मनोरमा सिक्स फीट अंडर, सी कंपनी, मुखबिर, मेरे ख्वाबों में जो आए, हनीमून ट्रैवल्स और तीन पत्ती आदि अनेक फ़िल्मों में उन्होंने अभिनय किया. उनकी एक नई फ़िल्म जैपनीज वाइफ शीर्षक से अंग्रेजी एवं बंगाली दोनों भाषाओं में जल्द ही रिलीज़ होने वाली है. निर्देशक अपर्णा सेन की इस फ़िल्म में राहुल बोस, राइमा सेन, मौसमी चटर्जी एवं जापानी अभिनेत्री चिगुसा तकाकू भी हैं. राइमा ने हाल में चौथी दुनिया से एक लंबी बातचीत की. पेश हैं खास अंश:

फ़िल्म में आपकी क्या भूमिका है?

मैं संध्या नामक एक विधवा की भूमिका में हूं, जिसका आठ साल का एक बेटा भी है. मैंने पहली बार इस तरह की भूमिका की है.

अगर कहानी की बात करें तो... ?

सुंदर वन में एक स्कूल शिक्षक है स्नेहमोय नाम का और मियागे जापान की एक जवान लड़की है. दोनों ही पत्रों के माध्यम से एक-दूसरे से मिलते हैं और उनमें प्यार हो जाता है. इसके अलावा पत्र के माध्यम से ही वे शादी भी कर लेते हैं. उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं, जबकि वे आज तक एक-दूसरे से कभी नहीं मिले. मैं भी परिस्थितियोंवश शिक्षक के घर में रहती हूं.

फ़िल्म किस लेखक की कहानी पर आधारित है?

यह अंग्रेजी लेखक कुनाल बासु की लघु कहानी पर आधारित है.

अपर्णा सेन जैसी वरिष्ठ निर्देशक के साथ काम करना कैसा लगा?

मैं शुरू-शुरू में उनसे कुछ डरी हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि वह बहुत ही कड़क हैं, लेकिन साथ में काम करते-करते सब ठीक हो गया. जब कोई सीन सही नहीं होता, तब वह समझातीं एवं ज़रूरत होने पर डांटतीं भी, लेकिन फिर अपनी बेटी की तरह प्यार भी करतीं. अपर्णा सेन के साथ काम करना बहुत ही अच्छा रहा. मैं भविष्य में भी उनके साथ काम करना चाहूंगी. वह जिस तरह से काम करती हैं, उससे बहुत ही प्रेरणा मिलती है.

राहुल बोस अपने संजीदा अभिनय के लिए जाने जाते हैं. उनसे केमिस्ट्री बैठाने में कोई मुश्किल हुई?

राहुल तो एक मंझे हुए अभिनेता हैं. उनके साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा मैंने अभिनय के बारे में.

आपकी जितनी भी फ़िल्में आईं, उनमें से अधिकतर कमर्शियल नहीं हैं. कोई ख़ास वजह?

मुझे जैसी भी फ़िल्में मिल रही हैं, मैं उनसे ख़ुश हूं. मुझे कोई भी शिक़ायत नहीं है.

आगामी प्रोजेक्ट कौन से हैं, जिनमें आप दिखाई देंगी?

एक तो सनग्लास है. इसके अलावा विनय शुक्ला की मिर्च एवं रितुपर्णो घोष की नौका डूबी मेरी आने वाली फ़िल्में हैं. और भी कई प्रोजेक्ट पाइप लाइन में हैं.

क्या करें, क्या न करें

फ़िल्म कितने दूर कितने पास में फरदीन खान के साथ बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज़ करने वाली अमृता अरोड़ा कभी भी नंबर एक की कतार में नहीं आ पाईं. ज़्यादातर फ़िल्मों में वह सह अभिनेत्री के किरदार में ही नज़र आईं. जिन फ़िल्मों में वह लीड रोल में थीं, उन्हें बॉक्स ऑफिस पर ख़ास नोटिस नहीं मिला. ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की. दरअसल अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने वे सारे तरीक़े अपनाए, जिससे सफलता हासिल हो सकती है. चाहे वह एक्जपोजर का मामला हो या जीरो फिगर का क्रेज. दोनों ही मामलों पर अमृता ने बहुत जल्द पकड़ बना ली. इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में हॉट प्रॉपर्टी बन चुकी करीना कपूर से भी उनकी ख़ासी दोस्ती के चर्चे सामने आए. इस दोस्ती की बदौलत ही उन्हें करीना के साथ कम्बख्त इश्क और गोलमाल जैसी बिग बजट की मल्टीस्टारर फ़िल्मों में काम मिला. लेकिन शायद उनकी क़िस्मत और एक्टिंग स्किल्स ही ऐसे हैं कि कुछ भी काम नहीं आया. उनकी फ़िल्में एक-एक करके पिटती गईं. पर उनका स्टार बनने का सफर अभी तक जारी है. अमृता के मुताबिक़, वह कोशिश करने वालों में से हैं. कुछ फ़िल्मों के न चल पाने का मतलब यह नहीं होता कि आपका काम सही नहीं है. फ़िल्म की सफलता और असफलता के ज़िम्मेदार फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कहानी, निर्देशक, पटकथा और अभिनय लगभग समान रूप से भागीदार होते हैं. अमृता को अपनी आगामी फ़िल्मों से काफी आशाएं हैं. ख़ैर, आगे का तो कुछ पता नहीं, पर अभी तक के करियर ग्राफ से तो यही अंदाज़ा निकलता है कि उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हैं.

हाउसफुल की गाइड जिया

रामगोपाल वर्मा की खोज जिया खान बहुत कम फ़िल्मों में ही दिखाई देती हैं. पिछले तीन-चार सालों से वह बॉलीवुड में हैं, पर अभी तक उनकी सिर्फ़ दो फ़िल्में ही प्रदर्शित हुई हैं, जिनमें निशब्द और गजनी का नाम लिया जा सकता है. लेकिन, अब दर्शकों को वह जल्द ही साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन और साजिद खान के निर्देशन में फ़िल्म ऑ हाउसफुल में दिखाई देंगी. इस बिग स्टारकास्ट मूवी में वह अक्षय कुमार के अपोजिट काम कर रही हैं. इस फ़िल्म में कई दिग्गज कलाकार नज़र आएंगे, जिनमें रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल, लारा दत्ता, दीपिका पादुकोण और बोमन ईरानी आदि प्रमुख हैं. फ़िल्म के प्रमोशन के मौक़े पर उन्होंने शूटिंग के दौरान हुए कई दिलचस्प वाकयों का ज़िक्र किया. सबसे दिलचस्प घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि सेट पर अक्सर उन्हें अक्षय और रितेश गाइड कहकर छेड़ते थे. इस गाइड के पीछे की कहानी क्या है? जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विदेशी लोकेशन पर शूट का उन्हें ख़ूब फ़ायदा मिला, क्योंकि वह अमेरिका में ही पली-बढ़ी हैं और वहां के इलाक़ों से वाक़िफ़ हैं. इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ती, वह सिनेमेटोग्राफर और सेट डिज़ाइनर को वहां की ख़ूबसूरत लोकेशन के बारे में बताती थीं. जब शूट ख़त्म हो जाता, तो वह अपने साथी कलाकारों को भी ख़ूब सैरसपाटा कराती थीं, इसीलिए सेट पर अक्सर अक्षय उन्हें जिया गाइड कहकर उनकी टांग खीचते थे. फ़िल्म में पहले से ही दो अभिनेत्रियों के होने से उनके खाते में क्या बचेगा, उन्हें इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं है. वह कहती हैं, मैं अपने रोल से संतुष्ट हूं और फ़िल्म के प्रदर्शन के बाद आप भी देखेंगे कि मेरा किरदार उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना दीपिका और लारा का. वह उन अफ़वाहों को भी ख़ारिज करती हैं, जिनमें कहा गया था कि शूटिंग के दौरान अभिनेत्रियों की कैट फाइट के चक्कर में बेचारे साजिद परेशान रहते थे.

फ़िल्म रिव्यू

मीडिया और सिनेमा का नाट्य रूपांतरण

बाज़ार में हावी दो प्रमुख क्षेत्रों बॉलीवुड और मीडिया हाउस में एक शीत युद्ध सा छिड़ा हुआ है, इसलिए समय समय पर दोनों ही क्षेत्रों के रचनात्मक और भ्रष्ट महाराथी एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आते हैं. पहले बॉलीवुड के सिनेमाई प्रोडक्शन से प्रभावित मीडिया गंभीर ख़बरों से इतर नाट्यरूपांतरण के रूप में रोमांचक लघु फ़िल्में दिखाता हैं और उन्हें न्यूज़ कहता है. वहीं दूसरी ओर अब बॉलीवुड भी मीडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ख़बरों (क्राइम, सेक्स स्कैंडल और प्राइम टाइम इंटरटेनमेंट) को अपने अंदाज़ का सिनेमा बताकर बेच रहा है. इसी शीत युद्ध में लव सेक्स और धोखा जैसी फ़िल्मों का जन्म होता है. पूरी फ़िल्म इन्हीं बिकाउ मसालों(खबरों) के इर्द गिर्द घूमती है. तीन अलग अलग चैप्टर्स में बंटी फ़िल्म में पहली कहानी फ़िल्म संस्थान के दो युवा जोड़ों की प्रेमकहानी पर आधारित है. घर से भागे इस जोड़े की परिवार वाले नृशंस हत्या कर देते हैं. दूसरी कहानी एक स्टोर शॉप की है, जहां मैनेजर लाला और उसका एमबीए दोस्त स्टोर में काम करने वाली लड़की को एमएमएस बनाकर बेचने की फिराक में हैं. आख़िरी कहानी एक स्टिंग किंग प्रभात की है. एक सिंगर लूकी लोकल (जो तू नंगी अच्छी लगती है... जैसे गाने गाकर सुपरस्टार बना है) की कास्टिंग काउच की शिकार डांसर नैना और प्रभात मिलकर सिंगर के लिए एक नया स्टिंग प्लान बनाते हैं. उसके बाद फिर वही ब्लैकमेल और टीआरपी का खेल होता है. फ़िल्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ने में दर्शकों को सिवाए माथापच्ची के कुछ भी हासिल नहीं होता. पूरी फिल्म कैमरे के रिकॉर्डिंग मोड में चलती है . शुरुआत में हास्यास्पद तरीक़े से चेताया गया है कि कैमरा हिल सकता है हमारी कोई गारंटी नही है. पर जो दर्शक पैसा ख़र्च करके फ़िल्म देखने आएगा वह शायद ही यह उम्मीद करे कि पूरी फ़िल्म में उसको हिलते हुए दृश्य दिखाई दें. सारें कलाकार नए हैं जो अपने-अपने रोल पर फिट बैठते हैं. एक दृश्य में कलाकार कहता है कि इसी स्टोर में शूट आउट और सेक्स स्कैंडल हुआ था, कुछ भी कहो स्टोर की सेल बढ़ गई. बिल्कुल वही सिनेमा के साथ है, जो अपनी सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है. दिबाकर निर्देशक के तौर पर ओय लकी और खोसला का घोसला जैसी सार्थक फ़िल्म देकर अचानक क्या सोचकर बी ग्रेड सिनेमा का मॉडर्न संस्करण बनाने पर तुल गए, यह समझ के बाहर है. यंगिस्तान के बिगड़े नवाबजादों के अलावा, इस ए सर्टिफिकेट और बात बात पर गालियां सुनने, फ़िल्म को और कौन देखने जा सकता है? पर हां अगर समाज की गंदगी दिखाने के बहाने सिर्फ़ गंदगी ही परोसी जाएगी तो हाथ ही गंदे होंगे. इसे तो कतई भी स्वस्थ मनोरंजन नहीं कहा जा सकता.

LSD
LOVE SEX aur DHOKHA

राजेश एस. कुमार
feedback@chauthiduniya.com

डबल डेब्यू की कहानी

गलोरियन परिवार में पली बढ़ी जेनेलिया डिसूजा जल्द ही क्रिकेट इंटरटेन पर बन रही फ़िल्म हुक या क्रुक में अंजली कक्कड़ के किरदार में चुलबुलाती हुई नज़र आएंगी. कॉमेडी किंग डेविड धवन की इस फ़िल्म में उनके साथ बॉलीवुड हॉट एंड हैंडसम स्टार जॉन अब्राहम औ वर्सेटाइल एक्टर श्रेयस तलपड़े भी नज़र आएंगे. पिछले दिनों यूटीवी के बिंदास चैनल पर वह एंकरिंग भी करती दिखाई दी थीं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड में इस मुक़ाम को हासिल करने के लिए उनको दो बार डेब्यू करना पड़ा था. हाल ही में हुए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि सात साल पहले रामोजी राव की फ़िल्म तुझे मेरी कसम (2003) से हिंदी फ़िल्मों में डेब्यू किया था पर उस वक़्त न तो मीडिया ने उनको खास तवज्जो दी थी और न ही उनके पास फ़िल्मों के आफ़रों की झड़ी लगी थी. हार मानकर अंत में उनको साउथ की राह पकड़नी पड़ी. लगभग पांच साल के लंबे अंतराल के बाद उनकी क़िस्मत चमकी और जाने तू या जाने ना की अदिति का किरदार हाथ लगा. उनका इस फ़िल्म से डबल डेब्यू माना गया. अब तो उनके खाते में दर्ज़नों फ़िल्में हैं. इसके अलावा अपने नाम का मतलब बताते हुए कहती हैं कि जेनेलिया का मतलब यूनिक या स्पेशल होता है. उनका यह नाम उनकी मां जेनेटा और पिता नील को मिलाकर रखा गया है. मतलब यह कि नाम में भी दो लोग और डेब्यू भी डबल.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार
झारखंड

दिल्ली, 5 अप्रैल–11 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

ताज रहा न राज

एक समय था, जब नीतीश सरकार में भूमिहार बिरादरी का ही बोलबाला था. लोग यह कहने से नहीं चूकते थे कि ताज नीतीश के पास है, राज भूमिहार चला रहे हैं. लेकिन, समय का ऐसा चक्र चला कि इस जाति विशेष के नेता हाशिए पर आ गए. आख़िर वजह क्या है?

ललन सिंह

सरोज सिंह

जातीय राजनीति के लिए बदनाम बिहार में इन दिनों एक तबका ख़ुद को ठगा महसूस कर रहा है. लगभग साढ़े चार साल पहले जब नीतीश कुमार के सिर पर इस राज्य की जनता ने ताज रखा तो इस बिरादरी को लगा कि लालू-राबड़ी के शासन के ख़िलाफ़ रात-दिन हर मोर्चे पर संघर्ष का बिगुल फूंकने का इनाम मिलने का समय आ गया. यहां बात भूमिहार बिरादरी की हो रही है, जिसने हर क़दम पर जान की बाजी लगाकर नीतीश का साथ दिया. हालांकि शुरुआत में नीतीश ने भी दिल खोल कर इसका साथ दिया और इस बिरादरी के नेताओं एवं अफसरों को इतनी तवज्जो दी कि सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम हो गई कि ताज भले ही नीतीश के सिर पर है, लेकिन राज तो भूमिहार नेता एवं अफसर ही चला रहे हैं. इतना ही नहीं, बाद के दिनों में तो यह कहा जाने लगा कि ताज एवं राज दोनों ही भूमिहारों के हाथ में है. मगर, समय और राजनीतिक हालात ऐसे बदले कि आज यह कहने वालों की कमी नहीं कि भूमिहारों के पास अब न ताज रहा न राज.

बात उस वक़्त की है, जब नीतीश की सरकार नई थी. अचानक चर्चा में आई एक ख़बर ने नए राज में भूमिहार बिरादरी से आने वाले ललन सिंह की हैसियत का एहसास शासन एवं प्रशासन को करा दिया. प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले पर ललन सिंह ने उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री बैधनाथ महतो को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने बिना मेरी राय के तबादले की सूची को कैसे फाइनल कर दिया. महतो को सूची दिखाकर अधिसूचना जारी करने की हिदायत दी गई. यह बात सही थी या गलत, यह तो ललन सिंह या फिर बैधनाथ महतो ही बता सकते हैं, लेकिन चर्चा में आई इन बातों ने नई सरकार में ललन सिंह का ग्राफ काफी ऊपर कर दिया. समय के साथ ललन सिंह का रुतबा भी बढ़ता गया और शासन-प्रशासन में ललन सिंह के निर्देश को सरकारी आदेश के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी साथ-साथ चलती रही कि संघर्ष के दिनों में नीतीश के हमसफर रहे कई भूमिहार नेता इस दौरान एक-एक कर उपेक्षा का शिकार होते चले गए. नीतीश के हाथों उपेक्षित होने वाले नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है. जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार, पूर्व मंत्री कृष्णा शाही, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज, पीरो विधायक सुनील पांडे, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, जहानाबाद के निलंबित सांसद डॉ. जगदीश शर्मा, बेगूसराय के पूर्व सांसद रामजीवन सिंह, नवादा सांसद भोला सिंह आदि. नीतीश कुमार ने 1994 में जब लालू से अलग होकर नई पार्टी बनाई तो भूमिहार समाज ने उन्हें हाथोंहाथ लिया. लालू राज में सर्वाधिक पीड़ित भूमिहार रहे और इस जाति ने इसलिए नीतीश को आगे बढ़ाया कि कुशासन से मुक्ति मिलेगी. इस सफर में कई भूमिहार नेताओं ने नीतीश के लिए इसलिए त्याग किया कि किसी भी प्रकार से लालू-राबड़ी के जंगलराज से मुक्ति मिले. रामजीवन सिंह, अरुण कुमार एवं ललन सिंह जनता दल (जॉर्ज) और फिर समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे. तीनों ही नेता नीतीश कुमार के साथ लगे रहे. उत्तर बिहार में रामजीवन सिंह एवं तत्कालीन मध्य बिहार में अरुण कुमार की पकड़ थी और बिरादरी में उनकी अहमियत भी थी. पशुपालन घोटाले की परत दर परत खोलने से चर्चा में आए ललन सिंह भी सब कुछ भूल कर नीतीश को आगे बढ़ाने में लगे रहे. नीतीश के सत्ता संघर्ष के दौरान बाढ़ में पूर्व मंत्री कृष्णा शाही एवं श्याम सुंदर सिंह धीरज भी सहभागी बने. कृष्णा शाही मोकामा से दो बार विधायक रहीं और बेगूसराय से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री भी रहीं. 1977 की जनता पार्टी लहर में कृष्णा शाही ही एकमात्र सांसद बनीं और शेष 53 सीटों पर कांग्रेस हार गई. लालू के ख़िलाफ़ मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहे नीतीश के साथ आईं कृष्णा शाही दो-ढाई वर्षों के अंदर ही वापस हो गईं. 17 वर्षों तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री श्याम सुंदर धीरज भी लालू के खात्मे के लिए नीतीश को मजबूती प्रदान करने आए. नीतीश के साथ चिपक कर रहने वाले धीरज भी अधिक दिनों तक साथ नहीं रह सके. धीरज तो यहां तक कहते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति रहने के बावजूद नीतीश कभी नेताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखते थे. धीरज ने तब अपना रास्ता अलग कर लिया, जब टाल क्षेत्र के बाहुबली अनंत सिंह ने बाढ़ के सकसोहरा में नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौला था. सर्वाधिक कष्टकारी

अरुण कुमार की अपमानजनक विदाई थी. 1990 से ही लालू के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे पूर्व सांसद अरुण कुमार कहते हैं कि उनका संघर्ष उस वक्त से है, जब नीतीश लालू के चाणक्य थे. नीतीश को समर्थन दिए जाने के संबंध में अरुण कहते हैं कि सामूहिक प्रयास के तहत ही कुशासन का खात्मा संभव था और नीतीश की अच्छी छवि के कारण ही वह उनके साथ थे. अलगाव के बाबत अरुण कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार जैसे अहंकारी व्यक्ति को झेलना किसी के वश की बात नहीं. एक समय अरुण कुमार भूमिहार बहुल इलाक़ों में घूम-घूमकर नीतीश कुमार के लिए ज़मीन तैयार करते थे और यही नीतीश कुमार ने यह स्थिति पैदा कर दी कि अरुण न सिर्फ पार्टी छोड़कर गए, बल्कि वह नीतीश के नाम पर ही हाथ जोड़ लेते हैं. बेगूसराय के पूर्व सांसद रामजीवन सिंह की तो यह स्थिति बनी कि वह रोते हुए पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए. अनुशासन का डंडा चलाकर पार्टी के क्षत्रपों को काबू में रखने वाले नीतीश ने उनकी वरिष्ठता का भी ख्याल नहीं रखा था. 2000 में मोकामा से विधायक बने सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह ने निर्दलीय विधायकों को एकजुट करके मोर्चा बनाया और ताक़त लगाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की. पीरो से तीन बार विधायक रहे सुनील पांडे ने भी शाहाबाद क्षेत्र में नीतीश को मजबूती दिलाने में हरसंभव भूमिका निभाई, लेकिन बाहुबली होने का भय दिखाकर दोनों को कमजोर किया गया.

इसी तरह विधायक मुन्ना शुक्ला भी हाशिए पर डाल दिए गए. नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री अजीत कुमार बार-बार यह सवाल पूछते हैं कि कोई मुझे यह तो बताए कि मुझे किस अपराध की सजा मिली है. वीणा शाही भी जदयू में एक किनारे पर खड़ी दिखाई पड़ती हैं. जहानाबाद के सांसद डॉ. जगदीश शर्मा ने नीतीश कुमार के एंटी परिवारवाद वैक्सीन को लेने से इंकार कर पत्नी शांति शर्मा को निर्दलीय घोसी के अखाड़े में उतारा तो जवाब में मतदान के दिन राज्य पुलिस की एसटीएफ को उतार दिया गया. जगदीश शर्मा के समर्थकों की चुन-चुन कर पिटाई की गई. शासन द्वारा हरसंभव उपाय अपनाए जाने के बावजूद जगदीश शर्मा की पत्नी जीत गईं. जगदीश शर्मा के साथ हुए सुलूक ने अरुण कुमार प्रकरण की याद दिला दी. अंतिम चोट ललन सिंह पर की गई. तमाम दूसरे कारणों के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, श्याम रजक, संजय सिंह और निहोरा यादव जैसे नेताओं का पार्टी में आना ललन सिंह के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी. बताया जाता है कि इसके अलावा अन्य कई राजनीतिक फैसलों में भी ललन सिंह को भरोसे में नहीं लिया गया. इस वजह से दोनों दोस्तों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि सीधी बातचीत का रास्ता भी बंद हो गया. पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महादलित वोटबैंक को मजबूत करने में लगे नीतीश कुमार और जदयू में आंतरिक लोकतंत्र एवं कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की लड़ाई छेड़ने वाले ललन सिंह के बीच सुलह कराने की शरद यादव की कोशिश भी बेकार गई तथा विजय कुमार चौधरी को जदयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया. ललन सिंह फिलहाल बिना ताज और राज के जदयू में रहकर कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार अपने नए राजनीतिक प्रयोग को सफल बनाने के लिए दिन-रात पसीना बहा रहे हैं. ललन सिंह के समर्थकों का कहना है कि वह जल्दी किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ते हैं तो छोड़ते भी नहीं. ललन सिंह के हर राजनीतिक क़दम पर उनके समर्थकों की नज़र है. देखना है कि वह अपने समर्थकों का भरोसा कहां तक बरक़रार रख पाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

वीणा शाही

मुन्ना शुक्ला

रामजीवन सिंह

सूरज भान सिंह

अजित कुमार

जगदीश शर्मा

श्याम सुंदर सिंह

सुनील पांडे

अरुण कुमार

भोला सिंह

रेलवे पुलिस से साठगांठ रखने वाले दबंग इस धंधे को खुलेआम कराने से भी नहीं हिचकते. इस विकसित ज़िले के होटलों का भाड़ा वैसे भी अधिक है.

सच तो यह है कि जब वे जवान थे तो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत थे, लेकिन जब परिवार बढ़ा, ख़र्च और ज़िम्मेदारियां बढ़ीं तो महंगाई के इस दौर में बेरोज़गार हो गए.

टिकट के दावेदारों की लंबी फ़ौज

अरुण सिंह

कैलाश भगत

ताजउद्दीन रैयान

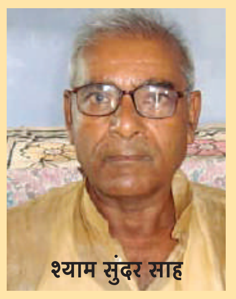
श्याम सुंदर साह

राजीव रंजन

संजीव कुमार झा

आलोक रंजन

सुशील कुमार यादव

महेंद्र शर्मा

किशोर कुमार मुन्ना

रंजीत यादव

सोहन झा

आगामी चुनाव में सहरसा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर परिसीमन की वजह से बदली-बदली सी दिखेगी, क्योंकि परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र से यादव बाहुल्य प्रखंड सत्तरकटैया हटाकर अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र सौर बाज़ार शामिल किया गया है. परिसीमन के बाद सहरसा शहरी क्षेत्र, सदर प्रखंड कहरा एवं सौर बाज़ार प्रखंड की ओर ग़ौर करें तो अब यह विधानसभा क्षेत्र पचपनियां बाहुल्य तो होगा ही, लेकिन निर्णायक भूमिका ब्राह्मण वोटों की होगी. वैसे भूमिहार, राजपूत, यादव एवं मुसलमान जिधर जाएंगे, उस राजनीतिक दल का पलड़ा भारी साबित हो सकता है.

परिसीमन पूर्व इस क्षेत्र से तेरहवें और चौदहवें विधानसभा चुनाव में भाजपा के संजीव कुमार झा पचपनियां एवं ब्राह्मण वोटों के बल पर ही विधानसभा पहुंचे थे. शिकस्त खाने वाले राजद उम्मीदवार पूर्व विधायक प्रो. अब्दुल गफूर रहे. लेकिन परिसीमन के बाद इस क्षेत्र से यादवों और मुसलमानों का समीकरण कुछ इस प्रकार बना है कि लोजपा प्रत्याशी किसी भी दल को सीधे टक्कर दे सकता है. राजद भी लोजपा से अलग हटकर सीट निकालना चाहे तो असंभव ही होगा. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महादलित कार्ड इन क्षेत्रों में हावी तो ज़रूर है, लेकिन प्रमुख दलित पासवान एवं अन्य वोट भी जीत के आधार वोट में ही गिने जाएंगे. सत्ताधारी दल समेत सभी दलों के युवाओं की नज़र सहरसा की ओर टिकी है. इस विधानसभा क्षेत्र पर पूर्व सांसद सूर्य नारायण यादव, निर्दलीय विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व विधायक सतीश चंद्र झा, कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष डॉ. तारानंद सादा, पूर्व मंत्री एवं जदयू नेता अशोक कुमार सिंह सरीख़े लोग दावेदारी कर रहे हैं. लोजपा, राजद, कांग्रेस, भाजपा और जदयू में कई ऐसे युवा, जुझारू एवं कर्मठ नेता हैं, जो इस चुनाव में अपनी क़िस्मत आज़माना चाहते हैं. युवा लोजपा नेता महेंद्र शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर साह, कैलाश प्रसाद भगत, मो. ताजउद्दीन, रंजीत यादव, भाजपा नेता डॉ. आलोक रंजन, भाजपा अध्यक्ष राजीव रंजन, पूर्व ज़िलामंत्री आरती सिंह, जदयू के ज़िला महासचिव सुशील कुमार यादव, युवा अध्यक्ष सोहन झा, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और बद्री प्रसाद यादव आदि मुख्य रूप से दावेदार हैं. इनमें राजद के श्याम सुंदर साह और कैलाश प्रसाद भगत ख़ुद को वैश्य समेत अन्य वर्गों पर पकड़ वाला नेता मानते हैं. पिछली बार सहरसा विधानसभा सीट से भगत को टिकट मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक़्त पर कुछ ख़ास जातीय समीकरणों के चलते उन्हें टिकट नहीं मिला. इस विधानसभा सीट पर भाजपा का क़ब्ज़ा है. पार्टी के अंदर इस सीट को झटकने के लिए कई नए चेहरे आस लगाए हुए हैं. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या दो लाख 92 हज़ार 158 है. अनुमानों के मुताबिक़, यादव 32 हज़ार, मुसलमान 22 हज़ार, ब्राह्मण 35 हज़ार, राजपूत 14 हज़ार और दलित एवं महादलित समेत ग़ैर यादवों की संख्या एक लाख 89 हज़ार 158 के क़रीब है. सहरसा के लिए युवाओं की लंबी फ़ौज विभिन्न दलों से मैदान में उतरने का मन बनाए हुए है. सभी दलों के लिए चुनौती बना राहुल गांधी का युवा टैलेंट हंट इन सभी को उम्मीदवारी के लिए प्रेरित कर रहा है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सभी दलों को सहरसा के लिए अपना प्रत्याशी चुनने के लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ सकता है.

एस सोनी
feedback@chauthiduniya.com

बेतिया विधानसभा : रेणु का पत्ता साफ़ करने में जुटे दिग्गज

> सांप्रदायिकता के आधार पर जीत-हार अथवा मतदाताओं की गोलबंदी का खेल भी समाप्ति के कगार पर है. इस सीट पर राज्य की कला एवं संस्कृति मंत्री रेणु देवी का क़ब्ज़ा है. पिछले तीन चुनावों में सांप्रदायिक गोलबंदी के आधार पर उन्होंने बाज़ी मारी, लेकिन परिसीमन के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 22 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गई है.

रेणु देवी

अनिल झा

महेंद्र यादव

ए राय

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही राजनीतिक दलों में भी धींगामुश्ती शुरू हो गई है. टिकट के दावेदारों की फ़ेहरिस्त काफ़ी लंबी है. इस बीच पोस्टर और बैनर लगाने के लिए युद्ध सा छिड़ गया है. दावेदार जनसेवा में भी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं. पश्चिम चंपारण ज़िला मुख्यालय बेतिया विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद आकार में छोटा हो गया है. लिहाज़ा मतदाताओं की संख्या भी कम हुई है. इसके साथ ही अल्पसंख्यक मतदाताओं का दबाव भी ख़त्म हो गया है. सांप्रदायिकता के आधार पर जीत-हार अथवा मतदाताओं की गोलबंदी का खेल भी समाप्ति के कगार पर है. इस सीट पर राज्य की कला एवं संस्कृति मंत्री रेणु देवी का क़ब्ज़ा है. पिछले तीन चुनावों में सांप्रदायिक गोलबंदी के आधार पर उन्होंने बाज़ी मारी, लेकिन परिसीमन के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 22 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गई है. वहीं मंत्री पद पर पहुंचने के बाद रेणु पार्टी के अंदर की खेमेबंदी को दूर करने में नाकाम रहीं. इस वजह से पार्टी के कई दिग्गज आगामी चुनाव में रेणु देवी का पता साफ़ करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं. पूर्व ज़िलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल झा की पकड़ कार्यकर्ताओं पर मज़बूत मानी जाती है. वह लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टिकट के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत करते रहे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्हें निराश होना पड़ा. आगामी चुनाव में खम ठोकने लिए वह तैयारी में जुट गए हैं. झा समर्थकों का कहना है कि बेतिया की बेटी के नाम पर रेणु देवी को दहेज़ स्वरूप तीन बार विधायक बनाया गया. उन्हें अब यह सीट स्वेच्छा से भाइयों के लिए खाली कर देनी चाहिए, नहीं तो बदले माहौल में उनकी और पार्टी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी. अनिल ने ऐलान किया कि अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करूंगा. इधर रेणु ने जीत की हैट्रिक के पीछे सांप्रदायिक गोलबंदी के योगदान और पार्टी के अंदर खेमेबंदी के आरोप को सिरे से ख़ारिज़ करते हुए कहा कि मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में वृद्धि हुई है. सभी जाति एवं धर्म के मतदाताओं में उनकी गहरी पैठ है. हर जगह उनका काम बोल रहा है. शीर्ष नेतृत्व पर उन्हें पूर्ण भरोसा है. लिहाज़ा उन्हें बेटिकट करने का दम किसी में नहीं है. राजद ने मंत्री पर भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. पूर्व विधायक बीरबल यादव ने उन पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता दुबली होती गई और मंत्री की धन-संपदा में वृद्धि होती गई. राजद के बहुचर्चित नेता मोतिउर रहमान के निधन के बाद बीरबल यादव फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव के क़रीब पहुंचने में कामयाब रहे. पिछले लोकसभा चुनाव में राजद-लोजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रकाश झा के पक्ष में ज़बरदस्त अभियान चलाकर बीरबल यादव ने अपनी अग्नि परीक्षा भी दे दी है. प्रमाणपत्र देने का काम अब लालू यादव के हाथ में है. बेतिया के चर्चित ठेकेदार संजय शाही बंधु हत्याकांड में आरोपित बाहुबली आलिंद राय इस दोहरे हत्याकांड में फंसाने के लिए मंत्री रेणु देवी को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. वह कहते हैं कि जनता की अदालत से बढ़कर कोई दूसरी अदालत नहीं है. वह इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव में रेणु को परास्त करने की तैयारी में लग गए हैं. राजद में वह ख़ुद पर केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह का वरदहस्त होने का दावा कर रहे हैं. आलिंद राय का कहना है कि यदि पार्टी को बेतिया सीट चाहिए तो मुझे टिकट देकर देख ले. राजद के युवराज नवीन सिंह ख़ुद को युवा दिलों की धड़कन बता रहे हैं. राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की क़वायद से वह टिकट के प्रबल दावेदार बन गए हैं. इसके अलावा महेंद्र यादव, मंगल यादव, राकेश कुशवाहा, रूपेश सिंह एवं ब्रज किशोर यादव आदि भी दौड़ में शामिल हैं. इधर लोजपा और जदयू के भी कई नेता ऐसे हैं, जो तालमेल की राजनीति से उब गए हैं. वे दूसरे दलों के टिकट पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं और अंदर ही अंदर गोटी फिट करने में लगे हैं. पिछले कई चुनावों में हास्यास्पद बनी कांग्रेस राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद ख़ासी उत्साहित है. कल तक कांग्रेस के नाम पर मुंह बिदकाने वाले आज ख़ुद को उसकी टिकट का दावेदार बता रहे हैं. प्रखंड प्रमुख मदन मोहन तिवारी उर्फ़ मुन्ना तिवारी सबसे आगे हैं. इसके अलावा मो. कामरान, विनय शाही एवं अबुल कलाम ज़ौहरी आदि के नाम भी कांग्रेसी दावेदारों में शामिल हैं.

मीना कुमारी
feedback@chauthiduniya.com

विकास योजनाओं पर भ्रष्टाचार हावी

कार्यालय नगर पंचायत महनार
जन्म-मृत्यु निबंधन अवश्य करायें
महनार

सरकार द्वारा विकास के लिए दिए जा रहे पैसों की बंदरबांट को लेकर महनार नगर पंचायत में आपसी खींचतान और द्वंद्व चरम पर है. यही वजह है कि महनार में विकास योजनाओं और साफ़-सफ़ाई के कामों पर ग्रहण लगता जा रहा है. संवैधानिक रूप से नगर निकायों को स्थानीय सरकार माना जाता है और वह अपनी आय से किसी भी तरह का जन कल्याणकारी कार्य करा सकता है, लेकिन बिहार के अधिकतर नगर निकायों की वित्तीय स्थिति बद से बदतर है. राज्य और केंद्र सरकार ने समय-समय पर अनुदान देकर इन्हें जीवित रखा है. अलग हटकर देखा जाए तो सरकारी पैसा ही विकास का पहिया रुकने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. वैशाली ज़िले की महनार नगर पंचायत को ही लें. राज्य सरकार का आदेश आया कि विकास कार्य सरकारी अभिकर्ता के माध्यम से न कराकर ठेकेदारी प्रथा से कराए जाएंगे. ठेकेदारों का पंजीकरण शुरू हुआ, लेकिन आवेदन लेने वाला कर्मचारी ही ग़ायब हो गया. मामला नगर विकास मंत्री तक गया, वहां से ज़िलाधिकारी को कहा गया. तब ज़िलाधिकारी ने अनुमंडलाधिकारी को जांच के लिए भेजा. अनुमंडलाधिकारी ने बैठकर आवेदन लिए. कुछ वार्ड आयुक्तों ने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि वे स्वयं सरकार हैं और अनुमंडलाधिकारी इसमें हस्तक्षेप कर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं.

बहरहाल, मामला निविदा समिति के पास गया (जिसमें वार्ड आयुक्तगण ही हैं). समिति ने कई ठेकेदारों का पंजीकरण विभिन्न कारणों से रोक दिया. बताया जाता है कि आधा दर्जन ठेकेदार ऐसे हैं, जो वार्ड आयुक्तों के चहेते माने जाते हैं, उनका पंजीकरण हो गया. वंचित ठेकेदारों ने हार नहीं मानी. वे मंत्री के पास गए. वहां से निर्देश दिया गया कि या तो सभी का पंजीकरण करें या बिना पंजीकरण के उक्त निविदा प्रस्ताव को सामान मान्यता दें. इसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही. तब जाकर नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र लिखकर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए उन्हें स्मरण कराया कि पत्रांक 205, दिनांक 27 जनवरी 2009 द्वारा निर्देश दिया गया था कि अन्य सरकारी विभागों में निबंधित ठेकेदारों को भी निविदा में समान अवसर दिया जाए, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है. संयुक्त सचिव ने ज़िला पदाधिकारी से इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजने का अनुरोध भी किया.

> मामला निविदा समिति के पास गया (जिसमें वार्ड आयुक्तगण ही हैं). समिति ने कई ठेकेदारों का पंजीकरण विभिन्न कारणों से रोक दिया. बताया जाता है कि आधा दर्जन ठेकेदार ऐसे हैं, जो वार्ड आयुक्तों के चहेते माने जाते हैं.

हालांकि इस पत्र के बाद नगर पंचायत से निबंधन की बाध्यता समाप्त कर दी गई, मगर स्थिति इस तरह की बना दी गई कि यह पॉकेट टेंडर होकर रह गया. गत 17 फरवरी को संबंधित कर्मचारी ग़ायब रहा, इसलिए निविदा फॉर्म नहीं बिक सके. हालांकि कई वार्ड आयुक्तों का कहना है कि दो दिनों तक तो फॉर्म बिकते रहे, लेकिन तीसरे दिन कर्मचारी की तबीयत ख़राब हो गई. वहीं विरोधी पक्ष ने बताया कि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने अपने चहेतों को फॉर्म दिलाकर बिक्री बंद करा दी. इस बात की शिकायत लोगों ने डीएम से की. उन्होंने जांच के लिए अनुमंडलाधिकारी को भेजा. संबंधित ज़िले का नाम जोड़ कर उनके प्रतिवेदन के आलोक में निविदा फॉर्म की बिक्री की तिथि बढ़ाई गई. तब जाकर ठेकेदार टेंडर डाल सके. वर्तमान में यह मामला निविदा समिति के पास विचाराधीन है. उल्लेखनीय तथ्य यह है कि तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष आशा देवी ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर शौचालय योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. मंत्री ने जांच करने और रिपोर्ट आने तक सारी योजनाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया. ज़िलाधिकारी ने उक्त आदेश के अनुपालन का दायित्व अनुमंडल पदाधिकारी को दिया, लेकिन उक्त आदेश का तात्कालिक कोई अनुपालन नहीं हुआ. बाद में जांच प्रतिवेदन भेजा गया, मगर कार्य बेरोकटोक जारी रहा.

नगर पंचायत का सबसे अनिवार्य कार्य सफ़ाई व्यवस्था है, लेकिन इस मामले में यह संस्था विफल है. समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सफ़ाई कार्य एनजीओ से कराने का सुझाव दिया, लेकिन संस्था इस पर गंभीर नहीं है. वार्ड आयुक्त सहदेव साह ने सफ़ाई हेतु बॉबकट मशीन और पे रोटर आदि ख़रीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसे ख़ारिज़ कर विकास राशि छोटी-छोटी योजनाओं में ख़र्च की जा रही है. नतीजतन सफ़ाईकर्मी शहर का कचरा गंगा में फेंक रहे हैं. सफ़ाई हेतु सरकार से मिला ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं ऑटो की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है. ख़रीदारी के पांच साल गुज़रने के बावजूद अब तक इन वाहनों पर निबंधन संख्या भी अंकित नहीं कराई गई. रखरखाव के अभाव में उक्त वाहन बिल्कुल सड़ चुके हैं. आएदिन ट्रैक्टर का डायनेमो ही चोरी हो जाता है. ऑटो गत दो साल से बंद पड़ा है और उसके कई क़ीमती पुर्जे ग़ायब हो चुके हैं.

अंजुम परवेज
feedback@chauthiduniya.com

गंदगी के ढेर पर लगेगा राजगीर का मलमास मेला!

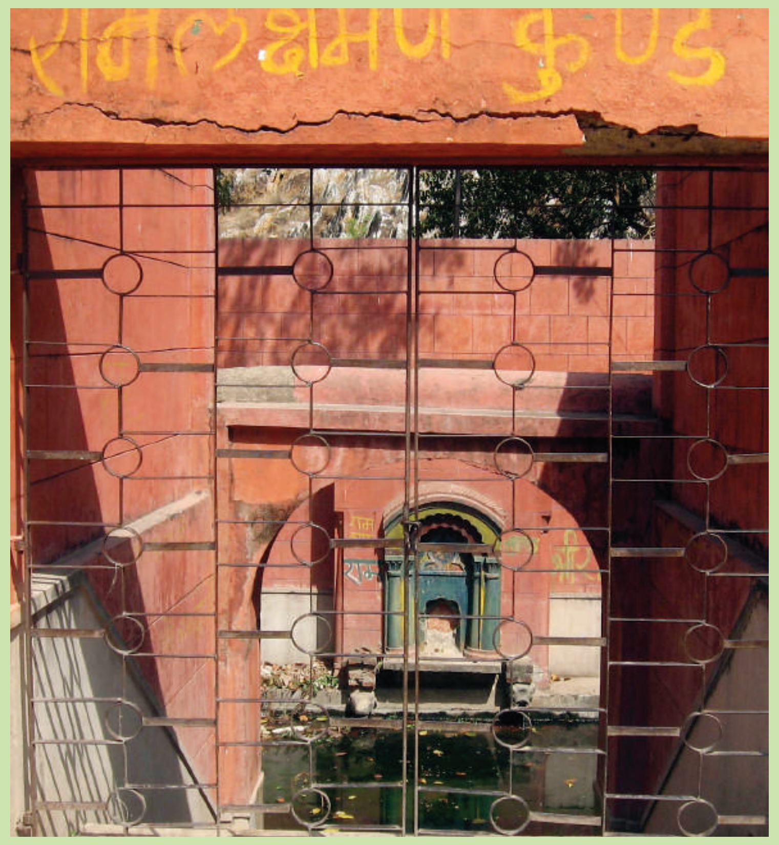

> राजगीर में पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार द्वारा समकालीन योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से कुंड के बगल में एक तालाब का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच दिसंबर 2009 को किया.

विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है. इस मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मकुंड में स्नान और पूजा-अर्चना करने आते हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक माह तक चलने वाले इस मेले में 33 करोड़ देवी-देवता राजगीर में ही वास करते हैं. मेले के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या अनुष्ठान वर्जित माना जाता है. यह मास निंदित, अशुद्ध और अपूज्य भी माना जाता है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक़, किसी भी नए कार्य के संकल्प में सभी देवी-देवताओं का यथोचित स्मरण किया जाता है, लेकिन अधिमास का नहीं. मलमास में तीर्थयात्रा, देवता-गृह देवता पूजन, मंदिर का निर्माण, यज्ञ, विवाह, उपनयन, द्विरागमन, राज्याभिषेक और गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं. इस अवधि में द्वादशाह, श्राद्ध, जातकर्म संस्कार, दैनिक पूजा, दान-संध्योपासना आदि कार्य करने योग्य हैं. इस अवधि में मृत प्राणियों का श्राद्ध एवं पिंडदान राजगीर में वैतरणी नदी के तट पर किया जाता है. इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां यज्ञ, दान, स्नान, होम एवं श्राद्ध करने पहुंचते हैं. माना जाता है कि इस अवधि में यहां श्राद्ध करने से सभी प्राणी अक्षय मुक्ति और बैकुंठ पाते हैं. पौराणिक अवधारणा है कि इस पवित्र नदी में मात्र एक गोता लगा लेने से महापापी भी पुण्यात्मा हो जाता है. कहा जाता है कि मलमास के दौरान एक माह तक राजगीर में कौआ नहीं दिखाई देता है. इसके पीछे यह धारणा है कि मलमास में आने के लिए सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भूलवश काकभुसुंडि छूट गए. यही कारण है कि एक माह तक कौआ राजगीर छोड़ कर कहीं और चला जाता है. इस दौरान 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास राजगृह की पावन धरती पर होता है. यही कारण है कि लाखों की संख्या में सनातन धर्मावलंबी और श्रद्धालु राजगीर पहुंच कर कुंडों और नदियों में स्नान करके पुण्य हासिल करते हैं.

मेले को शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन सफ़ाई की तरफ़ प्रशासन ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा है. मेला क्षेत्र के मंदिरों के इर्द-गिर्द कचरे का ढेर लगा हुआ है. पिछले मलमास मेले में भी सफ़ाई और पेयजल की समस्या से श्रद्धालुओं को दो-चार होना पड़ा था. लगता है कि वही स्थिति इस बार भी सामने आएगी. मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन कुंड में स्नान करते हैं. पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री सुरेंद्र प्रसाद तरुण का मानना है कि राजगीर मकर संक्रांति मेले एवं श्रावणी मेले की तरह आने वाले दिनों में राजगीर मलमास मेला भी समाप्त हो जाएगा. पिछले मलमास मेले की तरह इस बार भी ज़मीन की बंदोबस्ती दोगुने से अधिक राशि लेकर की जा रही है, जिसने मेले के भविष्य को ख़तरे में डाल दिया है. पिछली बार ठेकेदारों ने ज़मीन की बंदोबस्ती अपने हाथ में लेकर मेले में आए थिएटरों और सर्कस मालिकों से ज़बरन अधिक वसूली की थी. अगर शासन-प्रशासन ने समय रहते इस तरह की ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश न लगाया तो मेला एक दिन ख़त्म हो जाएगा.

राजगीर में पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार द्वारा समकालीन योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से कुंड के बगल में एक तालाब का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच दिसंबर 2009 को किया. लोगों ने भी सोचा कि कुंड को भीड़ से निजात मिलेगी और पर्यटक एवं श्रद्धालु खुले सरोवर में स्नान करने का आनंद लेंगे, लेकिन तालाब उद्घाटन के दिन ही खुला रहा. उसके बाद तालाब परिसर में प्रवेश बंद कर दिया गया. कुंड क्षेत्र की मरम्मत मलमास के पहले बहुत ज़रूरी है. कुंड के अंदर स्थित पेड़-पौधों एवं मंदिरों की कमज़ोर दीवारों के चलते हादसे की आशंका है. इस पर भी समय रहते ध्यान दिया जाना ज़रूरी है.

डॉ. शोभा कुमारी
feedback@chauthiduniya.com

चलती कार में जिस्मफ़रोशी का धंधा

राजेश सिन्हा

अब तक आपने होटल, रेस्तरां, घर या अड्डे पर जिस्मफरोशी के धंधे की बात सुनी होगी, लेकिन जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे पढ़कर हो सकता है कि आप चौंक जाएं. बिहार के बेगूसराय ज़िले में जिस्मफरोशी का धंधा कारों में चल रहा है. वैसे महानगरों में जिस्मफरोशी के धंधे की शिकायत मिलने पर मामला सुर्ख़ियों में आ जाता है और बड़े पैमाने पर हाय-तौबा मचती है. फिर भी बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मामले की हाई प्रोफाइल जांच भी करा दी जाती है. देह बेचने वाली महिलाओं के साथ-साथ अन्य गुनहगारों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि बेगूसराय ज़िले के विभिन्न होटलों सहित अन्य जगहों पर जिस्मफरोशी का धंधा तो खुलेआम चल ही रहा है, मगर अब बेगूसराय स्टेशन परिसर के पार्किंग स्थल में खड़ी कारों में भी जिस्मफरोशी का धंधा ख़ूब फल-फूल रहा है. दिन में भी यह गोरखधंधा खुलेआम जारी रहता है. दबंग लोगों द्वारा पुलिस के संरक्षण में चलाए जा रहे इस देह व्यापार की जानकारी सभी को है, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है. कुछ वर्ष पहले एक राजदार ने इसके विरोध में स्वर मुखर किया था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई. उसके बाद से कोई भी कुछ बोलने से कतराता है. बड़े ही शातिराना अंदाज़ में संगठित गिरोह इस धंधे को अंजाम देता है. वह पुरानी कार ख़रीद कर उसे स्टेशन परिसर की पार्किंग में खड़ा कर देता है. उसके बाद कोई ख़ुद को कार का मालिक तो कोई चालक बताता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ कारें भाड़े पर चलती हैं तो कुछ यूं ही खड़ी रह जाती हैं. दरअसल खड़ी रहने वाली कारें चलने योग्य हैं ही नहीं. बावजूद इसके ऐसी कारों पर मालिकाना हक़ रखने वाले लोग प्रति माह कम से कम दस हज़ार रुपये कमाते हैं. होटलों में देह सुख भोगने वाले अधिक राशि ख़र्च करते हैं. फिर भी उन्हें पुलिस और बदनामी का भय सताता रहता है. इसलिए कार मालिकों ने कार में जिस्मफरोशी का धंधा ईज़ाद किया है.

रेलवे पुलिस से साठगांठ रखने वाले दबंग इस धंधे को खुलेआम कराने से भी नहीं हिचकते. जानकारों के मुताबिक़, इस विकसित ज़िले के होटलों का भाड़ा वैसे भी अधिक है. जब पराई औरत या लड़की के साथ हमबिस्तर होने की बात सामने आती है, तब यह भाड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है. लेकिन, कार में जिस्मफरोशी कराने वाले भाड़े के नाम पर महज बीस से पचास रुपये लेते हैं. हालांकि अलग-अलग कारों के लिए अलग-अलग भाड़ा भी निर्धारित किया गया है. वैसे सभी कारों को इस तरह के धंधे में इस्तेमाल नहीं किया जाता. जानकारों की बातों पर भरोसा करें तो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में कई सभ्य घरानों की महिलाएं और लड़कियां भी इस धंधे से जुड़ गई हैं. पकड़े जाने के भय से ऐसी महिलाएं और लड़कियां ग्राहकों से सौदा तय करते समय ही स्पष्ट कर देती हैं कि वे किसी होटल या घर के बजाए कार में ऐसा करना पसंद करेंगी. इसके बाद कार के मालिक से सौदा तय किया जाता है. अगर ग्राहक आर्थिक रूप से मज़बूत है तो चलती कार का सौदा किया जाता है. यानी चलती कार में ग्राहक देह सुख का आनंद लेता है. उसके बाद उसे गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है. अगर ग्राहक आर्थिक मामले में मज़बूत नहीं है तो फिर खड़ी कार के मालिक से सौदा तय किया जाता है. इस तरह से कार खड़ी रह जाती है और भाड़ा वसूल लिया जाता है. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ कार में ही इस तरह का धंधा चल रहा है. बेगूसराय स्टेशन का वेटिंग रूम भी जिस्मफरोशी का अड्डा बन गया है. इस तरह की स्थिति से अगर रूबरू होना हो तो स्टेशन परिसर में एक-दो घंटे किसी मुसाफिर की तरह खड़े हो जाइए, सब कुछ ख़ुद-ब-ख़ुद सामने आ जाएगा. स्टेशन परिसर में रेलवे पुलिस के साथ-साथ बेगूसराय नगर थाना पुलिस का जमावड़ा तो दिखेगा, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर आपकी नज़रें शर्म से झुक जाएंगी. खगड़िया, बेगूसराय एवं समस्तीपुर आदि ज़िलों की महिलाएं और लड़कियां रात के अंधेरे में यहां पहुंचती हैं तथा पेट की ख़ातिर रोज़ देह बेचकर चली जाती हैं. ऐसी ही एक लड़की संजना (बदला हुआ नाम) ने बताया कि बचपन में ही उसके मां-बाप का निधन हो गया. परवरिश मामा ने की. बाद में मामी की प्रताड़ना से तंग आकर वह साहेबपुर कमाल से भाग कर बेगूसराय स्टेशन आ गई. पास में पैसे नहीं थे, भूख ज़ोर की लगी थी. वह यात्रियों से भीख मांग रही थी. अभी दो-चार रुपये ही मिले थे कि एक पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ कर थाने चलने को कहा और उसे पॉकेटमार घोषित कर दिया. थाने के बजाए किसी दूसरी जगह ले जाकर पुलिस वाले ने उसके साथ मुंह काला किया. फिर उसे एक कार मालिक के हाथों सौंप दिया. तबसे वह कार मालिक के कहने पर ग्राहकों को देह बेचती है. एवज में उसे जीने लायक रुपये मिल जाते हैं. अब मामा के घर वापस लौटना संभव नहीं है. बदनाम हो जाने के कारण कोई उसका हाथ थामने से रहा. संजना कहती है कि सिर्फ़ वही नहीं, ऐसी कई लड़कियां और महिलाएं हैं, जो इस नरक को भोग रही हैं. बहरहाल, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अगर किसी ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा बेगूसराय ज़िले में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे की जांच की जाए तो कई सफ़ेदपोश चेहरे बेनक़ाब हो जाएंगे.

बेगूसराय जीआरपी थानाध्यक्ष राम इक़बाल शर्मा का कहना है कि इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई आहत पक्ष इस संदर्भ में शिक़ायत नहीं करेगा, तब तक प्राथमिकी दर्ज़ कर आरोपी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती. वैसे भी ऐसे मामलों की ज़िम्मेदारी आरपीएफ की है. हालांकि शर्मा को पता है कि स्टेशन पार्किंग के ठेके की समयावधि समाप्त हो चुकी है. बावजूद इसके पुराना ठेकेदार पार्किंग संभाल रहा है. बात ही बात में शर्मा ने इशारा किया कि राजनीतिक दबाव के चलते अवैध मामला जानने के बाद भी सरकारी लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते. इस मसले पर जब बेगूसराय के आरपीएफ प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.

feedback@chauthiduniya.com

उद्योगविहीन सीवान और बीमार मज़दूर

वर्षों से बंद है सीवान एसकेजी शुगर मिल.

सीवान ज़िला विगत दो दशकों से उद्योगविहीन है. यहां जो भी चंद उद्योग थे, वे सभी सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण बीमार होकर बंद हो गए, जिससे हज़ारों कामगारों के परिवार आज भुखमरी की कगार पर हैं. बावजूद इसके वित्तीय कमी का रोना रोकर राज्य सरकार इन बंद उद्योगों को चालू नहीं करा पाई. आर्थिक तंगी के कारण सैकड़ों कामगार एवं उनके परिजन इलाज के अभाव में असमय ही काल के ग्रास बन गए. अधिकांश कामगार दैनिक मज़दूरी करके पेट की आग बुझाने में भी असमर्थ हो गए हैं. सच तो यह है कि जब वे जवान थे तो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत थे, लेकिन जब परिवार, ख़र्च और ज़िम्मेदारियों में बढ़ोत्तरी हुई तो वे बेरोज़गार हो गए.

एक समय था, जब सीवान में तीन चीनी मिलें थीं. इसके अलावा शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री भी थी. बाद में सूत मिल और चर्म शोधशाला-कारखाना की स्थापना हुई, लेकिन सारी मिलें और कारखाने एक के बाद एक करके बंद होते गए. कांग्रेस के ही शासनकाल में पचरूखी प्रखंड मुख्यालय स्थित पुरानी चीनी मिल और शराब फैक्ट्री बंद हो गई. इसके बाद जदयू-राजद के शासनकाल में निगमाधीन हुईं न्यू सीवान शुगर मिल एवं एसकेजी शुगर मिल वित्तीय संकट के कारण बंद हो गईं. इन दोनों चीनी मिलों के अलावा सीवान शहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित स्पिनिंग मिल और चर्म शोधशाला-कारखाना भी अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद बंदी के शिकार हो गए.

इन मिलों के बंद हो जाने से बेकार हुए हज़ारों कामगारों के परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं. बंद हुई तीनों चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का करोड़ों रुपया बकाया है. इन मिलों के बंद हो जाने से निराश किसानों ने गन्ने की खेती करना लगभग बंद ही कर दिया. कुछ छोटे किसान आज गन्ने की थोड़ी सी खेती करते हैं, लेकिन केवल गुड़ बनाने के लिए. जबकि उत्तर बिहार में गन्ने की खेती के लिए सीवान का नाम प्रमुख था. यहां की शुगर मिलों द्वारा उत्पादित चीनी काफ़ी उम्दा क़िस्म की होती थी, जिसकी हर जगह मांग थी. इसी प्रकार यहां पर दो दशक पूर्व स्थापित सहकारी सूत मिल बीच-बीच में चालू हुई, लेकिन वह भी वर्षों से बंद पड़ी है. मिलों के भवन भी जर्जर होने लगे हैं. वर्षों से जंग खा रही मशीनें ख़राब और बर्बाद हो गई हैं. इसी प्रकार लगभग दो दशक पूर्व ज़िला मुख्यालय से दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज़मालहाता गांव के बुनकरों के लिए क्लॉथ कलर प्रिंटिंग मशीन की स्थापना हेतु भवन का निर्माण कराया गया था. कुछ मशीनें भी लगाई गईं, लेकिन उनका न उद्घाटन हुआ और न ही वे चलीं. वर्षों से वहां पड़ी मशीनें बर्बाद हो गईं और भवन ध्वस्त हो गया.

दरअसल वित्तीय संकट और बिजली की कमी के कारण ज़िले के छोटे-छोटे उद्योग एक के बाद एक बंद होते गए, जिससे ज़िला उद्योगविहीन हो गया. इस ओर न तो प्रशासन का ध्यान है और न सुशासन का. जनप्रतिनिधि भी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं. राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण सीवान हमेशा विकास से वंचित रहा. एक सरकारी आदेश के तहत गत वर्ष ज़िले के सदर प्रखंड अंतर्गत ओरमा और बालमुकुंद गांव में नई शुगर मिलों की स्थापना हेतु ज़िला प्रशासन ने अधिग्रहण के लिए ज़मीन की नाप करानी चाही. लेकिन, जब मजिस्ट्रेट एवं अमीन पुलिस बल के साथ ज़मीन की नाप के लिए वहां पहुंचे तो कुछ नेताओं के इशारों पर ग्रामीणों ने लाठी के बल पर सभी को खदेड़ लिया. बाद में नई चीनी मिल की स्थापना राजनीतिक दलों का मुद्दा बन गई. शहर से लेकर समाहरणालय तक धरना-प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

धनंजय मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

बहुत कम लोगों को पता होगा कि रंभा हिंदी और भोजपुरी में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकती हैं.

ट्रक एंट्री का गोरखधंधा धड़ल्ले से जारी

नीतीश सरकार एक ओर जहां राज्य की माली हालत एवं राजस्व की कमी का रोना रोते हुए विकास के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता और बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधिकारी-दलाल गठजोड़ के कारण राज्य को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है.

ग़ौरतलब है कि पूर्णिया प्रमंडल से होकर कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से एनएच-31 पूर्णिया होते हुए किशनगंज, सिल्लीगुड़ी और उत्तर पूर्व के राज्य असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश होकर बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से होकर गुजरता है. राजमार्ग संख्या 57 पूर्णिया एवं अररिया होकर जोगबनी में नेपाल की सीमा को छूता है. वहीं दालकोला के निकट एनएच-31 से एक राजमार्ग कोलकता को जाता है. आज इन्हीं राजमार्गों से असम का कोयला, सीमेंट, चावल, गेहूं, दलहन, खाद्य तेल, सुपारी, चीनी, चायपत्ती, सिल्लीगुड़ी बेडमिसाली गिट्टी और तस्करी के लिए पशुओं आदि की ढुलाई ट्रकों द्वारा होती है.

उक्त ओवरलोड ट्रक मोटर वाहन अधिनियम का पालन किए बिना सड़कों पर दौड़ते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी एवं स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के अनुसार, ट्रक एंट्री का धंधा वर्षों पुराना है, जिसे दलालों द्वारा परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित किया जाता है. बताया जाता है कि छह चक्का वाले ओवरलोड ट्रक से 600-800 रुपये, दस चक्का वाले ट्रक से 1000-1500 रुपये, 16 चक्का वाले ट्रक से 2000 एवं 18 चक्का वाले ट्रक से 2500 रुपये दलालों द्वारा वसूले जाते हैं. एंट्री दलाल एक निश्चित समय सीमा के अंदर ट्रकों को सड़कों पर छोड़ते हैं. वैसे अधिकांश ट्रक रात में ही सड़कों पर निकलते हैं.

किशनगंज, बंगाल के धनतोला, पांजीपाड़ा, दालकोला, डगरुआ, डंगराहा, गुलाब बाग, जीरो माइल एवं गेड़ाबाड़ी आदि जगहों पर एंट्री के दलालों ने दिखावे के लिए लाइन होटल खोल रखे हैं. यहीं से इस धंधे को वे संचालित करते और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर नज़र रखते हैं. जानकारी के अनुसार, दलाल गाड़ी का नंबर एसएमएस द्वारा भ्रष्ट मोबाइल दारोगा, आरटीओ-एमवीआई एवं डीटीओ के निजी सहायक के मोबाइल पर भेजते हैं, जहां से ट्रक पास करने का क्लीयरेंस मिलता है. आश्चर्य की बात यह है कि इन अधिकारियों के पास विभागीय कर्मचारी बहुत कम रहते हैं. अधिकतर निजी लोगों को सुविधा के अनुसार रखा जाता है, जिनकी दलालों पर पकड़ होती है और वे उनके क्रियाकलाप से परिचित होते हैं.

ट्रक एंट्री के धंधे में कई सिंडिकेट काम कर रहे हैं. किसी के पास सिल्लीगुड़ी से आने वाले पत्थर बेडमिसाली एवं पाकुड़ स्टोन का काम है तो किसी के पास असम के कोयले का. ट्रक एंट्री माफियाओं के कई सरगनाओं ने पश्चिम बंगाल के दालकोला में दिखावे के लिए लाइन होटल खोल रखे हैं, लेकिन उनका वास्तविक काम ट्रक को एंट्री दिलाना है. एक सरगना डगरुआ में भी है, जो इस धंधे में पैठ बनाए हुए है. ऐसे लोग कभी-कभी परिवहन विभाग के अधिकारियों पर धौंस जमाने से भी बाज नहीं आते और उन्हें षड्यंत्र रचकर फंसाने का प्रयास करते हैं. इन्हीं लोगों के षड्यंत्र का शिकार अभी हाल में मोबाइल दारोगा महेंद्र प्रताप सिंह हुए, जिन पर एक मामला डगरुआ थाने में दर्ज़ किया गया. कई लोग राज्य परिवहन विभाग को करोड़ों का चूना लगा कर अपार संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं. कुछ ने तो अपनी राजनीतिक पैठ बना ली है और विधायक-सांसद बनने का सपना पालने लगे हैं. इनमें से कई पर डगरुआ एवं बायसी समेत कई थानों में विभिन्न मामले दर्ज़ हैं, लेकिन उनका धंधा जारी है. ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की आड़ में भी बेडमिसाली स्टोन की एंट्री कराई जाती है. एक ट्रांसपोर्टर ने बताया कि आरटीओ की न्यूनतम कमाई प्रति माह दो से तीन लाख रुपये है. वहीं मोबाइल वालों की कमाई प्रति माह लाखों में है.

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

अभी अलविदा न कहना...

नब्बे के दशक में कॉलीवुड की दो शीर्ष अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में एक साथ कदम रखा. कुछ सालों तक दोनों तारिकाओं का जलवा बरकरार रहा, लेकिन दोनों ही बॉलीवुड की रेगुलर-ए-लिस्ट की केटेगरी में अपना नाम दर्ज कराने में नाकाम रहीं. यहां हम बात कर रहे हैं रंभा और नगमा की. दोनों अभिनेत्रियों में और भी समानताएं हैं. दोनों आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित चेहरों में शुमार हैं. हाल में रंभा ने शादी कर ली. इससे उनके कई प्रशंसकों को लगा कि अब वह भोजपुरी फिल्मों को अलविदा कह देंगी, लेकिन रंभा फिलहाल भोजपुरिया फिल्म नगरी को अलविदा कहने के मूड में नहीं हैं. हालांकि फिजां में इस तरह की बातें तैर रही थीं कि शादी के बाद रंभा कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगी और फिर अपनी अधूरी फिल्मों को निपटाने में जुट जाएंगी. बांके बिहारी एमएलए जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. गौरतलब है कि रंभा राम-बलराम, पूरब और पश्चिम, रसिक बलमा जैसी फिल्मों में भोजपुरी सुपर स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी एवं निरहुआ के साथ अपनी जोड़ी जमा चुकी हैं. उनका भोजपुरी प्रेम तभी जाहिर हो गया था, जब वह यहां की इंडस्ट्री के विकास के लिए लालू प्रसाद से मिली थीं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि रंभा हिंदी और भोजपुरी में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकती हैं. उनके मुताबिक, मैंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है और मेरे लिए भाषा मैटर नहीं करती. मैं ज्यादातर डबिंग आर्टिस्ट का सहारा लेती हूं. हिंदी फिल्मों में उनके लिए मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी डब किया करती थीं. वह कहती हैं कि मुझे अंग्रेजी में स्क्रिप्ट दी जाती है और मैं भोजपुरी एक्सप्रेशन के साथ उसका रिहर्सल करती हूं, बाकी का काम निर्देशक समझा देते हैं. अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि रंभा फिल्मों से कितना लगाव रखती हैं. ऐसे में आपको लगता है कि वह भोजपुरिया फिल्मों को अलविदा कहेंगी?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शिबू सोरेन

रघुवर दास

पंचायत चुनाव की कठिन डगर

झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके सुर में सुर मिलाकर बरसात के पहले पंचायत चुनाव करा लेने का दावा कर रहे हैं. हाल में भूरिया आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह भूरिया एक कार्यशाला में शिरकत करने रांची आए. वह राज्यपाल समेत अन्य प्रमुख राजनेताओं से मिले. इस मौक़े पर उन्होंने पेसा क़ानून के तहत जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया. उनका कहना था कि शेड्यूल एरिया धारा 244 के तहत केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह यहां की आदिम जनजातियों और मूल निवासियों को उनका हक़ दिलाए. उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पर पहला हक़ आदिवासियों का ही बनता है. बहुराष्ट्रीय कंपनियां पंचायत चुनाव नहीं होने देना चाहतीं, लेकिन पेसा एक्ट के जरिए चुनाव कराना ही इस क्षेत्र के विकास का एकमात्र रास्ता है. उनका यह भी कहना था कि पेसा क़ानून के तहत चुनाव कराने से आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

भूरिया कमेटी के सदस्य बंदी उरांव मानते हैं कि पेसा क़ानून से ग्रामीणों को लघु वन उपज, माइनर मिनरल और बाज़ार की व्यवस्था का लाभ मिलेगा. उनका दावा है कि पेसा क़ानून आदिवासियों के हित में है. इसी प्रकार के विचार सूचना आयुक्त गंगोत्री कुजूर और विकास भारती के अशोक भगत के भी हैं. उनका मानना है कि पेसा क़ानून के तहत पंचायत चुनाव होने से आदिवासी खुशहाल होंगे और राज्य भी खुशहाल होगा.

दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि झारखंड के सदान पेसा क़ानून को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. वे इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. झारखंड के प्रखंडों और जिला मुख्यालयों से लेकर राजधानी तक वे धरना, प्रदर्शन एवं मशाल जुलूस आदि के जरिए अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं. उनका कहना है कि यदि पेसा क़ानून में संशोधन के बगैर चुनाव कराए गए तो राज्य में गृह युद्ध छिड़ सकता है. दरअसल शेड्यूल एरिया एक्ट में ज़िले को प्राथमिक इकाई मान लिया गया है. सदानों का कहना है कि किसी भी ज़िले की सभी पंचायतें आदिवासी बहुल नहीं हैं. कई पंचायतों में तो आदिवासी आबादी है ही नहीं. सदान विकास परिषद के अध्यक्ष पांडे हिमांशु नाथ राय एवं उपाध्यक्ष बब्बन सिंह का कहना है कि सरकार पेसा क़ानून में आवश्यक संशोधन कराने के बाद ही चुनाव कराए तो उचित होगा. शेड्यूल एरिया की प्राथमिक इकाई पंचायत को माना जाए और अन्य विसंगतियां दूर की जाएं, तभी सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो सकता है. 27 प्रतिशत आदिवासियों के लिए 73 प्रतिशत सदानों के हितों की अनदेखी करना कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत न्यायसंगत नहीं है.

ग़ौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा क़ानून के विरोध में फ़ैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेसा क़ानून के तहत पंचायत चुनाव कराने का फ़ैसला देकर हाईकोर्ट के फ़ैसले को उलट दिया. इसकी प्रतिक्रिया भी उल्टी हुई. जहां वर्ष 2005 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद झारखंड के सदान आंदोलित हो उठे. एक तरफ जहां उन्होंने अपना विरोध जताया है, वहीं कई संगठनों में विभाजित सदान इस मुद्दे को लेकर अब एक मंच पर आ चुके हैं. पेसा क़ानून देश के नौ आदिवासी बहुल राज्यों में लागू है. इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं. झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां अभी तक चुनाव नहीं कराए जा सके हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे आदिवासी बहुल राज्य कहा ज़रूर जाता है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी यहां मात्र 27 प्रतिशत है. सदान नेताओं का दावा है कि अब यह प्रतिशत और भी घट गया है.

पेसा क़ानून ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1874 में बने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पर आधारित है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 में भी बहाल रखा गया था. बाद में इसे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया. अब समस्या यह है कि इस एक्ट के तहत पूरे ज़िले को एक इकाई मान लिया गया है, जबकि एक ज़िले में कई प्रखंड होते हैं. एक प्रखंड में कई पंचायतें होती हैं. एक पंचायत में कई गांव होते हैं और एक गांव में कई टोले होते हैं. ज़िले के हर टोले में आदिवासियों की बहुलता हो, यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन क़ानून का दायरा उन पंचायतों को भी समेट लेता है, जहां जनजातीय आबादी शून्य है. वहां दूसरे गांवों से इनके प्रतिनिधि उधार मंगाने होंगे. सदान चाहते हैं कि पेसा एक्ट में संशोधन किया जाए और ज़िले की जगह पंचायत को शेड्यूल एरिया की इकाई माना जाए, लेकिन अब सुप्रीमकोर्ट के फ़ैसले के बाद उसकी पूर्ण पीठ ही सदानों की भावनाओं पर विचार कर सकती है और पार्लियामेंट्री कमेटी ही आवश्यक संशोधन कर सकती है.

बहरहाल बरसात के पहले पंचायत चुनाव कराने का सरकारी दावा कहीं से भी व्यावहारिक नहीं दिखता. हालांकि सरकार ने इस बार के बजट में पंचायत चुनाव के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन जब तक इस क़ानून पर सर्वसम्मति नहीं बनती, चुनाव कराना कई तरह के विवादों को निमंत्रण देने जैसा होगा. राज्य में सत्तारूढ़ लोगों को इसका एहसास है. इसलिए जुबानी जमा खर्च तो किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चुनाव की कहीं कोई तैयारी नहीं दिख रही है.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़

दिल्ली, 5 अप्रैल-11 अप्रैल 2010
www.chauthiduniya.com

महिला-बाल व्यापार का बढ़ता जाल

संध्या पाण्डे

बाज़ारवाद के इस युग में मनुष्य भी बिकाऊ माल बन गया है. बाज़ार में पुरूष की ज़रूरत श्रम के लिए है, तो वहीं स्त्री की ज़रूरत श्रम और सेक्स दोनों के लिए है. इसलिए व्यापारियों की नज़र में पुरूष की तुलना में स्त्री कहीं ज़्यादा क़ीमती और बिकाऊ है. राजधानी भोपाल की 66 बालिकाएं और 70 बालक ऐसे हैं जिनका पिछले एक साल से कोई अता-पता नहीं है. लापता होने वाले बच्चों की उम्र आठ से पंद्रह वर्ष के बीच है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष में राजधानी से कुल 368 बालिकाओं के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज़ करवाई गई थी. इनमें से 302 का पता चल गया है और दो की लाश बरामद की गई है. वहीं 66 बालिकाओं का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. लेकिन केवल 17 मामले आपराधिक प्रकरण के अंतर्गत दर्ज़ किए गए हैं.

इसी तरह, पिछले एक वर्ष में अकेले भोपाल से 334 बालक लापता हुए हैं, जिनमें से 71 का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. वरिष्ठपुलिस अधीक्षक आदर्श कटियार का कहना है कि बालिकाओं के ग़ायब होने के मामले में अब तक किसी गिरोह की सक्रियता होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है फिर भी पुलिस लापता बालिकाओं की खोजबीन कर रही है. भोपाल में पिछले वर्ष पुलिस ने मासूम बालिकाओं का अपहरण कर उन्हें मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफ़ाश किया था. पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरोह ने अनेक क्षेत्रों से लापता हुई छह बालिकाओं को मुंबई, ग्वालियर, पुणे आदि शहरों में भेजने की बात भी स्वीकारी थी. इस गिरोह में चार महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन अदालत में पुलिस इस गिरोह के ख़िलाफ़ पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, लिहाज़ा गिरोह के सभी सदस्य अदालत से बरी हो गए.

> **प्रदेश के कई ज़िलों में पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के व्यापार की सूचनाएं आ रही हैं. इसीलिए उनके लापता होने के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं.**

बच्चों और महिलाओं के व्यापार की प्रक्रिया बहुत ही योजनाबद्ध तरीक़े से की जाती रही है. मंडला के मवई विकासखंड के शकवाहा गांव के निवासी कुंवर सिंह का फलिया के पास 3 एकड़ असिंचित भूमि है. इनके 2 बच्चे ग़रीबी व कुपोषण जनित बीमारियों की भेंट चढ़ चुके हैं. परिवार आजीविका संकट से गुज़र रहा था. इसी गांव की एक महिला कमलावती ने कुंवर सिंह से कहा कि वह अपनी 14 वर्षीय लड़की को उसके साथ दिल्ली भेज दें. इसके पहले भी इस गांव से लड़कियां घरेलू कामकाज के लिए किसी न किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ जाती रही थीं. इसलिए कुंवर ने अपनी बेटी और उसकी 13 वर्षीय सहेली रमा को भी कमलावती के साथ भेज दिया. एक साल पहले रमा अपने गांव वापस आ गई है, वह बताती है हम दोनों को काम दिलाने के वास्ते अलग-अलग घरों में भेजा गया, वे फिर एक-दूसरे से दिल्ली में कभी नहीं मिलीं. उमा कहां और क्या काम करती थी, इसकी जानकारी कमलावती के अलावा और किसी को नहीं थी. उमा नाम की एक और लड़की इसी गांव से लापता हुई थी, लेकिन वह फिर गांव वापस नहीं लौटी.

रमा के अनुसार, वह एक घर में बच्चों की देखरेख तथा अन्य घरेलू काम किया करती थी. कमलावती हर माह रमा की मज़दूरी का पैसा उसके घर भेजने के नाम पर ले लिया करती थी. लेकिन यह पैसा कभी उसके घर नहीं पहुंचा. उमा के संबंध में जब महीनों कोई ख़बर न मिली, तब मजबूरन उसके और रमा के पिता ने दिल्ली जाकर उससे मिलने की कोशिश की. लेकिन कमलावती ने इन्हें केवल रमा से मिलवाया और उनसे कहा कि उमा बहुत दूर काम करती है, उससे मिलने में दिक्कत होगी. रमा एक बार वापस आने के बाद अब दिल्ली जाना नहीं चाहती. रमा दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहती, इसके जवाब में उसकी एक गहरी चुप्पी ही सबकुछ बयां कर देती है. छिन्दवाड़ा के कुंवर सिंह पुसाम की 17 वर्षीय पुत्री भी 2004 से लापता है. मंडला में काम कर रही स्वैच्छिक संस्था, निर्माण द्वारा किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि मंडला ज़िले में पिछले पांच सालों में 600 से अधिक अवयस्क बालिकाएं ग़ायब हो चुकी हैं. वर्ष 2006-07 में मंडला ज़िला पुलिस ने 125 किशोरियों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराया है.

बताते हैं कि इन किशोरियों को देह व्यापार के लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में भेजा जाता है. छिन्दवाड़ा ज़िले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी का भी मानना है कि ग़रीबी और रोज़गार जैसे अवसरों के अभाव के कारण इस इलाक़े में बच्चों और महिलाओं का अनैतिक व्यापार चल रहा है. सीधी ज़िले के कुसमी जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों से तीन वर्षों में एक दर्ज़न आदिवासी किशोरियां और युवतियां ग़ायब हो चुकी हैं. ग्राम चगोहर की चार, ग्राम ठाड़ीपथ की दो, ग्राम हर्रई की दो, ग्राम कुसमी से एक, चमारी टोल से दो और ग्राम जुरी से एक किशोरी ग़ायब हुई है. इनमें से कुछ मामले तो कुसमी पुलिस थाने में दर्ज़ हैं और कुछ मामले तो अबतक दर्ज़ भी नहीं किए गए हैं, ज़ाहिर है, ग़ायब हुई इन किशोरियों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है. मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों और कुछ सामाजिक जातियों में लिंगानुपात बुरी तरह गड़बड़ा गया है. यही वजह है कि विवाह योग्य पुरूषों के लिए स्त्रियों की कमी खलने लगी है.

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र तथा चंबल क्षेत्र में विवाह के लिए महिलाओं की ख़रीद-बिक्री का कारोबार इतने सुनियोजित तरीक़े से किया जाता है कि प्रशासन इस पर अब तक कोई रोक लगाने में नाकाम साबित हुआ है. कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बुंदेलखंड में चार महिलाओं की ख़रीद-बिक्री का मामला उठाया, लेकिन सरकार ने वयस्क स्त्री-पुरूष के विवाह को एक धार्मिक-सामाजिक संस्कार बताते हुए, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. मामले पर सफ़ाई दी गई कि विवाह के लिए ख़रीद-बिक्री का कोई प्रमाण नहीं मिला है. झांसी में तो एक मज़िस्ट्रेट के सामने ही विवाह क़रारनामा संपन्न हो गया और जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तो प्रशासन की ओर से यही जवाब आया कि इसमें तो कुछ भी ग़लत नहीं है.

मंडला ज़िले के बिछिया विकासखंड के इंद्रावन गांव के निवासी आनंद राम की बेटी रूपवती (परिवर्तित नाम) सोनाली नाम की एक युवती के साथ दिल्ली गई थी. आनंदराम ने पहले तो सोनाली से अपनी बेटी को दिल्ली ले जाने के नाम पर साफ़ मना कर दिया था, लेकिन अकेले में जब उसने रूपवती को दिल्ली की शानदार ज़िंदगी के सुनहरे सपने दिखाए तो वह अपने परिवार वालों को बिना बताए सोनाली के साथ घर से भागने तक को तैयार हो गई. दिल्ली तक पहुंचने के लिए रूपवती को पैसों की ज़रूरत पड़ती लिहाज़ा उसने किराए के लिए अपनी चांदी की पायल भी बेच दी. पिता आनंद राम को सोनाली ने ख़बर भी दी कि उनकी बेटी रूपवती दिल्ली में काम कर रही है और अच्छा पैसा कमाकर जल्द ही घर लौटेगी. इतना ही नहीं, टेलीफ़ोन पर रूपवती और उसके पिता के बीच बातचीत भी हुई.

तीन साल बाद रूपवती दिल्ली से वापस तो आई पर झुलुक गांव में अपनी बहन और बहनोई के पास रहने लगी. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को रूपवती ने बताया कि उसे पहले मोतीनगर फिर इंद्रपुरी और उसके बाद राजौरी गार्डन इलाक़े में रखा गया था. उसे एक ऑफ़िस में 10 दिन तक रखा गया जहां नीचे की मंज़िल में कुछ लड़कियां रहती थीं और ऊपर की मंज़िल में कुछ लड़कों को रखा गया था. उसने बताया कि आफ़िस के मालिक की नीयत लड़कियों के मामले में कुछ ठीक नहीं थी. वह एक-एक लड़की को अपने कमरे में काम के बहाने बुलवाता रहता था. उसने कहा कि उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी कुछ लड़कियां उस मालिक के चंगुल में थीं. उस ऑफ़िस में घरेलू कामगार युवतियों की सप्लाई करने का काम भी होता था. करोलबाग़, फ़रीदाबाद और गुड़गांव के बंगलों और बड़े-बड़े फ्लैट्स में लड़कियों को घरेलू कामकाज़ के लिए भेजा जाता था.

मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसूचित जनजाति थाना प्रकोष्ठ के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध रूप से महिलाओं को, विशेषकर अवयस्क बालिकाओं को, रोज़गार दिलाने के नाम पर घर से दूर तथा दूसरे राज्यों में ले जाने और वहां उनका सेक्स और श्रम के लिए शोषण करने की घटनाएं गंभीर हैं. राज्य के कुछ आदिवासी बहुल ज़िलों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है. पुलिस तो इस मामले में सजग है और जब कभी कोई शिक़ायत होती है तो इससे तत्परता से निपटा भी जाता है. लेकिन यह एक बड़ी समस्या है और इसके लिए जन-जागृति और जनसहयोग भी ज़रूरी है.

feedback@chauthiduniya.com

बाल व्यापार और मज़दूरी के शिकार किशोर.

सतना ज़िले के बरोघा थाना पुलिस को तड़के ख़बर मिली कि चार इनामी डकैत उसके क्षेत्र में देखे गए हैं. बस यहीं से ऑपरेशन शुरू हुआ.

सार-संक्षेप

प्रारंभिक शिक्षा की केंद्रीय योजना कहां गई ?

केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार और उसे रोचक बनाने के प्रयास में अरबों रुपए ख़र्च करने के बाद भी राज्य में सैटेलाईट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा (एडूसेट) की योजना पूरी तरह नाकाम हो गई है. इस योजना को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीधी ज़िले में, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रारंभ किया था. मोनिटरिंग के अभाव में और तक़नीकी ख़राबियों के चलते सीधी और सिंगरौली ज़िले में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में भी यह योजना दम तोड़ चुकी है. इस योजना को इसरो, इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया था. इस योजना के तहत दो लाख रुपए का सामान शिक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया गया था. केवल सिंगरौली के बेढ़न क्षेत्र में ही 65 विद्यालयों में सवा करोड़ रुपए ख़र्च किये गए थे, परंतु अब इस योजना का अस्तित्व इस क्षेत्र में कही नहीं है.

इमारती लकड़ी का दुरुपयोग ज़ारी

वनों में रहने वाले आदिवासियों का बहुत गहरा संबंध वनों के साथ है. सरकारी तंत्र लगातार आरोप लगाता है कि आदिवासी वन काट रहे हैं, जबकि मंडला ज़िले में ही यह तथ्य ग़लत साबित होता है. मंडला से 40 किलोमीटर दूर ग्राम बबलिया में जंगलों की लकड़ी एक ट्रैक्टर में खुलेआम ले जाई जा रही थी . ड्राईवर राजेंद्र से पूछने पर उसने सरपंच का माल बताया और पुरानी तारीख़ की एक रसीद भी दिखा दी. रसीद भी ऐसी, जिसपर न हस्ताक्षर थे और न ही सील. बाद में पता चला कि इसी गांव के ईट-भट्टे के ठेकेदार भूरा यादव, ईटों का भट्टा वनों की लकड़ी के माध्यम से ही चलाते हैं. जंगल विभाग के डिप्टी रेंजर एमडी अवस्थी ने इस अवैध कार्यवाही से मुंह मोड़ते हुए यह बयान दे दिया कि भट्टे में लकड़ियां है ही कहां, इसमें तो कोयला जल रहा है. डीएफओ श्री कोरी के मुताबिक़ इस पूरे मामले की जांच की जाएगी.

मंदाकिनी का अस्तित्व ख़तरे में

मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के वनवास के दौरान जिस नदी को राम, लक्ष्मण के स्नान का पुण्य प्राप्त था वह मंदाकिनी नदी प्रदूषण के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है. जल आंदोलन से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त राजेन्द्र सिंह कहते हैं कि लाचारी, बेकारी, बीमारी और विस्थापन का शिक़ार हमारी नदियां ही हुई हैं. वह कहते हैं कि इस क्षेत्र में कभी पुण्य सलिला कही जाने वाली मंदाकिनी का अस्तित्व आज संकट में है. गत वर्ष हुए अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव के एजेंडे से भी मंदाकिनी ग़ायब थी. यदि यही आलम रहा तो आने वाले समय में इस नदी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. मंदाकिनी का इतिहास धार्मिक एकता पर आधारित है. इस नदी के तट पर एक ओर रामघाट है तो ठीक दूसरी ओर रहीम घाट भी निर्मित है.राजेंद्र सिंह का कहना है कि मंदाकिनी को इस समय सर्वाधिक ज़रूरत एक जन आंदोलन की है, जो संभवत: इसके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है.

यात्री कुलियों से परेशान हैं

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों कुलियों की मनमानी चल रही है. जबलपुर रेलवे स्टेशन में कुल 79 कुली रजिस्टर हैं जिन्हें 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम दिया जाता है. नियमों के विपरीत काम के दौरान इनके बीच ही आपसी तकरार का माहौल कई बार बन जाता है. कुलियों की समस्याओं से निपटने में स्थानीय रेलवे पुलिस भी कोई रूचि नहीं लेती है. शहर में आने वाले यात्रियों से ये कुली निर्धारित पारिश्रमिक से 25 से 30 प्रतिशत अधिक राशि वसूल करते हैं. एक कुली की मासिक आय इस स्टेशन पर 6 हज़ार रुपए के आसपास है. इन कुलियों को सालभर में आने जाने का पास, रेलवे अस्पताल में मुफ़्त इलाज और नए बज़ट में स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान की गई हैं. कुलियों को प्रशासन से शिक़ायत है कि गैंगमैनों की भर्ती में वरिष्ठता को नज़र अंदाज़ किया जाता है. पुराने कुलियों को उपेक्षित कर नए कुलियों की भर्ती की जाती है. इलाज के दौरान महंगी दवाईयां भी स्वयं ख़रीदनी पड़ती हैं. ड्रेस के रूप मे दो मीटर से भी कम कपड़ा मिलता है. कुली विश्रामालय की हालत भी जर्ज़र है. इन शिक़ायतों के बावज़ूद कुलियों से यात्रियों को होने वाली परेशानियों का हल किसी के पास नहीं है.

वनग्रामों में मांझी सेना

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित आदिवासियों एवं वनवासियों के गांवों में अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मांझी सेना नामक संगठन अपना नेटवर्क फैला रहा है. मांझी सेना के बढ़ते प्रभाव को कुछ लोग नक्सली गतिविधियों से भी जोड़कर देखते हैं. मध्य प्रदेश की लगभग एक तिहाई आबादी वन क्षेत्रों में रहती है. इनमें गोंड एवं भील जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज भी इन जनजातियों में साक्षरता और शिक्षा की कमी है. इसी कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति अंजान हैं. मांझी सेना ने लगभग एक सौ से ज़्यादा स्वयंसेवक तैयार कर उन्हें वनवासियों एवं आदिवासियों के बीच भेजना शुरू किया है. उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत होने और ज़रूरत पड़ने पर संघर्ष करने की सीख दी जा रही है. अकेले होशंगाबाद ज़िले में 15 से ज़्यादा गांवों में मांझी सेना के सदस्य बन चुके हैं और वे जब-तब जुलूस आदि का आयोजन कर अपनी ताक़त का प्रदर्शन भी करते हैं. हाल में होशंगाबाद के कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मांझी सेना ने वन भूमि पर क़ाबिज़ वनवासियों को भू-अधिकार देने और वन मान्यता क़ानून पूरी तरह लागू करने की मांग की है. वनग्रामों में मांझी सेना के तेज़ी से फैल रहे नेटवर्क को कहीं वनवासियों के हित में बताया जा रहा है तो कहीं नक्सली गतिविधि के संकेत. वैसे इस सेना का प्रमुख उद्देश्य अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखकर उनका समाधान कराना है. सेना के जवान हर माह अलग-अलग वनग्राम में बैठक कर समस्याओं की जानकारी लेते हैं. सभी जवान बैठक में बाक़ायदा वर्दी पहन कर उपस्थित होते हैं. जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की मांझी सेना का मुख्यालय दिल्ली में है. अकेले होशंगाबाद ज़िले में सेना के लगभग 15 पदाधिकारी और तीस हज़ार जवान हैं. सभी जवानों को बेल्ट, टोपी एवं गणवेश दिल्ली मुख्यालय से दिए गए हैं.

मल्कीत के पांच लक्ष्य

ज़िला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्कीत सिंह ने पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए पांच लक्ष्य निर्धारित किए हैं. पांच सालों में युवा मल्कीत सिंह बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम करेंगे. आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और ज़िले के आधारभूत ढांचे में सुधार की संभावनाओं की खोज करना मल्कीत सिंह एवं उपाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह यादव का प्रमुख लक्ष्य है. देखना है, युवाओं के हाथों में सौंपी गई कमान ज़िले को पांच वर्षों में कहां से कहां तक ले जाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गांजे की अवैध खेती और तस्करी बढ़ी

किसी ज़माने में मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का मंदसौर और रतलाम ज़िला अफीम की अवैध खेती और तस्करी के लिए बदनाम था. इस दौरान सरकार ने कई सख्त क़ानून लगाते हुए अफीम और गांजे की खेती पर बैन लगाया. पर कहते हैं ना कि जब भी कोई नया क़ानून बनता है, उसके पालन से पहले उसका तोड़ पहले खोज लिया जाता है. इसी का परिणाम है कि अब राज्य के कई ज़िलों में गांजे की अवैध खेती हो रही है. बड़े पैमाने पर गांजा राज्य से बाहर तस्करी के लिए भेजा जा रहा है. प्रशासन कभी कभार ही सक्रिय होकर गांजे की खेती और तस्करी के मामले में गिरफ़्तारी करता है.

राज्य के वन प्रधान ज़िलों में जंगलों के बीच खाली पड़ी ज़मीन पर गांजे की अवैध खेती धड़ल्ले से की जाती है और जब फ़सल पक जाती है तो उसे तस्करी के लिए बाहर भेज दिया जाता है. खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, सिवनी, बालाघाट ज़िलों में पुलिस आबकारी और वन विभाग के कर्मचारियों ने ऐसे कई मामले पकड़े हैं. पिछले दिनों सतना ज़िले के लालपुर गांव में लगभग 45 लाख रुपये का अवैध गांजा पकड़ा गया. यह गांजा आबकारी विभाग के एक क्लर्क की मदद से ले जाया जा रहा था. लेकिन पुलिस की सक्रियता से उसे मौक़े पर ही पकड़ लिया. पुलिस को गांजे की तस्करी की सूचना अपने मुख़बिरों से मिली थी.

हाल ही में शिवपुरी ज़िले के खनिमांधना विकास खण्ड में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती का एक और मामला पकड़ा था और इसमें एक किसान दंपत्ति सूरजसिंह और उसकी पत्नी रामकली को गिरफ़्तार किया था. ज़िला पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सूरज सिंह और उसकी पत्नी खेत में साग सब्ज़ियों के बीच अवैध रूप से गांजे की फ़सल उगाते थे. पुलिस ने उनके दो खेतों से 21 किलो गांजे के पौधे और घर से सवा किलो सूखा गांजा बरामद किया है.

जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बड़े शहरों में गांजा भेजा जाता है जहां गांजे से हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं. जिनकी भारत के बड़े शहरों और विदेशों में बड़ी मांग है. गांजे की अवैध खेती से लेकर तस्करी तक का कारोबार करोड़ों रूपयों का है.

पिछले दिनों भोपाल के उपनगर मिसरोद में आबकारी विभाग का अर्जुन मीणा, तीन अन्य व्यक्तियों के साथ 20 किलोग्राम गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ़्त में आया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि आबकारी हवलदार अर्जुन मीणा की इन तस्करों से मिली-भगत रही है और वह शिवकुमार उर्फ़ मुन्ना नाम के तस्कर से इस सिलसिले में मिलने आया था. इन गिरफ़्तारियों से पता चलता है कि गांजे की तस्करी और अवैध खेती का धंधा ज़ोरों पर है और इसे रोकने के लिए पुलिस को अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कुछ और इनामी डकैतों से छुटकारा मिला

पुष्पेंद मौर्य

तराई क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे ददुआ और ठोकिया गिरोह की तरह ही छोटे-छोटे गिरोह द्वारा प्रदेश में आतंक फैलाने की होड़ मची हुई है. लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस कई ऑपरेशन के जरिए काफ़ी हद तक इनका ख़ात्मा करने में कामयाब रही है. इसी कड़ी में सतना पुलिस ने कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद चार इनामी डकैतों को ढेर करने में सफलता हासिल की है. सतना पुलिस की सक्रियता ने एक डकैत गिरोह को प्रभावशील होने से पहले ही ख़त्म कर दिया. विंध्य क्षेत्र में डकैतों का आतंक बार-बार सर उठा रहा है जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की सीमाओं का उत्तर प्रदेश से संलग्न होना है. सतना ज़िले के बरोघा थाना पुलिस को तड़के ख़बर मिली कि चार इनामी डकैत उसके क्षेत्र में देखे गए हैं. सूचना में पुलिस को बताया गया था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरहद पर आतंक फैलाने वाले नवागत राजाख़ान गिरोह के डकैत क्षेत्र में घूम रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसने कार्रवाई शुरू की. डकैतों से पुलिस की मुठभेड़ महतैन क्षेत्र में एक जंगल में नाले के किनारे हुई. कई घंटों की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चारों डकैतों को ढेर कर दिया. लेकिन जब डकैतों की शिनाख्त की गई तो पुलिस को पता चला कि मरने वाले डकैत, सुरेश गौड़ और उसके साथी थे. पुलिस को इन सभी के पास से बंदूकें और अन्य असलहा भी हाथ लगे.

ऑपरेशन को अंजाम देने वाला पुलिस दल.

मुठभेड़ में ढेर डकैत.

कई बड़े गिरोह के सरदारों से गुण सीखने वाला सुरेश गौड़ उर्फ़ बिज्जू मामा डकैत बनने के बाद राजाख़ान गैंग के साथ काम करता था. आपसी मतभेद के चलते सुरेश ने इस गिरोह से निकलकर अपना ख़ुद का गिरोह बना लिया था. सुरेश के साथ मारे गए मनोज यादव, रामदयाल और ओमप्रकाश यादव पर भी पुलिस द्वारा इनाम घोषित था. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख़बिर लगातार तीन दिनों से इन डकैतों के बारे में सूचना दे रहा था. धारकुण्डी थाने के कजरा गांव का रहने वाला सुरेश गौड़ ठोकिया गैंग में भी शामिल रहा है. अपना अलग गिरोह बनाने के बाद वह इस क्षेत्र में अपनी सल्तनत क़ायम करना चाहता था. मिली जानकारी के अनुसार राजाख़ान ने जब सती अनसुईया आश्रम में साधु संतों को गाली दी और फिर फायरिंग भी की तो इससे नाराज़ होकर सुरेश गौड़ ने अपना अलग गिरोह बना लिया.

इसके पहले कि सुरेश गौड़ क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन पाता, सतना पुलिस की टीम ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी. पुलिस की इस टीम में थाना प्रभारी बरोधा, उदयभानसिंह थाना प्रभारी मंझगवां फुलसिंह गुर्जर, एएसआई रामबाबू यादव, एसडीओपी चित्रकूट बीपीएस तोमर एवं विजय सिंह सहित कई जवान शामिल थे. सतना पुलिस के अधीक्षक ने इस सफलता के लिए पुलिस जवानों को शाबाशी दी है. साथ ही इन कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक देने के लिए अनुशंसा भी की है. पुलिस के अनुसार वर्तमान में विंध्यक्षेत्र में कुछ छोटे गिरोह अब भी सक्रिय हैं, जिनकी सघनता के साथ तलाश की जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के दो दर्ज़न से अधिक आईएएस और आईपीएस भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में हैं.

भूख ने एक और आदिवासी परिवार लीला

असगर कुरैशी

केंद्र एवं राज्य सरकार इस बात का दावा करती रही है कि देश में भूख और तंगहाली के कारण कोई मौत नहीं होती. लेकिन मंडला ज़िले के राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा जनजाति के एक दंपत्ति ने पांच बच्चों के भरण पोषण और भूख से तंग आकर, अपने आप को आग के हवाले कर दिया. मौक़े के गवाह रहे लोगों का कहना है कि दंपत्ति ने भूख से तंग आकर अपनी जान दी. सरकार के अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही हादसे की सच्चाई का पता चलेगा. बैगा जाति के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक अरबों रुपये ख़र्च किए हैं. पर इस हादसे के बाद सवाल उठता है कि तमाम ख़र्चों के बाद भी बैगा जाति का ऐसा हाल क्यों है?

पिछले दिनों मंडला ज़िले की निवास तहसील के पिपरिया गांव में अचानक एक बैगा परिवार के पांच मासूम बच्चे अनाथ हो गए. इस गांव में रहने वाले सरमन बैगा और उसकी पत्नी सुंदरिया बैगा ने ख़ुद को आग में झोंक दिया. इस हादसे में दोनों ही आदिवासियों की मौत हो गई. और इसके साथ ही राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा समुदाय को व्यापक संरक्षण देने की सरकारी नीति भी संदेह के दायरे में आ गई है. सरमन बैगा का परिवार पिपरिया गांव में अपनी पांच मासूम बेटियों के साथ रहता था. बेटियों की उम्र 11 वर्ष से 6 माह तक की है. सरमन अपनी 8 साल की बेटी पूजा बैगा की बीमारी से लगातार परेशान चल रहा था और उसका इलाज सरकारी अस्पताल में भी करवा रहा था.

बड़े लाल (मृतक के पिता)

हीरालाल

सोनबाई

रामप्यारे कुलस्ते

एन एस खंडाते

सरमन जो भी कमाता था वह बच्चों के दूध में ही ख़र्च हो जाता था. गांव में काम की कमी और रोज़गार के संसाधनों की कमी ने सरमन को निराश कर रखा था. राष्ट्रीय मानव कही जाने वाली बैगा जनजाति के इस युवक को प्रशासन से भी किसी तरह की मदद नहीं मिली. नतीजतन, मानसिक रूप से परेशान सरमन ने तंगहाली और भूख से बेहाल होकर अकाल मृत्यु का हाथ थाम लिया.

मंडला ज़िले में कार्यरत बैगा विकास प्राधिकरण प्रतिवर्ष नए-नए आंकड़ों के माध्यम से यह प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि बैगाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के शासकीय संकल्प शत प्रतिशत पूरे होते हैं, जबकि स्थितियां ठीक इसके विपरीत हैं. पिछले कुछ सालों में रामनगर क्षेत्र के गांव गल्लूखोह में बैगाओं की लगातार एक के बाद एक अज्ञात बीमारी से हुई मौत, सरकारी प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लगा चुकी है. यह ख़बरें राष्ट्रीय अख़बारों मे सुर्ख़ियों में रहीं पर जांच में कुछ भी पता नहीं चला.

सरमन बैगा की मौत पर मृतक के पड़ोसी हीरालाल बैगा कहते हैं कि सरमन अपनी तीसरी बेटी पूजा की एक साल पुरानी बीमारी से परेशान था. पूजा को ख़ून की उल्टियां होती थी. सरमन के पिता का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और बेटी की बीमारी ने सरमन को तोड़ दिया था. वहीं सरमन की सास का कहना है कि घर में दो वक़्त खाने के लिए अनाज नहीं था और सरमन ख़ुद ही बेटी के इलाज के लिए दर-दर भटकता था.

थाना निवास के ए.एस.आई. पुलिस एन.एस. खंडाते जो इस घटना के जांच अधिकारी भी हैं, बताते हैं कि बेटी का इलाज न करा पाना और ख़राब आर्थिक स्थिति ही सरमन की मौत का कारण बनी. घटना के विषय में स्थानीय विधायक रामप्यारे कुलस्ते का कहना है कि हमेशा की तरह सरकार इस परिवार की मदद ज़रूर करेगी. मेरी जानकारी के अनुसार सरमन शराबी था और नशे में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया है. ज़िले के कलेक्टर के.के. खरे के अनुसार दीन दयाल अंत्योदय कार्ड होने के बावजूद सरमन ने उसका लाभ नहीं लिया. कलेक्टर के अनुसार सरमन की बेटियों को कन्या आश्रम में रखकर हर संभव मदद की कोशिश की जायेगी.

राजनीतिक ज़िला प्रशासन के अधिकारी और घटना से जुड़े अन्य लोग अलग-अलग तरह के बयान देकर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन यह सोच का विषय है कि जिस मंडला शहर में आदिवासियों के नाम पर आने वाली करोड़ों रुपयों की राशि का लगातार घोटाला होता है, वहां सरमन जैसे आदिवासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई स्थानी तंत्र कभी मानवीय आधार पर भी कार्य करने में सक्षम हो सकेगा क्या?

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी भ्रष्टजनों का खाता उजागर

भ्रष्टाचार के लिए बदनाम मध्य प्रदेश के शासन-प्रशासन में अब तक भ्रष्ट तत्वों के सम्मान की रक्षा के लिए उनके नाम उजागर नहीं किए जाते थे. यहां तक कि मुख्यमंत्री भी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अक्सर जानकारी एकत्र की जा रही है जैसी टालू सूचना देकर भ्रष्ट तत्वों के चेहरे बेनक़ाब नहीं होने देते थे. लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में नियमानुसार पेश करना अनिवार्य है, लेकिन इस रिपोर्ट पर पिछले कई वर्षों से सदन में बहस भी नहीं कराई जाती. हाल में विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों ने लोकायुक्त में दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी चाही, लेकिन प्रशासन ने मुख्यमंत्री के माध्यम से यही सूचना सदन को दी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है. बाद में मुख्यमंत्री ने प्रश्नोत्तर से अलग विधानसभा में पूरी जानकारी विस्तार से प्रस्तुत की. उन्होंने स्वीकार किया कि शासन के कई वर्तमान एवं पूर्व मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के अलावा कई विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ लोकायुक्त में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण दर्ज़ हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान.

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के दो दर्ज़न से अधिक आईएएस और आईपीएस भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में हैं. विधायक उमंग सिंघार के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया कि जनवरी 2004 से लेकर 31 जनवरी 2010 तक की अवधि में लोकायुक्त ने 2675 प्रकरण दर्ज़ किए. इनमें से 1149 प्रकरणों में जांच कर ख़ात्मा लगाया गया. जवाब में यह तो बताया गया है कि प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाते हैं, लेकिन यह स्वीकारोक्ति चौंकाने वाली है कि बकाया में मात्र 243 प्रकरणों में ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. वहीं 296 शिक़ायती आवेदन लंबित हैं, जो परीक्षण में हैं.

जिनके ख़िलाफ़ लोकायुक्त में मामले दर्ज़ हैं

मंत्री : लक्ष्मीकांत शर्मा, अनूप मिश्रा, अजय विश्नोई एवं राजेंद्र शुक्ल.

पूर्व मंत्री : हिम्मत कोठारी, ढाल सिंह बिसेन, अखंड प्रताप सिंह एवं कमल पटेल.

आईएएस, आईपीएस एवं प्रकरण दर्ज़ करते समय पदस्थापना :

पुखराज मारू-प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, देवराज विरदी-प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण, अरविंद जोशी-प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग, पी डी मीणा-प्रमुख सचिव लोनिवि, सत्य प्रकाश-प्रमुख सचिव उद्योग विभाग, विश्वपति त्रिवेदी-आयुक्त वाणिज्य कर इंदौर, एम एन ख़ान-सचिव नगरीय प्रशासन, के सी जैन-सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण, एस आर मोहंती-सचिव महिला एवं बाल विकास, एम ए ख़ान-तत्कालीन प्रबंध संचालक बीज निगम, राघव चंद्रा-प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, आर सी साहनी- प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, पुलिस अधीक्षक-ज़िला भोपाल, विवेक अग्रवाल-कलेक्टर ज़िला इंदौर, प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य विभाग भोपाल, प्रबंध संचालक-लघु उद्योग निगम भोपाल, एस के मिश्रा-खनिज साधन, श्रीमती अलका उपाध्याय-आयुक्त स्वास्थ्य, महेंद्र ज्ञानी-उप सचिव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनीष श्रीवास्तव-कलेक्टर ज़िला शिवपुरी, राकेश साहनी-मुख्य सचिव मप्र., एस के मिश्र-तत्कालीन कलेक्टर रीवा, संजय शुक्ल-सीएमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपी, सरीना सिंह-आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, गाजीराम मीणा-पुलिस महानिरीक्षक इंदौर, मो. सुलेमान-सचिव लोनिवि.

अन्य : संयुक्त संचालक

कोष एवं लेखा पेंशन भोपाल, अध्यक्ष-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, आयुक्त- नगर पालिका निगम सागर, डॉ. एच सी जैन-मप्र गौसेवा आयोग पशु चिकित्सालय भोपाल, ए के ठाकुर-मुख्य अभियंता पीएचई भोपाल, एम एल गोयल-मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग भोपाल, पी एन सिंह-प्रबंध संचालक राज्य सहकारी मर्यादित भोपाल, प्रमुख अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल, एन एम पुरुषवानी-अधीक्षण यंत्री लोनिवि ग्वालियर, एस एन गुप्ता-अधीक्षण यंत्री पीएचई भोपाल, आयुक्त एवं कार्यपालन यंत्री नगर निगम जबलपुर, एस सी गर्ग-मुख्य अभियंता लोनिवि इंदौर, संजय तिवारी, संजीव दुबे, जिला आबकारी अधिकारी, रामजीत सिंह-सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, क्रमश: जबलपुर, विदिशा एवं रतलाम. नरसिंह तोमर-ज़िला पंजीयक कार्यालय इंदौर, विनोद शर्मा-आयुक्त नगर निगम इंदौर, बी के श्रीवास्तव- अधीक्षण यंत्री पीएचई विभाग, योगीराज शर्मा-चाइल्ड हेल्थ सलाहकार स्वास्थ्य विभाग, संदीप जायसवाल- महापौर नगर निगम कटनी, डॉ. अशोक शर्मा-संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल, जी एस कलसी-अधीक्षण यंत्री लोनिवि सेतु मंडल भोपाल, सी वी सिंह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर, संजय गोयल- सीईओ ज़िला पंचायत खंडवा, पवन शर्मा- तत्कालीन आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, ओ पी मुछाल- प्रभारी मुख्य अभियंता लोनिवि इंदौर, एस एल गुप्ता-मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर, एस के पंचनंदा-अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर, मधुकर वर्मा-अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, प्रमोद गुप्ता-मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण, महापौर-आयुक्त नगरपालिका इंदौर, वीर सिंह हिंडो-महापौर खंडवा, के पी जाटव-मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म निगम, डॉ. योगीराज शर्मा-संचालक स्वास्थ्य, प्रताप सिंह चंपावत-वन मंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी, अनिता बाथम-लेखा अधिकारी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आर एल भारतीय-अधीक्षण यंत्री प्रभारी मुख्य अभियंता लोनिवि ग्वालियर, एस के महावर-नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर, एस के मंडल-अपर सचिव गर्ग-मुख्य अभियंता लोनिवि, बोरासी-कार्यपालन यंत्री ब्रिज डिवीजन इंदौर, मुदगल-अधीक्षण यंत्री इंदौर, मुख्य अभियंता गंगा प्रसाद एवं अधीक्षण यंत्री बाणसागर नहर मंडल रीवा, डॉ. अंजू सिंह भदौरिया-नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, जे एस सलूजा-एसडीएम रतलाम, अशोक शर्मा- उप पंजीयक ग्वालियर, आयुक्त-नगर निगम भोपाल, मुख्य अभियंता लोनिवि संधारण क्रमांक एक भोपाल, वी के खरे-मुख्य अभियंता बाणसागर परियोजना रीवा, एल के जैन-तत्कालीन मुख्य अभियंता लोनिवि देवास, टी एन मलिक-अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मंडल क्रमांक सात खरगौन, डॉ. बी एल यादव-महापौर सतना, आर बी चतुर्वेदी-आयुक्त नगर निगम सतना, वी के सोनगिरा- मुख्य अभियंता देवास, ए पी राणे-कार्यपालन यंत्री लोनिवि देवास, राजेश गुप्ता-तत्कालीन सीईओ ज़िला पंचायत खंडवा, आर बी चतुर्वेदी-आयुक्त नगर निगम सतना, राम विश्वास तिवारी, सत्य नारायण त्रिपाठी एवं रमेश त्रिपाठी-नगर निगम सतना, मित्तल-अधीक्षण यंत्री एवं वी के मिश्रा-कार्यपालन यंत्री और नवीन उपाध्याय- मप्र राज्य विद्युत मंडल रीवा, आर के सक्सेना-मुख्य अभियंता अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई, भीमा मंड्लोई-वन परिक्षेत्राधिकारी, वी पी कपिल-वन मंडलाधिकारी रायसेन, एम एम सकुनिया-परियोजना अधीक्षण यंत्री लोनिवि अलीराजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-ज़िला पंचायत उमरिया, डी एस मुदगल-राज्य विद्युत मंडल बिरसिंहपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-ज़िला पंचायत बैतूल, अधीक्षण यंत्री एवं वीके शुक्ला-सहायक यंत्री, जे एस कलसी-मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी श्योपुर, ए के-अधीक्षण यंत्री एवं अन्य-नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बड़वानी एस एन प्रसाद-मुख्य अभियंता एवं अन्य-लोनिवि खंडवा, डी के त्रिपाठी-मुख्य अभियंता एवं अन्य-जल संसाधन विभाग छतरपुर, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव-प्रभारी अभियंता नगर पालिका अधिकारी उज्जैन, भगवान सिंह पवार-प्रभारी लेखपाल महिदपुर, दिनेश कौशल-प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी, शैलेंद्र शुक्ला-प्रमुख अभियंता लोनिवि भोपाल, के सी जैन-अधीक्षण यंत्री-लोनिवि इंदौर, आर के अग्रवाल-तत्कालीन अधीक्षण यंत्री एवं अन्य-पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी छिंदवाड़ा, एस जे एस तुलसी-तत्कालीन अधीक्षण यंत्री लोनिवि सिवनी.

> लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में नियमानुसार पेश करना अनिवार्य है, लेकिन इस रिपोर्ट पर पिछले कई वर्षों से सदन में बहस भी नहीं कराई जाती. हाल में विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों ने लोकायुक्त में दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी चाही, लेकिन प्रशासन ने मुख्यमंत्री के माध्यम से यही सूचना सदन को दी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जस्टिस प्रकाश प्रभाकर

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सार –संक्षेप

कृषक राहत योजना पर किसानों का भरोसा नहीं

मध्य प्रदेश सरकार ने दो साल पहले जिस कृषक राहत योजना को शुरू किया था, उस पर किसानों को भरोसा नहीं है और इसी कारण लगभग तीन लाख़ ग्यारह हज़ार किसानों ने इस योजना को अपनाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2008 में भोपाल में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन कर बिजली बिल में राहत देने के लिए एक योजना शुरू करने की घोषणा की थी. लेकिन सरकार ने यह शर्त भी रखी थी कि बकाया वसूली के लिए जितना ऊर्जा प्रभार होगा, उसका 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा. इसके अलावा 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर सरचार्ज की पूरी राशि ही माफ़ करने की बात भी कही गई थी. कृषकों पर 31 जनवरी 2008 तक 1044 करोड़ रुपए ऊर्जा प्रभार की राशि शेष थी, जिसमे 50 प्रतिशत माफ़ होने के बाद 521.82 करोड़ रुपया जमा होना था, और 242 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि को भी माफ़ किया जाना था. लेकिन अबतक मात्र 535616 किसानों ने ही योजना के तहत राशि जमा कराई है.

शिशुओं और माताओं की स्वास्थ्य रक्षा में कंजूसी

भारत में सबसे ज़्यादा बाल-मृत्युदर मध्य प्रदेश में है. इसके अलावा बच्चों में कुपोषण और गर्भवती तथा प्रसूता माताओं में ख़ून की कमी के कारण उनका स्वास्थ्य हमेशा कमज़ोर रहता है. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य बजट को ख़र्च करने में सबसे ज्यादा कंजूसी बच्चों और माताओं की ही स्वास्थ्य सेवाओं में ही कर रही है. राज्य सरकार के पास शिशु-मृत्युदर रोकने के लिए न तो कोई नीति है और न ही रणनीति. यही वज़ह है कि पिछले पांच सालों में सरकार इसके लिए आवंटित पूरी राशि, 65 करोड़ रुपए खर्च भी नहीं कर पाई है और इसमें से 26 करोड़ से अधिक राशि लैप्स हो गई. सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार जब तक जागती, प्रदेश में शिशु-मृत्युदर भारत में सबसे ज़्यादा हो चुकी थी. अब राष्ट्रीय ग्रामीण-स्वास्थ्य मिशन की रणनीति का अनुसरण कर रही सरकार शिशु-मृत्युदर को बढ़ने का ठीकरा गर्भवती महिलाओं और उसके परिवारों पर ही फोड़ने की कोशिश कर रही है. प्रदेश में एक हज़ार जन्में शिशुओं में सत्तर की मौत हो जाती है. यह आंकड़ा देश भर में सबसे ज़्यादा पहुंच चुका है. सरकार का दावा है कि शिशु-मृत्युदर अधिक होने के पीछे कम उम्र में मां बनना, गर्भवती महिलाओं में ख़ून की कमी होना, उचित देखभाल नहीं होना, संस्थागत प्रसव में कमी, बच्चों के कम वज़न का होना और उनका समुचित देखभाल नहीं होना आदि शामिल है. शिशु-मृत्यु दर रोकने के लिए आरसीएच कार्यक्रम के लिए पिछले पांच साल में 65 करोड़ 7 लाख रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन जनवरी 2009-10 तक सिर्फ़ 38 करोड़ 85 लाख 65 हज़ार रुपए ही ख़र्च किए जा सके. इसमें भी सबसे ज़्यादा राशि वर्ष 2008-09 और 2009-10 में ख़र्च की गई. इससे पहले करोड़ों रुपए में सिर्फ़ चंद लाख रुपए ही ख़र्च किए जा सके. वर्ष 2005-06 और 2006-07 में सबसे कम पैसे ख़र्च किए गए.

भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है सरकार

मध्य प्रदेश का प्रशासन, भ्रष्टाचार की बुराई के लिए बुरी तरह बदनाम हो गया है. मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी प्रशासन का शुद्धिकरण करने का इरादा रखते हैं, लेकिन सब कहने भर की बातें हैं. सच्चाई तो यह है कि आज भी मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को दबाने और संरक्षण देने में लगी हुई है. हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसआर आलम और अराधे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक अशोक शर्मा द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम के प्रभारी रहते हुए लगभग 12 करोड़ रुपयों का घपला करने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायालय ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का वक़्त दिया है. यह याचिका भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम की ओर से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि डॉ. अशोक शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान में 12 करोड़ रुपयों का घपला किया है. इस बारे में लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण में जांच भी शुरू हो चुकी है. लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है. इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इंदौर में मुख्य ज़िला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए डॉ. अशोक शर्मा ने कई गंभीर वित्तीय हेरा-फेरी की थी. न्यायालय के कामकाज के जानकार बताते हैं कि याचिका दायर होते ही न्यायालय की ओर से इसकी एक प्रति सरकार के महाधिवक्ता कार्यालय को भेज दी जाती है. इसके अलावा याचिकाकर्ता भी अनावेदक या प्रतिवादी पक्ष को याचिका की सूचना देता है. निश्चित ही मोहम्मद सलीम की याचिका राज्य सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव या मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय के निर्देश के पहले ही मिल गई होगी, लेकिन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में माहिर प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. फिलहाल अशोक शर्मा दूसरे मामलों में निलंबित हैं, लेकिन इस नये मामले में अभी राज्य सरकार को अपना जवाब उच्च न्यायालय में एक माह के भीतर देना होगा.

पौने छह सौ करोड़ रुपए पानी में बहाए

मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग कितना लापरवाह है इसका एक उदाहरण महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दिया है. विभाग की लापरवाही से जलदरों का निर्धारण नहीं हो सका. नतीज़तन विभाग को पौने छह सौ करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और सरकारी जलाशयों से पानी लेने वाले मुफ़्त में ही पानी का उपयोग करते रहे. रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग न कर पाने के चलते विभाग को 161 करोड़ रुपयों की राजस्व की क्षति हुई, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के किसान कई इलाकों में पानी के लिए तरसते रहे. इसके अलावा जल दरों के ग़लत निर्धारण से सवा 24 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ. रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंचाई और ग़ैर-सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल-आपूर्ति की दरों के निर्धारण और संग्रहण में भारी कमियां पाई गई और इसी वज़ह से सरकार को राजस्व क्षति हुई है.

आय 21 हज़ार और क़र्ज़ 9 हज़ार

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को भलीभांति मालूम है कि राज्य के नागरिकों की औसत आय 21648 रुपये वार्षिक है और सरकार ने प्रत्येक नागरिक को औसतन 9 हज़ार रुपये का क़र्ज़दार बना दिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले छह वर्षों में जिस तेज़ी से क़र्ज़ लिया है, वह सरकारी हिसाब-किताब देखने से साफ़ पता चलता है. मार्च 2004 की स्थिति में राज्य सरकार पर 34109 करोड़ रुपये का क़र्ज़ था, जो मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 54111 करोड़ रुपये हो गया है. अनुमान है कि मार्च 2010 तक यह क़र्ज़ बढ़कर 60000 करोड़ रुपये हो जाएगा. पिछले चार वर्षों में जिस तेज़ी से क़र्ज़ का बोझ बढ़ा है, उस अनुपात में राज्य की विकास दर में वृद्धि नहीं हुई है. क़र्ज़ में लिया गया पैसा ज़्यादातर अनुत्पादक मदों में ही ख़र्च हुआ है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकार को ज़िलों से जो हिसाब मिला है उसके अनुसार 2196 करोड़ रूपए मज़दूरी के रूप में बांटे गए, जिसमें से 835 करोड़ रूपए राष्ट्रीयकृत बैंकों या पोस्ट ऑफिस में श्रमिकों के अकांउट खाते खुलवाकर, उनके नाम जमा किए गए.

हीरे और अलेक्ज़ेन्ड्राइट की तस्करी जारी

शिवा कुमार

राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित हीरे की खदान में पिछले लंबे समय से अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से जारी है. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पास खनिज विभाग का ज़िम्मा भी है, इसके बावजूद सुरक्षा तंत्र इस अवैध खुदाई को रोक पाने में असक्षम है. उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र के खनिज माफ़िया, छत्तीसगढ़ से अवैध खनन कर हीरा निकालते हैं और बेरोक–टोक उसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंचाते हैं.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मशहूर पायलीखंड की हीरा खदान सिर्फ़ 150 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां इन दिनों उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के खनिज माफिया की गतिविधियां ज़ोरों पर हैं. सरकार की नाक के नीचे हो रही इन गतिविधियों को रोक पाने में खनिज विभाग का ज़िम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी असक्षम हैं. खनिज विभाग के केंद्रीय उड़नदस्ते और खनिज निरीक्षकों की संयुक्त जांच से यह ख़ुलासा हुआ है कि देवभोग के निकट सेंधमुड़ा से ही नहीं बल्कि पायलीखंड और बेहराडीह से भी फेंसिंग तोड़कर हीरे की तस्करी धड़ल्ले से जारी है. संयुक्त टीम ने अवैध खुदाई की सूचना पर जब यहां छापा मारा तो उसने बड़े–बड़े गड्ढों में लोगों को हीरा तराशते हुए पाया. तस्कर इस टीम को देखकर भाग चुके थे. संयुक्त टीम की वापसी के बाद तस्करों ने स्थानीय बीटगार्ड और चौकीदार को बुरी तरह पीटा. चौकीदार की रिपोर्ट पर मैनपुर पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज़ कर लिया है. बड़े पैमाने पर चल रही इस खुदाई का मुख्य मक़सद, बेशक़ीमती अलेक्जेन्ड्राइट पत्थर की तलाश को बताया जाता है, जिसका इस क्षेत्र में विशाल भंडार मौजूद है. मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 1991–92 में इसी पत्थर की सुरक्षा के लिए सात हज़ार वर्गफुट ज़मीन को कांक्रीट से ढका था. वर्तमान में इस सुरक्षा को भी तोड़ दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ और रूस में ही अलेक्जेन्ड्राइट पत्थर उपलब्ध हैं. बहुमूल्य होने के अलावा उपलब्धता कम होने के कारण भी इसकी क़ीमत करोड़ों में होती है. छत्तीसगढ़ के देवभोग और सेंधमुड़ा में इसी पत्थर की तलाश की जा रही है. देवभोग, मैनपुर, गरीयाबंद में दबे इस मूल्यवान पत्थर को बचाने के लिए राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है, हालांकि इस कार्रवाई की रूपरेखा का अभी तक कुछ पता नहीं है. लगभग 20 साल पहले 1989–90 में सेंधमुड़ा गांव के किसान को देवभोग से 7 किलोमीटर पहले हल चलाते समय एक रंगीन और चमकता हुआ पत्थर मिला था, जिसे उसके बच्चों ने खिलौना समझकर उठा लिया था. इसी क्षेत्र में कुछ ही दिनों में कई किसानों को इस तरह के पत्थर मिले. तब उड़ीसा के व्यापारी, किसानों से इन पत्थरों को 100 रू. में ही ख़रीद लिया करते थे. और तब से लेकर आज तक ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में ज़मीन के नीचे अलेक्ज़ेन्ड्राइट पत्थर बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं. हीरा खदान में अवैध खुदाई करने वाले लोगों के साथ पुलिस एवं वन अधिकारियों की कई बार मुठभेड़ हुई है. पड़ोसी राज्यों से आकर उत्खनन करने वाले लोगों को नियंत्रित करने में वर्तमान ज़िला प्रशासन पूरी तरह असक्षम है. नतीजतन, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खनिज संपदा अवैध रूप से बाहर ले जाई जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

विंध्य हर्बल

सफल सहकारी संस्था

अभय पटेल, संस्था प्रमुख

सरकारी प्रयासों से जनकल्याण के काम बिना रुकावट पूरे होते रहें, यह लगभग असंभव बात मानी जाती है. पर जब आप मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के द्वारा बनाई गई विंध्य हर्बल संस्था के कामकाज को देखेंगे तो मानेंगे कि जनकल्याण के लिए सरकारी प्रयासों की कमी नहीं है. विंध्य हर्बल संस्था प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित संग्रहण, उत्पादन, शोधन, दवा निर्माण एवं उसकी बिक्री का काम करती है. इन सभी कामों में इस संस्था को सफलता हाथ लगी है. मध्य प्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ ने इस संस्था की शुरूआत मध्य प्रदेश में लघु वनोपज के संरक्षण संग्रहण एवं उनकी बिक्री के कामों को संतुलित बनाए रखने के लिए किया था. इसके अलावा राज्य में चल रहे अरबों रुपयों के तेन्दूपत्ता व्यापार को व्यवस्थित रखने के लिए भी इस सहकारी संघ का निर्माण किया गया था. लघु वनोपज संघ ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए इसका ध्यान आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों की ओर बढ़ाना शुरू किया. राज्य की वन संपदा में जड़ी बूटियों का विशेष महत्व है. मध्य प्रदेश के दूर दराज़ इलाकों में कई तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं. मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ ने विंध्य हर्बल को अपने पंजीकृत ब्रांड के रूप में विकसित किया, जिसके बाद विंध्य हर्बल संस्था ने ग्रामीण एवं ज़िला स्तर पर गठित वन समितियों के माध्यम से आसपास रहने वाले आदिवासियों को जड़ी बूटियों के संग्रहण एवं व्यापार के लिए प्रेरित किया. इस नेक प्रयास से आज आदिवासी लोगों का जीवन यापन आसान हो चला है. भारतीय राष्ट्रीय वननीति 1998 में भी जंगलों पर निर्भर आदिवासी एवं ग्रामीणजनों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जड़ी बूटियों के उचित प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया गया है. मध्य प्रदेश औषधीय और सुगंधीय पौधों की खेती में एक अग्रणी राज्य है. पिछले कुछ सालों से यहां इन पौधों की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इन औषधीय पौधों से जुड़े किसानों एवं संग्रहकों को तकनीकी जानकारियां पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में वर्ष 2002–03 में मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय सहायता से लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एमएफपी–पार्क) स्थापित किया गया. इस केंद्र में किसानों और संग्रहकों को तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं. यह केंद्र औद्योगिक पौधों की मानक प्रयोगशाला भी है और इस केन्द्र में विंध्य हर्बल ब्रांड के औषधीय एवं खाद्य उत्पाद भी निर्मित किए जाते हैं. यहां प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, शहद प्रसंस्करण प्रभाग, हर्बल प्रसंस्करण प्रभाग, मानव संसाधन विकास प्रभाग एवं नर्सरी हैं. प्रयोगशाला के तीन उप–प्रभाग हैं जहां पादप रासायनिक विश्लेषण, माक्रोबॉयोलोजी, वनस्पति विज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं. इस पार्क में सभी उत्पादों की प्रकृति ऑर्गेनिक है. उन्नत प्रयोगशाला में उत्पादों का गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है. ग्राम स्तर की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कच्ची जड़ी बूटियों का संग्रहण कराया जाता है. जड़ी बूटियों के संग्रहक किसानों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है. यह संस्था प्राथमिक संग्रहकों को अपने लाभ में हिस्सेदार बनाती है. विंध्य हर्बल द्वारा वर्तमान में 233 आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण या शोधन किया जाता है, इसमें सभी तरह की दवाईयां शामिल हैं. संघ द्वारा निर्मित की जाने वाली दवाइयों की बिक्री राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है. विंध्य हर्बल राष्ट्रीय स्तर पर शुद्धता की पहचान बन चुका है. संस्था के प्रमुख, अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री अभय पाटिल का कहना है कि स्वच्छता और शुद्धता के मामले में यह संस्था किसी भी तरह का समझौता नहीं करती है. विंध्य हर्बल राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसायिक दायरे को क्रमश: बढ़ाती जा रही है. यहां तक कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में आज विंध्य हर्बल की दवाईयों को सर्वश्रेख़मानकर उनका उपयोग किया जाता है. इस संस्थान से जुड़े श्री निगम के अनुसार संस्था को यहां तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के वनवासी एवं ग्रामीणों के अलावा स्थानीय स्तर पर कार्यरत् आयुर्वेदिक औषधियों के जानकारों ने इसमें अहम भूमिका निभायी है. हमारा नाम ही शुद्धता की गारंटी है, इस भावना के साथ इस संस्था में पेटेन्ट आयुर्वेदिक दवाईयों का निर्माण किया जाता है. श्री अभय पाटिल ने यह भी जानकारी दी कि इस संस्था को आईएसओ 9001–2000 का प्रमाण पत्र भी प्राप्त है. संस्था में शोध संबंधी कार्यों को विशेष रूप से संग्रहित करके विभिन्न कार्यशालाओं में उनके उपयोग पर चर्चा भी आयोजित की जाती है. इस संस्थान द्वारा निर्मित शहद, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. इस संस्था के पास प्रायोगिक तौर पर परीक्षण के लिए और दवा निर्माण में उपयोगी जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए खुद की नर्सरी भी है. लघु वनोपज संघ के वनांचलों में गठित 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां और 60 ज़िला सहकारी वनोपज यूनियनों की एक शीर्ष संस्था होने के कारण इस संस्था को कच्चे माल की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी नहीं आती.

राज्य प्रशासन द्वारा निर्मित इस संस्था ने यह साबित कर दिया है अगर प्रशासनिक कामों को ईमानदारी और सच्चाई से अंजाम देने की कोशिश की जाए तो विंध्य हर्बल जैसी संस्थाओं की संरचना करना असंभव नहीं है. यह संस्था वर्तमान में लाभ में चल रही है. इसका पूरा श्रेय संस्था में काम करने वाले समर्पित सहयोगियों और अधिकारियों को ही जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा रोज़गार नहीं, धोखा है

गोपाल भार्गव

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को लेकर सरकार भले ही बड़े–बड़े दावे करती हो, लेकिन हक़ीक़त यही है कि राज्य में कहीं भी ग्रामीण श्रमिकों को औसतन 60 दिन का काम भी नहीं मिल रहा है. जबकि क़ानूनी तौर पर श्रमिकों को कम से कम 100 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए. इसके अलावा मध्यप्रदेश में मज़दूरों को ज़्यादातर भुगतान नगद में ही किया जाता है, उन्हें बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते के ज़रिए भुगतान करने की किसी को नहीं सूझती. रोज़गार गारंटी योजना की विभागीय समीक्षा के दौरान इसके क्रियान्वयन और प्रगति पर खुलकर विचार किया गया. मिली जानकारी के अनुसार समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाक़ों में ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और गांवों में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है. इस तरह रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम की उम्मीद रखने वालों को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है. ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि राज्य में कुल एक करोड़ 12 लाख ग्रामीण श्रमिकों के ही जॉबकार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से पिछले साल केवल 52 लाख श्रमिकों को ही काम दिया गया. कुल मिलाकर श्रमिकों को औसतन 57 दिन ही काम मिला. वर्ष 2008–09 में रोज़गार गारंटी योजना के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्र से 4068 करोड़ रूपए मिले थे और राज्य सरकार ने अपनी ओर से 528 करोड़ रूपए भी इस योजना में लगाए. पर इस पूरी राशि में से सिर्फ 3552 करोड़ रूपए ही ख़र्च किए गए. 50 प्रतिशत से ज़्यादा की राशि, निर्माण सामग्री ख़रीदने और दूसरे सरकारी ख़र्चों में ही लगा दी गई. पूरे साल कुल दो लाख 12 हज़ार काम पूरे हुए और तीन लाख से ज्यादा काम अधूरे रह गए. सरकार को ज़िलों से जो हिसाब मिला है उसके अनुसार 2196 करोड़ रूपए मज़दूरी के रूप में बांटे गए, जिसमें से 835 करोड़ रूपए राष्ट्रीयकृत बैंकों या पोस्ट ऑफिस में श्रमिकों के अकांउट खाते खुलवाकर, उनके नाम जमा किए गए. इस समीक्षा बैठक में उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने असंतोष और गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में सुधार की ज़रूरत है और इस योजना पर पूरे समय निग़रानी रखे जाने की भी ज़रूरत है.

आमतौर पर राज्य के लगभग सभी ज़िलों से ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार, घपलों, घोटालों और घटिया स्तर के निर्माण कार्यो की शिकायत आती रहती है. इन शिकायतों पर नज़र रखने के लिए मंत्री जी ने सांसदों, विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सहयोग लेने की ज़रूरत पर भी बल दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com